चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

बीजेपी के अस्तित्व पर संकट

पेज 3

दूर हो रहे भगवान

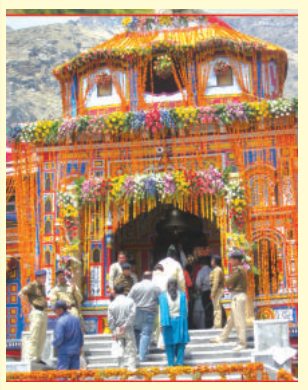

पेज 6

तबादले के लिए क़ैदियों को पीटो...

पेज 7

पाकिस्तान में फौज़ के आने की आहट

पेज 9

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 12 जुलाई–18 जुलाई 2010

मायावती के पीछे राहुल गांधी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में माया फैक्टर छाया है. बसपा की संगठनात्मक सक्रियता को अन्य दलों के नेता विधानसभा के जल्दी चुनाव का संकेत तो मानते हैं, पर अपनी पार्टी का पानी हिलाना नहीं चाहते. राजनीतिक दल ठहरे हुए पानी का तालाब बन रहे हैं. राहुल गांधी के बूते कांग्रेस सक्रिय है. बसपा में इसको लेकर बेचैनी भी है. राहुल 1989 के पहले के राजनीतिक–काल की वापसी चाहते हैं. जाटव छोड़ कर अन्य दलित जातियों के छोटे छत्रपों की कारगर भूमिका आंकते हुए जो भी दल इनका साथ लेगा, सत्ता उसी के हाथ होगी. ऐसा समझते हुए राहुल अन्य दलित जातियों को साथ लेकर माया के सोशल इंजीनियरिंग की काट में जुटे हुए हैं...

प्रभात रंजन दीन

देश में सियासत की धुरी तय करने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2012 में होने वाले हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के बड़े नेता यह मानने लगे हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव पहले भी हो सकते हैं. कैसे? वे इसका कोई बहुत तार्किक और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते, लेकिन मुलायम सिंह यादव सरीखे वरिष्ठ नेता भी कहते हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव पहले हो सकते हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरह अपनी पार्टी को चाक–चौबंद करने में लग गई हैं और संगठनात्मक शक्ति–संतुलन का काम जिस तेज़ गति से हो रहा है, उससे भी कुछ ऐसा संकेत मिलता है. प्रदेश के कई आला नौकरशाह कहते हैं कि चुनाव के पहले जिस तरह सत्ता प्रशासनिक फ़ैसले, तैनातियां और नियुक्तियां करती है, वैसा ही आजकल उत्तर प्रदेश में हो रहा है. बसपा की तेज़ी देखते हुए कांग्रेस भी ज़मीनी स्तर पर अपना आधार मज़बूत करने में जुट गई है. कांग्रेस की सक्रियता इससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की सहमति से दिग्विजय सिंह और परवेज हाशमी ने सीधे कमान संभाल ली है. पार्टी की रणनीति में प्रदेश कांग्रेस को बहुत हद तक शामिल नहीं किया जा रहा है. एक अलग युवा जुझारू दस्ता कांग्रेस के लिए ठोस पृष्ठभूमि तैयार करने में लगा हुआ है. यह समय से पहले चुनाव कराने की ही तैयारी है, जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों की निगाह है.

मायावती की संगठनात्मक सक्रियता उत्तर प्रदेश के उन राजनीतिक पार्टियों के लिए नज़ीर है, जो सांगठनिक परिवर्तन की बात तो छोड़ दें, आंशिक फेरबदल से भी घबराती हैं. सपा या भाजपा कोई भी. यहां तक कि कांग्रेस भी प्रदेश संगठन को छुए और छेड़े बग़ैर केंद्रीय नेताओं के बूते रिज़ल्ट चाहती है. अकेले राहुल के भरोसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मायावती के पीछे पड़ी है. राहुल की सक्रियता के कारण बसपा की व्यग्रता ज़रूर बढ़ी है. दलितों, मुस्लिमों और ब्राह्मणों को अपने साथ समेटने की राहुल (कांग्रेस) की तीव्रता मायावती की व्यग्रता की वजह हो सकती है. कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 1989 के पहले का राजनीतिक–काल वापस लाना चाहती है, जब कांग्रेस का निर्बाध राज हुआ करता था. अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो फिर देर हो जाएगी. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में शिद्दत से लगे राहुल गांधी को भी यह समझ में आने लगा है कि दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मणों के कांग्रेस के साथ के पुराने रिश्तों को दोबारा बहाल किए बग़ैर काम नहीं बनने वाला. ख़ास तौर पर दलितों और मुसलमानों को. हाल के उपचुनावों में कांग्रेस जीती भले ही नहीं, लेकिन दलितों और मुस्लिमों का वोट प्रतिशत कांग्रेस की ओर बढ़ा है. जो उत्तर प्रदेश का सामाजिक–राजनीतिक तापमान महसूस करते हैं, वह ये जानते हैं कि प्रदेश के तक़रीबन 66 जातियों वाला दलित समुदाय विभिन्न छोटे छत्रपों के नीचे है. ये उनकी भावनाओं से जुड़े हैं. इन छत्रपों के अपने छोटे राजनीतिक दल भी हैं, जो वोट भी काटते हैं और ख़ुद भले ही नहीं जीतें, पर बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को हरा ज़रूर देते हैं. लिहाज़ा, राजनीतिक अनिवार्यताओं के तहत अब कोई भी बड़ी पार्टी प्रदेश के इन छोटे छत्रपों को अपने साथ मिलाए बग़ैर नहीं चल सकती. बड़े राजनीतिक दलों को इसकी खीझ भी है, पर इसकी कोई कारगर काट भी नहीं है उनके पास.

अभी हाल ही में डुमरियागंज विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ, उसका हाल तो देखा ही आपने. सारे राजनीतिक समीकरण उलट–पुलट कर रख दिए. चुनाव परिणाम आने के बाद जब वोटों का हिसाब–किताब सामने आया तो यह ज़ाहिर हुआ कि बड़े राजनीतिक दल कुछ और समीकरण बनाए बैठे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ज़मीनी स्तर पर कुछ और ही घटित हो रहा था. छोटे दल इतनी सेंधमारी कर ले जाएंगे, इसका अंदाज़ा किसी भी बड़े दल के नेता को नहीं था. डुमरियागंज में सत्ताधारी बसपा के जीतने पर लोगों और नेताओं को आश्चर्य भले ही नहीं हुआ, लेकिन चुनाव परिणाम की समीक्षा के क्रम ने नेताओं को हैरत में ज़रूर डाला. महज़ स्थानीय स्तर के राजनीतिक दल पीस पार्टी ऑफ इंडिया (पीपीआई) ने सारे बड़े राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए. समाजवादी पार्टी ने तो अपनी खीझ उजागर भी कर दी और कहा कि इसके लिए छोटी पार्टियां ज़िम्मेदार हैं. पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि पीस पार्टी ने सपा का काम अधिक बिगाड़ा. पीपीआई को सपा उम्मीदवार से अधिक वोट प्राप्त हुए थे. याद रहे कि पीपीआई को सपा से निष्कासित अमर सिंह का समर्थन प्राप्त था. डुमरियागंज विधानसभा उपचुनाव एक टेस्ट केस की तरह है, जिसके परिणाम की बौखलाहट में सपा नेता व सांसद मोहन सिंह ने कह डाला कि स्थानीय पार्टियां प्रदेश की राजनीति का नुक़सान कर रही हैं. मोहन सिंह क्षेत्रीय दलों के हिमायती माने जाते रहे हैं. पीस पार्टी से भी नीचे चौथा स्थान पाने के कारण सपा की खीझ की वजह समझी जा सकती है. कांग्रेस यहां पांचवें स्थान पर रही, लेकिन उसके मुस्लिम वोटों का प्रतिशत बढ़ा. कांग्रेस के पास लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव का भी उदाहरण है. भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के सांसद बनने से खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ज्ञान किशोर शुक्ला को जीत हासिल हुई. ख़ूबी यह है कि शिया मुस्लिम बहुल इस इलाक़े में सपा के प्रत्याशी भुक्कल नवाब चुनाव हार गए, जहां अकेले डेढ़ लाख मुस्लिम मतदाता हैं. कांग्रेस के पास यह मानने का आधार है कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ़ आ रहे हैं. आंकड़े भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों का मुस्लिम वोट प्रतिशत घटा है, जबकि कांग्रेस का बढ़ा है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बहरहाल, 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी उप चुनाव हुए, उसमें छोटे क्षेत्रीय छत्रपों की प्रभावकारी भूमिका सामने आई. 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इनका असर दिखा. बड़ी पार्टियों के नेता इन छोटे छत्रपों वाले दलों को भले ही नकारात्मक भूमिका अदा करने वाले या वोट–कटवा जैसी संज्ञाएं दें, लेकिन यह साफ है कि इनको साथ लेकर चलना मौजूदा दौर की राजनीति की मांग है. इसमें जो भी दल आगे निकलेगा, उसका पलड़ा भारी रहेगा.

दूसरी पार्टियों को खीझता छोड़ कर कांग्रेस इस दिशा में अग्रसर है. कांग्रेस के कुछ बुज़ुर्ग नेता राहुल का क़द छोटा करने के लिए भले ही उल्टी चाल चल रहे हों, पर 1989 के पूर्वार्ध की राजनीतिक परिस्थितियां वापस लाकर कांग्रेस को फिर से जीवित करने की कोशिशों में राहुल पूरे मन से लगे हैं. फ्लैशबैक में जाएं तो पाएंगे कि दलितों का एकमुश्त वोट पहले कांग्रेस की झोली में जाता था. ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोट कांग्रेस के साथ था. कांग्रेस उस वोट बैंक को फिर से अपने पास लाना चाहती है. 23 साल बाद वह फिर से सत्ता में वापस आने की जद्दोजहद में है. 2007 में ब्राह्मण बसपा के पाले में चले गए पर ब्राह्मण के नाम पर कुछ व्यक्ति विशेष ने फ़ायदा उठाया. यह देख कर वृहत्तर ब्राह्मण समुदाय फिर से कांग्रेस की ओर लौटना चाहता है. कांग्रेस के प्रदेश संगठन में ब्राह्मणों का वर्चस्व बना कर रखा गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और यूथ कांग्रेस प्रेसीडेंट ब्राह्मण हैं, लेकिन राहुल की कोशिश दलित–ब्राह्मण–मुस्लिम कॉम्बिनेशन क़ायम करने की है. राहुल को दलितों के उस प्रभावी नेता की तलाश है जो जाटव समुदाय का न हो. इसके लिए पासी समुदाय के नेता को कांग्रेस समानान्तर तौर पर खड़ा करना चाहती है. दलितों में जाटव के बाद प्रदेश में पासी समुदाय का ही सबसे अधिक राजनीतिक प्रभाव है. उत्तर प्रदेश में दलितों की 66 विभिन्न जातियां हैं. 2001 की जनगणना के मुताबिक दलितों में जाटव आबादी 56 प्रतिशत है. जबकि पासी 20 प्रतिशत, धोबी–कोरी–वाल्मीकी 15 प्रतिशत और गोंड, धानुक व खटिक आबादी 5 प्रतिशत है. शेष 4 प्रतिशत में मुसहर, कठेरिया व अन्य दलित जातियों के लोग आते हैं.

मायावती ख़ुद जाटव जाति की हैं और इस जाति पर उनकी पकड़ बरक़रार है. लेकिन पासी जाति के लोग बसपा से बिल्कुल अलग हो रहे हैं. प्रदेश की क़रीब डेढ़ सौ विधानसभा सीटों पर पासी समुदाय के लोगों की आबादी पांच हज़ार से 75 हज़ार और 82 विधानसभा सीटों पर 30 से 75 हज़ार है. लिहाज़ा अवध क्षेत्र के 82 विधानसभा क्षेत्रों में पासियों की निर्णायक भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. जाटवों को छोड़ कर पासी समेत दलित समुदाय की अन्य जातियां राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध पारख महासंघ के साथ गोलबंद हो रही हैं. दलितों के बृहत्तर समुदाय को यह महसूस हो रहा है कि जाटव जाति के सामने उनकी स्थिति दोयम दर्जे की है. मायावती के उत्तराधिकारी की घोषणा ने भी यह संदेश प्रसारित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. दरअसल जाटव जाति के व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाने की मायावती की घोषणा के बाद ही

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मंत्रालयों में नियुक्ति के मामले में प्रधानमंत्री की सहमति मिलने के बाद मंत्री स्तर पर अपॉएंटमेंट कमेटी के गठन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सुधार के लिए बिल

सेवानिवृत्ति के बाद नियामक संस्थाओं के साथ जुड़ने के सपने संजो रहे नौकरशाहों के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया का बयान चिंता का कारण बन सकता है. नियामक संस्थाओं में सुधार के लिए प्रस्तावित बिल पर चर्चा करते हुए अहलूवालिया ने कहा था कि सचिव स्तर से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी उन नियामक संस्थाओं से न जुड़ें तो अच्छा है, जिनसे सेवाकाल में उनका वास्ता रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों से लाइसेंस लिया जाना चाहिए और उसे नियामक संस्थाओं को दिया जाना चाहिए. मंत्रालयों में नियुक्ति के मामले में प्रधानमंत्री की सहमति मिलने के बाद मंत्री स्तर पर अपॉएंटमेंट कमेटी के गठन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए. अहलूवालिया ने कहा कि ये फ़ैसले कैबिनेट स्तर पर लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है. उन्होंने नियामक संस्थाओं को संसद के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी बनाने की वकालत भी की. संसद की प्रक्रिया को ज़्यादा खुला बनाने के लिए उन्होंने स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकों को सार्वजनिक करने की अपील की. अहलूवालिया के बयान ने कुछ अधिकारियों और नेताओं के कान भले खड़े कर दिए हों, लेकिन अभी भी गेंद उनके ही पाले में है. कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन धनेंद्र कुमार ने पहले ही कह दिया है कि नियामक संस्थाओं सहित बिल की जद में आने वाले हर पक्ष से विचार मांगा जाना चाहिए. ऐसे एक बिल की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन यह कितना प्रभावकारी होगा, यह इसी पर निर्भर होगा कि इस पर क्या फ़ैसला लिया जाता है.

सर्वे से हलचल

कॉरपोरेट जगत का मायाजाल नौकरशाहों को पहले भी आकर्षित करता रहा है. यह भी मानी हुई बात है कि करियर के लिहाज़ से सिविल सेवा अब पहली पसंद नहीं है. सिविल सेवा के प्रति आकर्षण किस कदर कम हो रहा है, इसका एक और सबूत सरकार द्वारा कराए गए एक ताज़ा सर्वे में मिला. सिविल सेवकों के बीच कराए गए इस पहले सर्वे में यह बताया है कि देश में शीर्ष पदों पर क़ाबिज़ हर तीन में से एक नौकरशाह ने अपने करियर में कभी न कभी नौकरी छोड़ने के विकल्प के बारे में सोचा है. और जो वास्तव में छोड़कर चले गए, उनमें से अधिकतर कॉरपोरेट जगत की ही शोभा बढ़ा रहे हैं. आमतौर पर राजनीतिक दबाव को नौकरशाहों की विरक्ति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन रोचक बात यह है कि ख़ुद नौकरशाहों की नज़र में ऐसा नहीं है. उनके लिए प्रमोशन, ट्रांसफर, पराफॉर्मेंस एप्रेजल और डेपुटेशन की संभावना जैसी बातें भी उनके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना राजनीतिक हस्तक्षेप. कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर को पेश की गई इस सर्वे की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है कि वे सुधार के लिए ज़रूरी उपाय कर सकें. इस सर्वे को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका पता इसी से चलता है कि उसने अब इसे हर साल कराने का फ़ैसला किया है. लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि सर्वे में नौकरशाही में सुधार पर भी जोर दिया गया है.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

प्रबोध बनेंगे संयुक्त सचिव

हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना को जल्द ही आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव पद पर तैनात किया जाएगा. प्रबोध 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. प्रबोध कुमार संजय कृष्णा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल नवंबर 2009 में ही ख़त्म हो चुका है.

लाथर संस्कृति मंत्रालय में

कंवर समीर लाथर संस्कृति मंत्रालय में निदेशक बनाए जाएंगे. 1997 बैच के आईडीएएस अधिकारी लाथर संजय कुमार की जगह लेंगे.

सीबी सिंह बन सकते हैं निदेशक

1986 बैच के आईईएस अधिकारी चंद्र भान सिंह बहुत जल्द पेट्रोलियम मंत्रालय में निदेशक बनाए जा सकते है. सिंह संजय गुप्ता की जगह लेंगे, जिनकी केंद्रीय तैनाती अप्रैल 2010 में ख़त्म हो गई है.

माला आईडीबीआई प्रमुख

आख़िरकार यह तय हो ही गया कि राजेंद्र मोहन माला आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे. माला, योगेश अग्रवाल की जगह लेंगे. माला इससे पहले सिडबी के सीएमडी हुआ करते थे. 1975 में माला ने सिंडिकेट बैंक में प्रोबेशनरी अफसर के पद से करियर की शुरुआत की थी. माला आईडीबीआई बैंक में पहले भी काम कर चुके हैं. उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी.

प्रभाकरण केवीएस में संयुक्त आयुक्त

ओएम प्रभाकरण केंद्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त आयुक्त बनाए जा सकते हैं. प्रभाकरण, 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव की जगह लेंगे. ऋचा का कार्यकाल अप्रैल 2010 में ख़त्म हो चुका है. प्रभाकरण 1986 बैच के आईएसएस अधिकारी हैं.

मायावती के पीछे राहुल गांधी

पृष्ठ 1 का शेष

कांग्रेस ने इतर समुदाय के दलितों को अपने साथ लेने की कोशिशें तेज़ कर दी थीं. इसके लिए कांग्रेस ने अंदरूनी सर्वे भी कराया और छोटे जातीय छत्रपों से संपर्क क़ायम करने का भी अभियान चलाया. 1989 के बाद ग़ैर जाटव दलित समुदाय पहले तो बसपा–सपा–भाजपा में बंटा, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ़ इसका रुझान फिर से बढ़ रहा है. यह समझते हुए कांग्रेस भी ग़ैर जाटव दलित जातियों को रिझाने में लगी है. राहुल गांधी की जो यात्राएं दलितों के घर हुईं, उनमें पासी समुदाय के लोग अधिक थे. कांग्रेस को 2007 के विधानसभा चुनाव में महज़ दो फ़ीसदी जाटव वोट मिले थे, जो 2009 के लोकसभा चुनाव में बढ़ कर 4 प्रतिशत हुए. लेकिन इधर दलित वोट प्रतिशत पांच फ़ीसदी से बढ़ कर 16 फ़ीसदी पर पहुंच गया. रायबरेली में सोनिया गांधी का पासी सम्राट के माही किले पर जाना और किले को पुरातत्व और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने का वायदा करना, राहुल गांधी का अमेठी के सिमरा गांव में शिवकुमारी कोरी के घर जाना या श्रावस्ती में छेदी पासी के घर जाकर रुकना या प्रतापगढ़ के एक मंदिर में हुई भगदड़ मामले में राधेश्याम पासी को अपना मोबाइल फोन देना या उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रमोद तिवारी का प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान देवकी पासी के घर रुकना जैसे कई वाकये ग़ैर जाटव दलितों को कांग्रेस की तरफ़ समेटने और बसपा के सामने एक समानान्तर सोशल इंजीनियरिंग खड़ी करने की कोशिश ही है. कांग्रेस नेतृत्व की ओर से मिली सहानुभूति के कारण पासी बहुल इलाके से पीएल पुनिया को लोकसभा चुनाव में विजय मिली. कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों का मानना था कि पुनिया को प्रदेश संगठन में आगे लाकर पार्टी दलितों का समर्थन पाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व जाटव बनाम जाटव के बजाय

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

किसी अन्य दलित जाति के नेता को सामने लाकर ग़ैर जाटव दलित समुदाय का व्यापक गोलबंद समीकरण खड़ा करना चाहती है. इसके लिए आवश्यक है कि पासी समेत अन्य दलित जातियों के महत्वपूर्ण नेताओं को कांग्रेस के खेमे या समर्थन के दायरे में लाया जाए, कांग्रेस इस प्रयास में लगी है. दरअसल, वर्ष 2007 में मायावती ने जिस सोशल इंजीनियरिंग का पासा फेंका और विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की, वही राहुल गांधी 2012 में कांग्रेस की ओर से आजमाना चाहते हैं. कांग्रेस जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने वाले तीन–तीन नेताओं का पैनल तैयार करा रही है. चुनाव में इस पैनल के आधार पर ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी.

प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां भी कांग्रेस का साथ दे रही हैं. भाजपा की राजनीति हाशिए पर है और भाजपा इससे जल्दी उबरती नहीं दिखती. लिहाजा मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की सपाई राजनीति फ़िलहाल अप्रासंगिक है. मुस्लिम वोटरों के पास अब सपा, कांग्रेस और बसपा तीन विकल्प हैं. बसपा हालांकि ब्राह्मण–दलित गठजोड़ को ब्राह्मण–दलित–मुस्लिम गठजोड़ में बदलना चाहती है, लेकिन मायावती के भाजपा के साथ के पुराने सम्बन्धों की राजनीतिक पृष्ठभूमि मुसलमानों को बसपा से जुड़ने से रोक रही है. दलितों को अपने साथ लाने में कांग्रेस को फिलहाल जो भी मुश्किलें पेश आ रही हों, लेकिन वास्तविकता यही है कि दलितों में एक जाति को छोड़ कर अन्य जातियां राजनीतिक विकल्प तलाश रही हैं. राहुल की दलित राजनीति पर मायावती की तल्खी भी यह संकेत देती है कि राहुल की सेंध से बसपा में बेचैनी है. कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का भी मानना है कि जिस तरह ब्राह्मणों का एक तबका कान्यकुब्ज सतीश चंद्र मिश्र की वजह से बसपा से जुड़ा, उसी तरह दलितों का जाटव तबका मायावती के कारण बसपा से जुड़ गया. लिहाज़ा अन्य समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने का राजनीतिक मौक़ा कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती. डॉ. अय्यूब के नेतृत्व वाली पीस पार्टी ऑफ इंडिया, कौशल किशोर के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पारख महासंघ, सोनेलाल पटेल की विधवा कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल, ओमप्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली भारत समाज पार्टी जैसे छोटे जातीय छत्रपों की बड़ी भूमिका आने वाले विधानसभा चुनाव में तय हो सकती है. लेकिन इन छोटे जातीय छत्रपों के नेताओं की राजनीतिक पहचान दर्ज कराने की लोकतांत्रिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस के सामने मुश्किलें ला रही है. कांग्रेस छोटे छत्रपों का अपने साथ विलय चाहती है, जबकि ये छोटे दल अपनी शिनाख्त बचाए रखते हुए कांग्रेस के साथ सम्मानजनक गठबंधन चाहते हैं.

prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला सामाहिक अखबार
वर्ष 2 अंक 18
दिल्ली, 12 जुलाई –18 जुलाई 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9899815169
प्रसार + 91 9868013165
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भाजपा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके पास न तो कोई नई सोच है और न ही वह ख़ुद को अलग दिखाने की कोशिश में है.

बीजेपी के अस्तित्व पर संकट

ग़रीब तो ग़रीब इस बार अमीर भी महंगाई की मार झेल रहे हैं. खाने पीने के सामान इतने महंगे हैं कि ग़रीबों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं. जो साग-सब्जी, दूध दही और घी मिल भी रहे हैं वे ज़हर हैं. देश में मिलावट का ऐसा खेल चल रहा है जिससे इंसानियत शर्मसार हो चुकी है. शहरों में भी पीने का साफ पानी नहीं हैं. गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बुरा है. लोगों को ट्रेन में सफर करने में डर लगता है, पता नहीं कब कहां माओवादी हमला बोल दें. बेरोज़गारी इतनी है कि लगभग हर शहर और गांव में बेरोज़गारों की फौज़ तैयार हो रही है और समाज क्राइम की आग में जल रहा है. लुटेरे अपने कारनामों को दिनदहाड़े अंजाम दे रहे हैं. ऐसा लगता है मानो किसी राक्षस की तरह दुनिया भर की समस्याएं एक साथ एक समय पूरे देश पर छा गई हैं. ज़िंदगी मानों सांस लेने तक ही सिमटती जा रही है. सरकार ने जनता को निचोड़ने के लिए बाज़ारवाद को छुट्टा छोड़ दिया है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री भी इन समस्याओं से निपटने के बजाए हाथ खड़े कर चुके हैं. अब जनता किसके पास जाए. किससे मदद मांगे. जनता का हमदर्द कौन बने.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

मुसीबतें हर आम इंसान और समाज पर आती हैं. हम लड़ते भी हैं. इस लड़ाई में अगर कोई हमदर्द न मिले तो लोग असहाय और बेसहारा महसूस करने लगते हैं. ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है. इससे भी ख़तरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब कोई ख़ुदगर्ज हमदर्द बनने का नाटक करता है. जब मदद के नाम पर धोखा देता है और जब मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगता है. भारत के लोग इसी मन:स्थिति से गुज़र रहे हैं. देश की स्थिति यह है कि बाज़ार ने लोगों के जीवन को नरक बना दिया है. अमीर हो या ग़रीब, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है. देश के 260 ज़िलों में सरकार विफल हो चुकी है. आज यहां माओवादियों का वर्चस्व है. सिपाही और अर्धसैनिक बलों की लाशों को देखकर जनता सिहर जाती है. घरों में बेरोज़गारों की तादाद बढ़ रही है क्योंकि नौकरी नहीं है. यह सब सरकार की संवेदनहीनता का नतीजा है. फ़िलहाल पेट्रोल और डीज़ल को बाज़ार के हवाले किया गया है. अगर सरकार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बाज़ार पूरी तरह देश को अपने क़ब्ज़े में ले लेगा. लेकिन इस त्रासदी का उपाय किसके पास है. जनता की तरफ़ से लड़ाई कौन लड़े. अफसोस की बात यह है कि जिन पर सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़िम्मेदारी है, वो अपनी प्रासंगिकता और उपयोगिता खो चुके हैं.

यह देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीय विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल हो गई है. इसे अपने कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है. महंगाई हो या बेरोज़गारी या फिर जनता से जुड़ी अन्य समस्याएं, भाजपा ने सिर्फ़ खानापूर्ति के लिए धरना प्रदर्शन और संसद के अंदर हंगामा किया. वो भी सिर्फ़ मीडिया में दिखने और दिखाने के लिए. प्रजातंत्र में विपक्ष का यह दायित्व है कि वह सरकार के कामकाज पर नज़र रखे, उस पर अंकुश लगाए, जनता का पक्षधर बनकर सरकार की नीतियों और योजनाओं पर सवाल उठाए, ग़रीबों-ग्रामीणों एवं शोषित वर्गों के लिए संघर्ष करे और उनकी अगुवाई करे और उनके साथ मिल कर उनकी मांगों के समर्थन में आंदोलन करे. अगर विपक्ष यह काम करता है तभी उसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता होती है. अगर वह ऐसा नहीं करता तो ऐसे विपक्ष का क्या फ़ायदा. फिर सरकार का निरंकुश बनना तो स्वाभाविक है. लोकतंत्र में जनता किसी पार्टी को इसलिए विपक्ष में बैठाती है, ताकि वह उसके दुख-तकलीफों को समझे और सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे. प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी प्रासंगिकता और उपयोगिता साबित करनी होती है. उन्हें सिर्फ़ संघर्ष ही नहीं करना होता है, बल्कि यह भी साबित करना होता है कि वह वर्तमान सरकार से ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, ताकि जनता उस पर भरोसा कर सके और उसे अगले चुनाव के बाद सरकार चलाने का मौक़ा दे. यही वजह है कि लोकतंत्र में विपक्ष की ज़िम्मेदारियां सत्तापक्ष से कहीं ज़्यादा होती हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है. डीज़ल के दाम बढ़ गए लेकिन भाजपा के अंदर इस बात पर बहस हो रही है कि जसवंत सिंह और उमा भारती को पार्टी में वापस बुलाया जाए या नहीं. महंगाई के मुद्दे पर लालकृष्ण आडवाणी प्रेस कांफ्रेस नहीं करते लेकिन जसवंत सिंह को पार्टी में वापस लाने के लिए वह प्रेस के सामने आते हैं. जनता की मुसीबतों को कैसे दूर किया जाए या फिर सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ क्या रणनीति हो, यह भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है लेकिन उमा की पार्टी में वापसी के मसले पर बैठकों का दौर चल रहा होता है. झारखंड में जूते और प्याज खाने के बाद भाजपा अब बिहार की रणनीति तैयार करने में जुट गई है. जनता की परेशानियों के बारे में क्या करना है, यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है. भारतीय जनता पार्टी और अध्यक्ष नितिन गडकरी को विपक्ष की ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं है.

अभूतपूर्व त्रासदी झेल रही जनता और देश पर गहराए संकट के बीच भाजपा में किसी टीवी सीरियल की तरह रूठने और मनाने का ड्रामा चल रहा है. उनके व्यवहार से तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार की नीतियों का साथ दे रही है. ऐसा मानने की वजह यह भी है कि भाजपा ने वर्तमान आर्थिक नीति के ख़िलाफ़ अपनी कोई योजना या नीति का रोडमैप जनता के सामने नहीं रखा है. जब महंगाई से लड़ने का भाजपा के पास कोई तरीक़ा ही नहीं है तो जनता की नज़रों में अपनी मौजूदगी का एहसास करने के लिए भाजपा ने फिर से जिन्ना के भूत को बाहर निकाला है. जसवंत सिंह को पार्टी में वापस लेने का बहाना बना कर सुर्ख़ियां बटोरीं. भारतीय जनता पार्टी की कहानी अजब है. पहले आडवाणी जी ने जिन्ना को सेकुलर बताया तो उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा. आरएसएस और पार्टी संगठन ने आडवाणी के बयान को पार्टी की विचारधारा के विपरीत बताया था. कई महीनों तक आडवाणी को अज्ञातवास लेना पड़ा था. आडवाणी फिर वापस आ गए. चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया. जिस बात पर आडवाणी ने सिर्फ़ एक बयान दिया था, उसी बात पर जसवंत सिंह ने पूरी किताब लिख दी. पार्टी ने उन्हें बेइज़्ज़त करके बाहर का रास्ता दिखा दिया. एक साल भी नहीं बीते जसवंत सिंह को फिर पार्टी में वापस ले लिया गया. जब इन लोगों को वापस ही लेना था तो निकालने का फ़ैसला क्यों लिया गया. समझने वाली बात यह है कि आज जो देश का माहौल है उसमें जनता को इस बात से क्या फ़र्क़ पड़ता है कि जिन्ना क्या थे और जसवंत सिंह भाजपा में रहें या न रहें. भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है. प्रजातंत्र में एक मज़बूत विपक्ष जनता का अधिकार है. संसद में भाजपा कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर है और सात बड़े-बड़े राज्यों में सरकार चला रही है. अब जब भाजपा ही इस ज़िम्मेदारी को नहीं समझ सकती है तो देश की जनता क्या करे. भाजपा की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर सरकार जनविरोधी नीतियां लागू कर रही है. जनता की त्रासदी के लिए ज़िम्मेदार जितनी सरकार की नीतियां हैं, उतनी ही भाजपा की गैरज़िम्मेदारियां भी.

भाजपा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके पास न तो कोई नई सोच है और न ही वह ख़ुद को अलग दिखाने की कोशिश में है. महंगाई के नाम पर भाजपा ने दिल्ली और दूसरे शहरों में विरोध प्रदर्शन तो किया लेकिन वह भी एक कार्यक्रम की तरह था. जैसे भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो. भारतीय जनता पार्टी के बयानों और विरोध प्रदर्शनों में जनता के प्रति संवेदना की कमी साफ-साफ दिखती है. जनता के साथ मिलकर जनता की आवाज़ उठाने की कला भाजपा भूल चुकी है.

दुनिया भर में कई दक्षिणपंथी पार्टियां हैं जो हमेशा नए-नए विचारों के साथ जनता को लुभाने और सरकार को घेरने में सफल होती हैं. भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि दुनिया बदल गई लेकिन इसकी विचारधारा, संगठन प्रणाली एवं कार्यप्रणाली वैसी ही है जैसी शुरुआत में थी. भाजपा में बदलाव नहीं है. हाल में चुनाव हार जाने के बाद पार्टी में विचारधारा और संगठन पर पुनर्विचार करने का वक़्त आया तो आश्चर्यजनक तरीक़े से पार्टी ने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया और पार्टी की विचारधारा को श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीन दयाल उपाध्याय के विचारों से जोड़कर थम गए. यह बात और है कि इन दोनों की विचारधारा क्या है, यह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ही पता नहीं है. बेचारी देश की जनता को तो यह भी मालूम नहीं है कि इन दोनों का भारतीय राजनीति और समाज में क्या योगदान है. समाजिक बदलाव, राजनीति, विदेश नीति और अर्थनीति पर उनके विचार क्या हैं. यह भारतीय जनता पार्टी की ही कमज़ोरी है. दोनों बड़े नेता हैं, विचारक भी हैं, लेकिन भाजपा ने उनके विचारों को प्रचारित करने के लिए कुछ भी नहीं किया. इससे तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पार्टी विचारधारा को ज़्यादा महत्व नहीं देती है. कार्यकर्ता का मनोबल समय के साथ-साथ घटता जा रहा है. समर्थक पार्टी से दूर जा रहे हैं फिर भी कार्यपद्धति में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं है. हिंदु धर्म ख़तरे में है, यूनिवर्सल सिविल कोड और राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे को जनता ने नकार दिया है. तो फिर भारतीय जनता पार्टी आज भी उन्हीं विचारों, मुद्दों और विवादों में क्यों उलझी हुई है. भाजपा को पाकिस्तान और बंग्लादेश में धर्म के आधार पर बनी पार्टियों से सीख लेने की ज़रूरत है. इन दोनों देशों में जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं लेकिन उन्हें जन समर्थन नहीं है. नितिन गडकरी को पार्टी की कमान संभाले छह महीने हो चुके हैं. अपनी टीम चुनने में उन्हें चार महीने लग गए. उनकी टीम के चुनाव में देरी हुई लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक पार्टी के महासचिवों, उपाध्यक्षों और सचिवों को निर्धारित ज़िम्मेदारियां नहीं मिली हैं. इसलिए पार्टी का काम रुका हुआ है. गडकरी कहते हैं कोई जल्दबाज़ी नहीं है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में चिंता है. उन्हें लगता है कि गडकरी डी-फोकस्ड हैं. उन्हें पता नहीं है कि पार्टी को किस दिशा में लेकर जाना है. वे राजनीतिक दल को किसी एनजीओ की तरह चलाना चाहते हैं जबकि अभी पार्टी को विचारधारा और नीति को लेकर साफ-साफ आदेश की ज़रूरत है. पार्टी कार्यालय में काम कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं व अधिकारियों को लगता है कि पार्टी स्थिर हो चुकी है. कुछ तो यह भी कहने लगे हैं कि अगर यही हाल रहा तो बिहार और उत्तर प्रदेश में पार्टी का हाल बद से बदतर हो जाएगा. गडकरी की समस्या यह है कि उनका ख़ुद का स्टेचर नेशनल लीडर का नहीं है. वह सबको एक साथ ख़ुश करना चाहते हैं, इसलिए ठोस निर्णय लेने में असमर्थ हैं. वह ज़्यादातर फ़ैसले वरिष्ठ नेताओं के आदेश पर लेते हैं और उसके बाद उस फ़ैसले से आहत हुए गुटों को ख़ुश करने में लग जाते हैं. जसवंत सिंह को वापस लेने का फ़ैसला गडकरी ने आडवाणी के दबाव में लिया. हैरानी की बात यह है कि नितिन गडकरी ने जसवंत सिंह को वापस लेने का फ़ैसला लेने के लिए पार्लियामेंटरी बोर्ड की मीटिंग भी नहीं बुलाई, जिसने जसवंत सिंह को निकालने का फ़ैसला लिया था. नरेंद्र मोदी जसवंत सिंह के निष्कासन के सूत्रधार थे. उन्हें ख़ुश करने के लिए राज्यसभा में राम जेठमलानी को लाया गया. मतलब यह है कि पार्टी किसी नीति पर नहीं अपितु नेताओं को ख़ुश करने के आधार पर चल रही है. वैसे किसी पुराने नेता को वापस पार्टी में जगह देना किसी भी पार्टी के लिए आम बात है. लेकिन जसवंत सिंह का वापस आना थोड़ा अलग है. जब जसवंत ने जिन्ना को सेकुलर बताया और नेहरू को विभाजन के लिए ज़िम्मेदार बताया तो भाजपा ने यह ऐलान किया था कि जिन्ना को सेकुलर कहना पार्टी की कोर-विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसे भाजपा की विचारधारा पर हमला कहा था. जसवंत सिंह अपने बयानों से नहीं पलटे हैं, न ही उन्होंने कोई माफ़ी मांगी, फिर भी उन्हें बीजपी ने पार्टी में वापस ले लिया. अब भारतीय जनता पार्टी की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह देश को यह बताए कि अब पार्टी की विचारधारा क्या है. क्या भाजपा जिन्ना को सेकुलर मानने लगी है. या फिर यह महज़ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग के अलावा कुछ नहीं है. एक इवेंट, बीजेपी का एक शो था. सच्चाई यह है कि बीजेपी के साथ फ़िलहाल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. शायद पार्टी को यह लगता हो कि इस तरह के कामों से जनता में यह मैसेज जाए कि पार्टी में कुछ हो रहा है. पार्टी मज़बूत हो रही है, लोग वापस आना चाह रहे हैं. लेकिन भाजपा की यह रणनीति भी कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि इसके तुरंत बाद उमा भारती की वापसी पर पार्टी की गुटबाज़ी सामने आ गई.

देश की जनता त्रस्त है. सरकार एक के बाद एक जनता को परेशानी में डालने वाली नीतियों पर अमल कर रही है. इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सरकार का कोई अल्टरनेटिव नज़र नहीं आ रहा है. भाजपा के नए अध्यक्ष से लोगों की उम्मीदें बढ़ी थीं, लेकिन वह भी असफल साबित हो रहे हैं. उन्हें आरएसएस ने पार्टी को सुधारने के लिए भाजपा का अध्यक्ष बनाया था लेकिन वह भी भाजपा के रंग में रंग गए. गुटबाज़ी पहले से कहीं ज़्यादा तीखी हो चुकी है. पुराने लोगों को वापस लाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि नए नेता पैदा करने में भाजपा विफल रही है. पार्टी के अंदर चल रहे गृहयुद्ध की वजह से भाजपा ने जनता के सवालों को पीछे छोड़ दिया है. न कोई नई रणनीति है न ही कोई वैचारिक व आर्थिक रोडमैप है. दुख के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा प्रासंगिकता और उपयोगिता को ही ख़त्म करने पर आमदा है.

manish@chauthiduniya.com

दिल्ली, 12 जुलाई–18 जुलाई 2010

चौथी दुनिया

आर वी देशपांडे, अध्यक्ष, केपीसीसी

कर्नाटक कांग्रेस की करतूत

खा गई बाढ़ राहत का पैसा

कर्नाटक कांग्रेस बाढ़ राहत के लिए वसूला गया धन खा गई. आम लोगों से लिया गया चंदा पार्टी का धंधा बन गया. कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हों या कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष आर वी देशपांडे, राहत के पैसे की अनियमितता उजागर होने से आहत जनता के समक्ष इसका हिसाब तो देना ही होगा...

शशि शेखर

प्राकृतिक आपदा के वक़्त अमूमन राजनीतिक और सामाजिक संगठन राहत के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं. आम लोग ऐसे मौक़े पर दिल खोल कर पैसा देते हैं ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके, लेकिन उसी पैसे से अगर कोई राष्ट्रीय दल अपने कार्यालय का ख़र्चा चलाने लगे तो इसे क्या कहेंगे. कर्नाटक कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही किया. अक्टूबर 2009 में आई बाढ़ के समय कर्नाटक कांग्रेस ने राहत के नाम पर क़रीब दो करोड़ 30 लाख रुपये जमा किए. ज़ाहिर है, इस पैसे का इस्तेमाल बाढ़ पीड़ितों के लिए किया जाना था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क़रीब एक करोड़ रुपये का सामान बाढ़ पीड़ितों के लिए ख़रीदा गया. और बाक़ी के बचे सवा करोड़ रुपये में से दिसंबर 2009 से मई 2010 के बीच पार्टी दफ्तर के ऊपर 40 लाख रुपये से ज़्यादा ख़र्च कर दिए गए. इसके अलावा, 75 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया गया ताकि ब्याज मिलता रहे और पार्टी दफ्तर का ख़र्च निकलता रहे. इसी पैसे से कांग्रेस नेताओं के लिए हवाई टिकट ख़रीदे गए. और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए टी-शर्ट. पार्टी के लिए बैनर-पोस्टर बनवाए गए और पार्टी दफ्तर के लिए टाइल्स भी इसी पैसे से ख़रीदे गए.

दिलचस्प पहलू यह है कि कर्नाटक कांग्रेस पर यह आरोप कहीं बाहर से नहीं लगाया जा रहा है. बाढ़ राहत के पैसों के इस लूट की जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी दी गई है. कर्नाटक के ही कांग्रेसी नेताओं ने इस पूरी लूट का काला चिट्ठा तैयार कर दिल्ली भेजा है. *चौथी दुनिया* के पास भी वो सारे काग़ज़ी सबूत हैं, जिसके आधार पर कर्नाटक कांग्रेस और उसके अध्यक्ष आर वी देशपांडे पर बाढ़ राहत के पैसों के हेरफेर का आरोप लगाया गया है. पूरे ख़र्च और बैंक स्टेटमेंट का ब्यौरा *चौथी दुनिया* के पास है. उपलब्ध दस्तावेज के मुताबिक़ पूरी कहानी यूं है. 2009 में आई बाढ़ ने कर्नाटक के 11 ज़िलों को बुरी तरह से प्रभावित किया था. इसमें बगलकोट, बीजापुर, बीदर, बेलगांव, धारवाड़ और बेल्लारी में बाढ़ का कहर कुछ ज़्यादा ही था. 200 से ज़्यादा मौतें हुई थीं. हज़ारों परिवार बेघर हो गए थे. सैकड़ों मवेशी उस बाढ़ में बह गए. फ़सल बर्बाद हुई, वह अलग. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया था. बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए राज्य के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू किया. इसी कड़ी में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने भी बाढ़ राहत के नाम पर पैसा जमा करना शुरू किया. पैसा जमा करने के बाद इसे बंगलुरू के केनरा बैंक की माधवनगर शाखा में जमा किया गया. एक अक्टूबर 2009 को यह अकाउंट खोला गया था. यह बैंक अकाउंट केपीसीसी फ्लड रीलिफ फंड के नाम से खोला गया था, जिसका अकाउंट नंबर 0788101056855 है. एक अक्टूबर 2009 से 17 अप्रैल 2010 के बीच इस अकाउंट में दो करोड़ 30 लाख रुपये जमा कराए गए.

TOTAL AMOUNT PAID TOWARDS PURCHASE OF FLOOD RELIEF MATERIALS LIKE BLANKETS, SHIRTS, TROUSERS, PANTS, RICE, PLASTIC MATERIALS ETC., TO SEND FLOOD AFFECTED DISTRICTS

Date	Ch Nos	Payments	Amount
6/10/09	207381	Shesh Woolens 1000 Blankets UK	84000
6/10/09	207383	Shesh Woolens 6600 Blankets Siruguppa	686400
26/10/09	207384	Munot Textiles 2500 Sarees Koppal	232500
20/10/09	207385	Sha Sagarmal Sukharaj & Co - 7000 Blankets Haveri	655200
29/10/09	207386	Metro - 20000 Blankets - Belgaum, Bijapur, Bagalkot, Davanagere	2100000
21/10/09	207387	Akhawat - 11732 Sarees, Gadga, Koppal	1201240
21/10/09	207388	Arihants - 5060 Sarees, Gadga, Koppal	404800
27/10/09	207389	Arihants - 1250 Sarees, Davanagere	100000
21/10/09	343461	Sri. Venkateshwara Textiles 10000 dothi Bijapur	600000
22/10/09	348462	M/s Arihants - 3250 Sarees for Davanagere	260000
21/10/09	348463	M/s Munot Textiles - 1250 Sarees for Dharwad	100000
21/10/09	348465	M/s S.J.N.Impex - 10000 Blankets for Bijapur	930000
21/10/09	348466	M/s Gian Textiles - 10300 Blankets for Bagalkot	930000
29/10/09	348469	M/s Surya Handlooms - 500 Bedsheets for UK Dharwad	60000
29/10/09	348468	M/s Sanghvi - 1000 Blankets wide Bill No 822,823,824	152500
30/10/09	348742	M/s Arihants - 6050 Sarees for Gulburga	484000
30/10/09	348741	M/s Akhawat Syndicate 10417 for Yadgir	1092830
30/10/09	348743	Himalaya Traders - 3000 Sarees to Gulburga	225000
30/10/09	348744	Venkateshwara Textiles - 5000 Dhothis to Gadag	400030
26/11/09	348470	M/s Kamala Textiles - 800 sarees Belgaum, UK	98400
26/02/10	348751	Deepti Textiles - 50 Sarees for U.K	6000
26/11/09	348753	Aditya Screen - 500 T Shirts supply Youth Congress	19240
23/12/09	357773	M/s Digital Palace Towards Printing 150 Copies relief flood report	70000
		Total	11052110

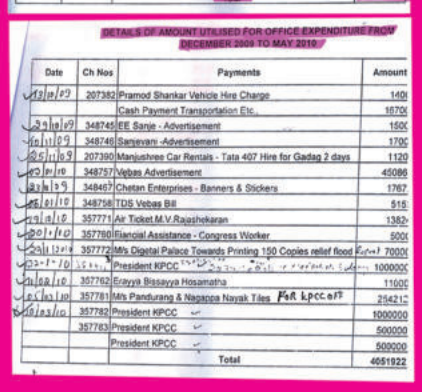

DETAILS OF AMOUNT UTILISED FOR OFFICE EXPENDITURE FROM DECEMBER 2009 TO MAY 2010

Date	Ch Nos	Payments	Amount
13/10/09	207382	Pramod Shankar Vehicle Hire Charge	1400
		Cash Payment Transportation Etc.	16700
29/10/09	348745	EE Sanje - Advertisement	1500
10/11/09	348746	Sanjevani -Advertisement	1700
25/11/09	207390	Manjushree Car Rentals - Tata 407 Hire for Gadag 2 days	1120
03/01/10	348757	Vebas Advertisement	45086
31/12/09	348467	Chetan Enterprises - Banners & Stickers	1767
05/01/10	348758	TDS Vebas Bill	515
19/01/10	357771	Air Ticket M.V.Rajashekaran	1382
20/01/10	357780	Fiancial Assistance - Congress Worker	5000
23/12/09	357772	M/s Digetal Palace Towards Printing 150 Copies relief flood	70000
23-1-10		President KPCC	1000000
11/02/10	357762	Erayya Bissayya Hosamatha	11000
05/03/10	357781	M/s Pandurang & Nagappa Nayak Tiles For KPCC off	254212
10/03/10	357782	President KPCC	1000000
	357783	President KPCC	500000
		President KPCC	500000
		Total	4051922

काग़ज़ी सबूत कहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक करोड़ 10 लाख रुपये का सामान, मसलन साड़ी, कंबल, चावल, प्लास्टिक, शर्ट, पैंट इत्यादि ख़रीदे गए. इसी बीच, दिसंबर 2009 से मई 2010 के बीच 40 लाख 51 हज़ार रुपये कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय और बैनर-पोस्टर बनवाने पर ख़र्च कर दिए गए. ग़ौरतलब है कि यह सारा ख़र्च प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आर वी देशपांडे की मर्जी से हो रहा था. प्रदेश कांग्रेस ने बाढ़ राहत के लिए जमा पैसे का इस्तेमाल वाहन किराया देने, ऐड एजेंसी से पोस्टर-बैनर और स्टीकर बनवाने, बुकलेट्स छपवाने के लिए किया. इतना ही नहीं, इसी पैसे से एक बड़े कांग्रेसी नेता एम वी राजशेखरन के लिए क़रीब 14 हज़ार रुपये का हवाई टिकट भी ख़रीदा गया. यूथ कांग्रेस के सदस्यों के लिए 19240 रुपये के टी-शर्ट भी इसी पैसे से ख़रीदे गए. इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि राहत के नाम पर जमा किए गए पैसों में से 75 लाख रुपये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिक्सड डिपॉजिट करा दिए ताकि ब्याज का पैसा मिलता रहे. और इसी से पार्टी दफ्तर का ख़र्च निकलता रहे. उपलब्ध सबूतों के मुताबिक़ राहत का अधिकतर पैसा केपीसीसी के आधिकारिक बैंक अकाउंट संख्या 0788101020789 में भी ट्रांसफर किया गया. फ़िलहाल, मई 2010 के अंतिम सप्ताह तक फ्लड रीलिफ फंड में 4 लाख रुपये बचे हुए हैं. बहरहाल, यह कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्मनाक बात ही कही जाएगी कि कर्नाटक में कांग्रेस को चलाने के लिए बाढ़ राहत के पैसे की ज़रूरत पड़ती है. अगर कांग्रेस पार्टी राज्य में अपनी साख बचाना चाहती है, तो उसे जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करवा कर दोषियों को उचित सज़ा देनी चाहिए. चाहे वह दोषी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष आर वी देशपांडे ही क्यों न हो.

shashishekhar@chauthiduniya.com

बिहार में वाम दल दिखाएंगे दम

भाकपा-माकपा वाम एकता के साथ चुनावी दंगल में उतरना चाहती है. इसके लिए भाकपा और माकपा के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है. भाकपा माले ने क़रीब 100 सीटों पर, भाकपा ने 54 सीटों पर और माकपा ने 25-35 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है.

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

पश्चिम बंगाल में कमज़ोर होती पकड़ के बावजूद बिहार में वाम दल पूरी तैयारी के साथ चुनावी अखाड़े में कूदने की तैयारी कर रहे हैं. बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से लगभग दो सौ सीटों पर भाग्य आजमाने के लिए पार्टी नेता रात-दिन पसीना बहा रहे हैं. बंगाल से सटे बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर वाम नेता यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है और घमासान जंग के बाद ही तय होगा कि लाल झंडे का भविष्य क्या होगा.

अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश की प्रमुख वामपंथी पार्टी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा), भाकपा माले और माकपा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. भाकपा-माकपा वाम एकता के साथ चुनावी दंगल में उतरना चाहती है. इसके लिए भाकपा और माकपा के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है. भाकपा माले ने क़रीब 100 सीटों पर, भाकपा ने 54 सीटों पर और माकपा ने 25-35 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है. क़रीब-क़रीब तीनों पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम पर मोटे तौर पर मोहर लगा दी है. इस बार के विधानसभा चुनाव में भाकपा के तीन में दो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह और रामविनोद पासवान चुनावी दंगल में नहीं उतरेंगे, ऐसा पार्टी सूत्रों का कहना है. वहीं भाकपा माले विधायक अमरनाथ यादव की सीट सुरक्षित हो जाने के कारण उनकी उम्मीदवारी पर भी संशय है.

पिछले दिनों भाकपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 54 पर क़िस्मत आजमाने का निर्णय लिया गया. इन सीटों के लिए उम्मीदवार तलाशने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. हालांकि प्रथम श्रेणी की 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों की तस्वीर भी क़रीब-क़रीब साफ हो गई है. सूत्रों के अनुसार कार्यकारिणी में गहन विचार विमर्श के बाद 54 सीटों को चिह्नित किया गया है. इनमें से 18 सीटों पर तैयारी शुरू कर देने का निर्देश संबंधित ज़िलों को दिया गया है.

सूत्रों के अनुसार पार्टी ने चयनित 54 विधानसभा सीटों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है. तीनों श्रेणियों में 18-18 सीटों को शामिल किया गया है. इसमें प्रथम श्रेणी की सीट है बेगूसराय ज़िले की तेघड़ा, बछबाडा, मटिहानी, बखरी, मधुबनी ज़िले की हरलाखी, खजौली, विस्फी, खगड़िया की बेलदौर, गया की गया शहर, बांका ज़िले की बांका, धुरैया, औरंगाबाद की गोह, पूर्वी चंपारण की मीनापुर, समस्तीपुर की समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण की केसरिया, सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर, नालंदा की इस्लामपुर और भागलपुर की कहलगांव है. इसके अलावा पीरपैंती, शंकरपुर, रफीगंज और गोपालपुर को भी प्रथम श्रेणी में शामिल करने की मांग सदस्यों ने उठाई है. प्रथम श्रेणी की चयनित 18 सीटों में से तीन पर वर्तमान में भाकपा का क़ब्ज़ा है. साथ ही अन्य सीटों पर पिछले चुनावों में पार्टी के उम्मीदवार दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे. माना जा रहा है कि हर हाल में पार्टी इन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. भाकपा ने अपने कोटे की सभी सीटों की सूची माकपा को उपलब्ध करा दी है. इन सीटों पर जल्द ही दोनों पार्टियों के नेताओं की अगली बैठक होगी. जिसमें सीटों के आदान-प्रदान पर चर्चा होगी.

सूत्रों के अनुसार तेघड़ा से रतन सिंह, बखरी से विधायक सूर्यकांत पासवान, बछबाड़ा से पूर्व विधायक अवधेश राय, मटिहानी से पूर्व विधायक राजेंद्र राजन, हरलाखी से विधायक रामनरेश पांडे, विस्फी से हेमचंद्र झा, खजौली से रामनारायण बनरैत और अमीरूद्दीन, बेलदौर से पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह, गया शहर से पूर्व सांसद जलालुद्दीन अंसारी, बांका से पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार, कहलगांव से पूर्व विधायक अंबिका प्रसाद, इस्लामपुर से राकेश रौशन, धुरैया से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुन्नीलाल पासवान, सिमरी बख्तियारपुर से ओमप्रकाश संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं. भाकपा कभी विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल की हैसियत रखती थी. भाकपा पंद्रहवीं विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को विधानसभा भेजने की तैयारी में जुटी हुई है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एबी बर्द्धन जनवरी से अब तक चार बार बिहार के दौरे पर आ चुके हैं. इसके अलावा लोकसभा में पार्टी के नेता गुरुदास गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर आदि नेता भी कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं. भाकपा माले ने भी अपनी चुनाव तैयारी शुरू कर दी है. इसी के मद्देनज़र 30 मार्च को राजधानी में पार्टी की बड़ी रैली और 10 मई को किसानों का राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया. माले विधानसभा चुनाव में क़रीब एक सौ सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है. पार्टी की स्थायी समिति ने संभावित सीटों के साथ-साथ उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है. इसके साथ ही संभावित उम्मीदवारों को अपने-अपने चुनावी क्षेत्र में तैयारी शुरू करने का निर्देश भी दे दिया गया है. विधानसभा में जन समस्याओं को जोरदार तरीक़े से उठाने वाले माले सदस्य अमरनाथ यादव का विधानसभा क्षेत्र दरौली आरक्षित हो गया है. इसी चलते माले अपने चर्चित विधायक को फिर से विधानसभा पहुंचाने के लिए सीट खोजने में जुटी हुई है. माले अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान के पुराने खिलाड़ियों के साथ-साथ नए खिलाड़ियों को उतारने की कोशिश करेगा. इसके लिए भी प्रयास शुरू है. आधी अबादी की सीट शशि यादव, माधवी सरकार, सहित कई चर्चित महिला नेत्री भरेगी. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, पार्टी के प्रदेश सचिव नंद किशोर प्रसाद, किसान नेता राजाराम सिंह, मज़दूर नेता धीरेंद्र झा, महिला नेत्री सरोज चौबे सहित पार्टी के सभी बड़े नेता और विभिन्न जन संगठनों के पदाधिकारी चुनाव तैयारी में लग चुके हैं. इन लोगों का कार्यक्रम हर विधानसभा में चालू है.

उधर, माकपा के केंद्रीय नेतृत्व ने हिंदी भाषी क्षेत्र में अपनी मज़बूत उपस्थित दर्ज़ करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव पर पूरा ध्यान केंद्रीत कर दिया है. यही कारण है कि पार्टी पोलित व्यूरो सदस्य एवं सांसद श्रीमती वृंदा करात, पूर्व सांसद एवं किसान नेता एस रामचंद्र पिल्लै जनवरी से अबतक कई बार प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं. यह सभी दौरा चुनावी तैयारी को लेकर ही किया गया है. केंद्रीय पार्टी ने भीतर ही भीतर बिहार में पार्टी को मज़बूत करने की ज़िम्मेदारी श्रीमती वृंदा करात को सौंप दी है.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी 25-35 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगी. मज़बूत जनाधार वाली सीटों का चयन भी कर लिया गया है. साथ ही उम्मीदवारों का चयन जारी है. माकपा अपनी चयनित सीटों की सूची भाकपा को सौंप दी है. माकपा नेताओं का कहना है कि पार्टी किसी भी हालत में विधानसभा चुनाव में राजद, लोजपा, कांग्रेस आदि पूंजीपति पार्टियों के साथ समझौता नहीं करेगी. इसका संकेत श्रीमती करात भी दे चुकी हैं. पार्टी ने चुनाव के मद्देनज़र आंदोलन भी तेज़ कर दी है. इसी का परिणाम है कि सीतामढ़ी ज़िले के रून्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय में क़रीब ग्यारह सौ झोपड़ियों का निर्माण माकपा के नेतृत्व में कराया गया. इसके अलावा 14 जून को पटना में किसानों की रैली. इसे पहले छात्रों-नौजवानों की रैली आयोजित की गई. कहा जा सकता है माकपा विधानसभा चुनाव में अपनी मज़बूत स्थिति दर्ज़ कराने के लिए पूरी दमखम के साथ जुटी है. पार्टी के सचिव विजयकांत ठाकुर विधानसभा चुनाव की तैयारी में दिन-रात एक किए हुए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

शिवपुरी ज़िले के पुनर्स्थापित गांवों में रहने वाले आदिवासी परिवार भूख, कुपोषण और बीमारियों के शिकार हैं.

वनवासियों का त्रासद विस्थापन

कोई कुनो की सुनो

जगदीश यादव

उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में है कुनो पालपुर अभयारण्य. यह ग्वालियर से लगभग 120 किमी दूर है. यहां एक अभयारण्य बनाने और उसमें गुजरात के गीर जंगल के पांच से आठ एशियाटिक शेरों को रखने के लिए 1650 परिवारों (करीब 5,000 लोगों) वाले लगभग 28 गांवों को विस्थापित कर जंगल से बाहर बसा दिया गया. इन परिवारों में ज़्यादातर सहरिया जनजाति के थे.

यह बात अब अख़बारों में प्रकाशित भी हो चुकी है कि गुजरात के वन मंत्री ने गीर के शेरों को देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि 344.686 वर्ग किमी में फैले कुनो अभयारण्य का वातावरण शेरों के अनुकूल नहीं है और उन्हें शिकारियों का ख़तरा है. इसके अतिरिक्त वहां शेरों के भोजन के लिए कोई शिकार नहीं है. गुजरात के वन मंत्री सोचते हैं कि कुनो अभयारण्य में आदिवासियों की मौजूदगी शेरों के लिए ख़तरनाक साबित होगी.

कंद मूल खाने, छोटी-मोटी खेती करने और शिकार करने वाली आदिवासी आबादी उस इलाक़े में विस्थापित कर दी गई है जहां खेती की कोई संभावना ही नहीं है. सूखाग्रस्त इलाक़े में इन लोगों को बिना किसी योजना के बसा दिया गया. इस इलाक़े की मिट्टी भी अनुपजाऊ है. इन परिवारों की जंगल आधारित आजीविका छिन जाने की भरपाई नहीं की गई. पुनर्वास पैकेज की अपर्याप्तता और कार्यान्वयन में टालमटोल से सहरिया जनजाति के लोग दिहाड़ी मज़दूर बनने पर विवश हो गए हैं और उनके सामने खाद्य असुरक्षा का गंभीर संकट पैदा हो गया है. विस्थापन से पहले, वे आजीविका के लिए वन पर आश्रित थे. ग़रीब परिवार अपनी कुल आय का लगभग 30 से 65 प्रतिशत अर्जन वन उत्पादों को बेच कर करता था. इसके अतिरिक्त, वन से उन्हें गोश्त सहित विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, जलावन, चारा और घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल मिलता था.

विस्थापन के शिकार अहिरवानी और पारी गांवों के साथ-साथ कुनो अभयारण्य के बाहरी इलाक़े में स्थित खजूरी कलां, पीपल बावड़ी, नया गांव, पालपुर, परोंद और चाक परोंद गांवों में भी इस संवाददाता को जाने का मौक़ा मिला. इन गांवों में विस्थापित आदिवासी बसे हैं. इस इलाक़े में काम करने वाले सहरिया मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता प्रकाश और एक विस्थापित आदिवासी ओंकार ने बताया कि गुजरात के शेरों के लिए कोई 11 साल पहले 28 गांवों को विस्थापित कर दिया गया था. इन गांवों में से किसी को भी समुचित ढंग से नहीं बसाया गया है. ग़रीबी से लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है. अभयारण्य के किनारे बसे गांव के लोगों की आमदनी काफ़ी घट गई है. पहले जंगल से आदिवासियों को दूध, घी, फल, सब्जी, मवेशी, जड़ी बूटी, सरसफल आदि फल मिल जाते थे. आदिवासी तेंदू पत्ता, गोंद आदि बेचकर पैसा कमाते थे. अब वन के अधिकारी आदिवासियों को जंगल में घुसने नहीं देते. जंगल और इर्द-गिर्द आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. इससे इस आबादी में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो गया है. विडंबना तो यह है कि इन आदिवासियों को परेशानी में डालने के बाद भी यहां शेरों को नहीं लाया गया.

आदिवासियों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा कर विस्थापित किया गया. मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र प्रायोजित परियोजना- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य योजना के तहत कुनो-पालपुर के विकास और संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी गई. 2004-05 और 2006-07 के दौरान कुनो-पालपुर अभयारण्य के लिए 97.19 लाख रुपए जारी किए गए. इसके अतिरिक्त, कुनो-पालपुर अभयारण्य के कारण विस्थापित 1545 परिवारों के पुनर्वास के लिए भी राज्य सरकार को 1436.32 लाख रुपए दिए गए. लेकिन दोबारा बसाए गए गांवों में पानी, बिजली, शौचालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी या स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं. जंगल में इन परिवारों के घर कुनो नदी के किनारे थे. चक परोंद गांव के लालजी ने कहा कि गांव में एक हैंडपंप तक नहीं है. महिलाएं पानी लाने के लिए 3 किमी दूर कनखेड़ा जाती हैं. यहां चारागाह न होने के कारण मवेशी जिंदा नहीं रह सकते. इसलिए हमें अपने सभी पशुओं को जंगल में छोड़ना पड़ा. अब हम खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं.

शिवपुरी ज़िले के पुनर्स्थापित गांवों में रहने वाले आदिवासी परिवार भूख, कुपोषण और बीमारियों के शिकार हैं. इन गांवों के बच्चों में बड़े पैमाने पर कुपोषण फैला हुआ है. सहरिया आदिवासी भूख, कुपोषण, बीमारी और अपनी उपेक्षा के ख़िलाफ़ लगातार संघर्ष कर रहे हैं. श्योपुर और शिवपुरी ज़िलों के गांवों में कुपोषण का ख़तरनाक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है. पातालगढ़ गांव में 2005 और फरवरी 2007 के बीच छह वर्ष से कम उम्र के 29 बच्चे कुपोषण से मर गए. कुपोषण से होने वाली बाल मौतों की बार-बार शिकायत करने पर खाद्य अधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आयुक्तों ने स्थिति और कारणों की जांच के लिए एक संयुक्त जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया. इस आयोग ने नवंबर 2006 में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार को सौंपी. रिपोर्ट में कहा गया कि आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है कि शिवपुर में बड़े पैमाने पर कुपोषण फैला हुआ है. यहां की स्थिति दूसरी किसी भी जगह की स्थिति से बदतर है. मध्य प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक़ शिवपुर ज़िले में अप्रैल और अगस्त 2006 के बीच 40 मौतें हुईं. लेकिन एनजीओ कार्यकताओं ने केवल सात गांवों में कम-से-कम 44 मौतें दर्ज की हैं. इन गांवों में जद्दपुरा, रानीपुरा और गोथरा कपूरा शामिल हैं. सितंबर 2008 में कुपोषण से 165 बच्चे मर गए. जबलपुर स्थित रिजनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल्स द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के अनुसार 93 प्रतिशत सहरिया बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 15 प्रतिशत बच्चे मौत की कगार पर हैं. 70 प्रतिशत से अधिक बच्चों का वजन कम है. वे दुर्बलता के शिकार हैं और उनका विकास रुक गया है. बच्चों में कुपोषण की इतनी ऊंची दर को देखते हुए देश में स्वस्थ वयस्कों की उम्मीद नहीं की जा सकती. 87 प्रतिशत वयस्क अल्परक्तता के शिकार हैं. इन आंकड़ों को दुनिया के बदतरीन आंकड़ों में शुमार किया जा सकता है. सहरिया मुक्ति मोर्चा के ज़रिए उमा चतुर्वेदी विस्थापित आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रही हैं. वे शिवपुर में खाद्य अधिकार अभियान की भी सक्रिय सदस्य थीं. श्योपुर और शिवपुरी ज़िलों के गांवों में व्याप्त भूख और कुपोषण के मुद्दे पर मीडिया, ऐक्टिविस्टों, बुद्धिजीवियों और जनता को लामबंद करने के साथ-साथ वे भ्रष्ट संवेदनहीन अधिकारियों के ख़िलाफ़ लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के लिए आदिवासियों को गोलबंद कर रही हैं.

feedback@chauthiduniya.com

ग़ैरज़िम्मेदार मीडिया

ताक़ पर साख़

- बीच सड़क पर अर्ध सैनिक बल के जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटे जाने और उसकी हत्या पर आमादा भीड़ का बर्बर चेहरा मीडिया के लिए प्राथमिकता का मुद्दा नहीं. जवान को हिंसक भीड़ से बचाने के लिए सीआरपीएफ द्वारा चलाई गई गोली मीडिया के लिए मुद्दा है.
- कर्नल और ब्रिगेडियर स्तर के शीर्ष सैनिक अधिकारियों समेत अन्य फौज़ियों की कश्मीर में आम तौर पर रोज़ाना होने वाली हत्याएं मीडिया के लिए मानवाधिकार हनन का मसला नहीं, लेकिन पगलाई भीड़ को क़ाबू में करने के लिए चलाई गई गोली से किसी के मारे जाने की घटना मीडिया के लिए मानवाधिकार का मसला है.
- मॉडल ने आत्महत्या कर ली तो मीडिया के लिए ख़बर है. लेकिन किसानों की लगातार हो रही आत्महत्याएं मीडिया के लिए इश्यू नहीं.
- फिल्मी हस्तियों के गर्भवती होने की ख़बरें मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में असमय गर्भपात से लाखों महिलाओं के मरने की ख़बरें मीडिया की प्राथमिकता में स्थान नहीं बना पातीं.
- किसी मॉडल का कपड़ा खुल जाए तो मीडिया दिन रात भोंपू बजाए, लेकिन अधनंगे वस्त्र के सहारे उम्र काट देने वाले लोगों की बढ़ती जमात इनके लिए ध्यानाकर्षण का विषय नहीं.
- दिलों को जोड़ने की समाज में चल रही सार्थक कोशिशों पर मीडिया का ध्यान नहीं, पर हर छह दिसम्बर को बाबरी ढांचा तोड़े जाने का दृश्य दिखाना इनकी सेरिमोनियल (त्यौहारी) अनिवार्यता है.
- एक तरफ नक्सलियों के ख़िलाफ़ सेना उतारने की वक़ालत तो दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेज़ स्पेशल पावर एक्ट को वापस लेने की मांगों को हवा देने वाली ख़बरों का नासमझ विरोधाभासी प्रसारण.

दिखाने के लिए शहीदों के सम्मानजनक चिन्ह का अपमान करने जैसी हरकतें क्या मीडिया ने फैशन बना लिया है? ऐसे कार्टून बनाने वाले पत्रकार को बेहतरीन कार्टून का पुरस्कार दिया गया और उसे सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया. लोकतंत्र की पहरेदारी करने वाला मीडिया इस घटिया स्तर का होगा तो देश का तो अल्ला ही मालिक है...

ऐसे ढेर सारे उदाहरण देश के सामने हैं जो यह संकेत देते हैं कि मानव अधिकार और देश हित की समझ को लेकर मीडिया या तो बिल्कुल नासमझ है या हिंदुस्तान की एकता और सामाजिक तानेबाने को तहस-नहस करने की साज़िश में लगी शक्तियों के साथ मिलीभगत का हिस्सा है.

छत्तीसगढ़ में फिर से सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के हाथों मारे गए. मीडिया ने फिर से ख़बर बनाई और एक बार फिर से सरकार पर दबाव बना, नक्सलियों के ख़िलाफ़ सेना उतारने का, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मीडिया इस ख़बर की ओर कभी ध्यान क्यों नहीं देता कि नक्सलियों के निशाने पर हमेशा अर्धसैनिक बल ही क्यों होते हैं? हमेशा सीआरपीएफ के जवान ही क्यों मारे जाते हैं? किसी भी नक्सली ऑपरेशन में सिविल पुलिस वाले क्यों नहीं मारे जाते? कश्मीर में भी हमेशा सैनिक या अर्ध सैनिक बल ही आतंकवादियों के निशाने पर क्यों होते हैं? मीडिया को यह आम बात समझ में क्यों नहीं आती? देश की मीडिया को कश्मीर में या पूर्वोत्तर में हमेशा सेना की गोली ही क्यों दिखती है? आतंकवादियों की गोली उन्हें क्यों नहीं दिखती? अपने ही देश की सेना और अर्ध सैनिक बल का मनोबल गिराने पर आमादा मीडिया को इससे क्या हासिल होने वाला है? ऐसी ख़बरें जो देश की एकता बढ़ाने में मदद करें, ऐसी ख़बरें जो धार्मिक, जातीय या सामाजिक सौहार्द कायम करने में सार्थक भूमिका अदा करे, मीडिया से गुल क्यों रहती हैं? यह देश और उसकी अखंडता को लेकर मीडिया की समझ है.

समाज में भेदभाव की खाई को और गहरा करने वाले मुद्दों पर आप मीडिया पर होने वाली विद्वत बहसें सुन-सुन कर आप पक चुके होंगे. सगोत्र विवाह का मसला हो, सगे रिश्तेदार से शादी का मसला हो, घरेलू कलह का मसला हो या देश की एकता से जुड़ा मसला, विचार और बहस के नाम पर आप मीडिया को सब तहस-नहस करता हुआ पाएंगे. 1984 के दंगे पर मीडिया की भूमिका आपको याद ही होगी. एक तथाकथित स्वयंभू बुद्धिमान पत्रकार के नेतृत्व में चलने वाले एक न्यूज़ चैनल ने तो तीन दिनों का विशेष कार्यक्रम ही चला डाला, जिसमें 1984 के दंगे की तमाम वीभत्सता का री-प्ले देश भर के दर्शकों को दिखाया गया. यह देश को जोड़ने की ज़िम्मेदार कोशिश थी या एक बार फिर से समाज में नफ़रत का विष बोने की शातिराना साज़िश? सेना के एक आला अधिकारी ने मीडिया की हरकतों पर बेसाख्ता कहा, गंगा में कोई पेशाब कर दे तो क्या आप कह देंगे कि गंगा पवित्र नदी नहीं, पेशाब है? इस अधिकारी ने कहा कि मीडिया को गुजरात के दंगे का ज़ख्म कुरेदने की जैसे बीमारी हो गई है. लेकिन वे कभी यह मसला नहीं उठाते कि गुजरात का दंगा हुआ क्यों था? आप क्या यह समझते हैं कि पब्लिक ये सब नहीं समझती? बाबरी मस्जिद पर चलने वाले हथौड़ों की वीभत्स ध्वनि क्या आपको हर साल सुनाने की लत पड़ गई है? मीडिया क्या चाहता है यह सब दिखा कर? आप भारतीय मीडिया हैं या पाकिस्तानी मीडिया या दुनियाभर में समाज को तोड़फोड़ कर अपना धंधा चलाने वाली दुष्ट शक्तियों के घटिया एजेंट? सेना के इस आला अधिकारी की बातें मीडिया के प्रति लोगों में घर करती जा रही घृणा की सनद देती हैं. उक्त अधिकारी की बातें अगर आप मीडिया अलमबरदारों के सामने रख दें तो बड़ा सा विद्वत चेहरा बना कर वे उस सैन्य अधिकारी का धर्म पूछने लगेंगे. अगर वह सेनाधिकारी हिन्दू हुए तो मीडिया के ये विकृत चेहरे उस सेनाधिकारी को भाजपाई या संघी बताने से नहीं हिचकेंगे और अपने चैनलों पर उन्हें फिर से विद्वत-बहस आयोजित कराने का मौक़ा मिल जाएगा.

तो आपको यह बता दें कि ये सेनाधिकारी मुस्लिम हैं. अभी हाल ही दक्षिणी कमान की तैनाती से दिल्ली सेना मुख्यालय आए हैं. उन्होंने दक्षिण के एक प्रमुख मीडिया की करतूत बताई और कहा कि उस मीडिया ने शहीदों के सम्मान में इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति के सामने उल्टी रखी राइफल के नीचे सेना के कुछ घोटालों से सम्बन्धित दस्तावेज रख कर एक कार्टून बनाया. उक्त अधिकारी ने कहा कि सेना के कुछ घोटालों को श्रीलंका में लिट्टे के ख़िलाफ़ चले निर्णायक सैन्य अभियान में मीडिया को ऑपरेशन-फील्ड में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई. यह मीडिया की आज़ादी से जुड़ा मसला नहीं बल्कि देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने की व्यवस्था थी. इसमें श्रीलंका की मीडिया ने भी साथ दिया. लिट्टे के ख़िलाफ़ चलाए गए सैन्य ऑपरेशन की कई सूचनाएं वहां और भारत में भी नए सिरे से हिंसा को जन्म दे सकती थीं. लेकिन वहां की मीडिया के दायित्वबोध के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ. लेकिन भारतीय मीडिया ने जो किया उसके परिणाम सामने हैं. करगिल युद्ध के दौरान मीडिया की हरकतों के कारण दुश्मन को भारतीय सेना की सटीक पोजिशनिंग का पता चलता रहा और टीवी देख-देख कर वे निशाने लगाते रहे और भारतीय सैनिक शहीद होते रहे. हीरो बनने की कोशिश करती एक महिला पत्रकार के कारण सेना का एक पूरा बंकर तबाह हुआ और विक्रम बतरा जैसे अफसर की शहादत हुई. वो पत्रकार इतनी जिम्मेदार निकलीं कि सत्ता के गलियारे में दलाली करने वाले कुछ खास लोगों में आज उनका नाम है. मुंबई हादसे के दौरान भी तो ऐसा ही हुआ था. टीवी देख कर मॉनिटरिंग कर रहे आतंकी सरगनाओं को निशाना साधने में कोई दिक्कत नहीं हुई. इसी बेवकूफाना हीरोगिरी में मीडिया ने अपनी ही एक साथी अंग्रेजी अख़बार की एक पत्रकार को आतंकवादियों का निशाना बनवा दिया. न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों में से एक की भी लाश आपने टीवी पर देखी थी? इसका मतलब क्या अमेरिकी मीडिया बेवकूफ है और हम बुद्धिमान! चुनावों में मीडिया की पतंगबाजी आपने देखी ही है अब तो विज्ञापन के बजाय ख़बरें बेचकर नेताओं से पैसे कमाने जैसी हरकतें पूरा देश जानता है. इन्हीं हरकतों के कारण भारतीय मीडिया ने ख़ुद पर अंकुश लगाए जाने के इंतजाम कर लिए हैं. सरकार को तो बहाना चाहिए और वह बहाना ख़ुद मीडिया अपनी ग़ैरज़िम्मेदाराना हरकतें कर दे रहा है.

प्रभात रंजन दीन
prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद इन धामों में आतिथ्य भावना घटती गई और जनता से मनमाना धन वसूलने की प्रवृत्ति बढ़ी.

दूर हो रहे भगवान

राजकुमार शर्मा

देवभूमि उत्तराखंड के देवालयों में विराजमान नारायण आमजन से कितने दूर हो चुके हैं, यह जनता को इन पावनधामों में पहुंचने पर पता चलता है. इन धामों में दर्शन की फीस में इस वर्ष 40 प्रतिशत की सीधे की गई बढ़ोत्तरी ने भगवान और अवाम की दूरी बढ़ा दी है. इस बढ़ोत्तरी से बदरीनाथ धाम में विराजमान नारायण का दर्शन अब धनाढ्य ही कर पाएंगे. देश का मध्यमवर्ग, ग़रीब किसान या मज़दूर इन विशेष पूजा दरों को देखकर पूजन के बारे में सोच भी नहीं सकता. राज्य के गठन के बाद 9 सालों में इन धामों में पूजा को तीन गुना महंगा किया जा चुका है. बदरी केदार मंदिर समिति प्रतिवर्ष पूजा की दरों में वृद्धि कर रही है. लोगों की आस्था और विश्वास के प्रतीक बदरीनाथ अब जनता जनार्दन से दूर होते जा रहे हैं.

बैकुंठधाम को साकार करने वाले बदरीनाथ धाम को आज भी मोक्ष देने वाला पवित्र स्थल माना जाता है. ऐसी आस्था है कि यहां विराजमान नारायण का दर्शन करके मानव सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाता है. इस आस्था के चलते समस्त उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है. गहरी पौराणिक और धार्मिक आस्था के कारण ही देश के कोने–कोने से श्रद्धालु यहां खिंचे चले आते हैं. लेकिन अब इस पावनधाम में विराजमान नारायण को इनके पुजारी–व्यवस्थापकों ने इतना महंगा बना डाला है कि जनता और जनार्दन अलग अलग होते जा रहे हैं.

उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद इन धामों में आतिथ्य भावना घटती गई और जनता से मनमाना धन वसूलने की प्रवृत्ति बढ़ी. धामों में मंदिर की व्यवस्था के लिए बनाई गई भगवान बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी निरकुंशता का परिचय देते हुए भगवान के दर्शन की फीस में चालीस प्रतिशत की वृद्धि कर पूजा व्यवस्था को ही मंहगा बना डाला. इस बढ़ोत्तरी को राज्य गठन के बाद से ही मनमाने ढंग से अंजाम दिया जा रहा है. वर्ष 2001 में महाभिषेक पूजा की दर 2100 रुपये थी. यह 2007 में 4500 रुपये और 2010 में 6301 रुपये कर दी गई. इस धाम में अभिषेक पूजा की दर 2001 में 1100 रुपये थी जिसे 2007 में 3500 रुपये और 2010 में 4901 रुपये कर दिया गया. इस धाम में नारायण के दरबार में गीतापाठ के लिए जहां वर्ष 2001 में 751 रुपये लिए जाते थे, वह 2007 में 1501 रुपये और 2010 में सीधे बढ़ कर 2101 रुपये हो गया. वेदपाठ के लिए 2001 में 501 रुपये लिए जाते थे जो 2007 में 1001 रुपये हो गया और अब 2010 में इसे बढ़ा कर 1401 रुपये कर दिया गया. धाम में नारायण की खड़े होकर कर्पूर आरती करने का शुल्क 2001 में 75 रुपये था, जिसे 2007 में बढ़ा कर 151 रुपए किया गया और अब 2010 में इसे 211 रुपये कर दिया गया. इस धाम में नारायणश्री की चांदी की थाल में आरती करने की फीस 2001 में 151 रुपये थी, जिसे 2007 में बढ़ा कर 301 रुपये कर दिया गया. स्वर्ण आरती का शुल्क 2001 में 201 रुपये था, जिसे 2007 में 351 रुपये और 2010 में बढ़ा कर 491 रुपये कर दिया गया. धाम में विष्णुसहस्त्रनाम पाठ की फीस 2001 में 301 रुपये थी, जिसे 2007 में बढ़ा कर 401 रुपये और 2010 में 561 रुपये कर दिया गया. विष्णुसहस्त्र नामावली पाठ 2001 में 301 रुपये में होता था, जो 2007 में 501 रुपये और 2010 में 701 रुपये हो गया. शयन आरती गीत में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को 2001 में 501 रुपये देने पड़ते थे. 2007 में यह 1001 रुपये और 2010 में 1401 रुपये हो गया.

देश के कोने–कोने से बदरीकाश्रम पहुंचने वाले हज़ारों ग़रीब किसान मज़दूर नारायण के धाम में पैदल अथवा सार्वजनिक साधनों से किसी तरह धक्के खा कर पहुंच भी जाते हैं, तो इतनी महंगी पूजा दर देख कर इनका सारा धार्मिक भाव उड़नछू हो जाता है. नारायण धाम में क़ब्ज़ा जमाए बैठे पंडित पुजारियों के इस मकड़जाल ने पावनधाम को वसूलीधाम में तब्दील कर दिया है. इस धाम में 2001 में 4,22,647 तीर्थ यात्री आए थे. आठ साल के बाद 2009 में यह संख्या 9,11,333 ही रही. 2001 में मंदिर समिति को लगभग 24 लाख रुपये की आमदनी हुई, जो 2009 में बढ़कर 9 करोड़ 22 लाख के क़रीब पहुंच गई. नर में नारायण का रूप देखने वाली इस देवभूमि में दरिद्र नारायणों की बुरी हालत है. मंदिर समिति सहित धर्म के ठेकेदार चुप हैं.

सरकारी व्यवस्था के नाम पर पुलिस के साथ ही अर्ध सैनिक बल के जवान भी तैनात हैं, किन्तु इनका काम महज़ वीआईपी की सेवा और सुरक्षा ही रह गया है. पिछले ही दिनों धाम में तैनात पुलिस ने बंगाल से आई महिलाओं पर जिस तरह बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाईं, उसने व्यवस्था की सारी कलई खोल दी. मामला इतना बढ़ा कि वहां के व्यापारी भी हड़ताल पर चले गए. सरकार ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की, तब जाकर मामला शांत हुआ. ऐसी घटनाओं की लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है, किन्तु जनता सब भुगतकर वापस चली आती है. घटतौली, मिलावट और तमाम किस्म की ठगी के ज़रिए यात्रियों का शोषण होता है, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं. धर्म के ठेकेदार ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और संपत्ति के लिए आपस में लड़ते भी रहते हैं. इस पीठ में वर्तमान में तीन–तीन शंकराचार्य ख़ुद के जगतगुरु होने का दावा करते हैं, पर यहां की छिन्न–भिन्न व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए कोई पहल नहीं करते.

feedback@chauthiduniya.com

पूजा के लिए साल दर साल बढ़ती क़ीमतें

वर्ष–	2001	2007	2010
महाभिषेक पूजा	2100	4500	6301
अभिषेक पूजा	1100	3500	4901
गीता पाठ	751	1501	2101
वेद पाठ	501	1001	1401
कर्पूर आरती	75	151	211
स्वर्ण आरती	201	351	491
विष्णु सहस्त्रनाम पाठ	301	401	561

मेरी दुनिया.... बढ़ती महंगाई ! ...धीर

पत्र भेजने वाले क़ैदी का कहना है कि वास्तव में जिन 35 क़ैदियों की बेरहमी से पिटाई की गई, उनका न किसी से झगड़ा है और न किसी से कुछ लेना-देना.

जेल की कहानी

तबादले के लिए क़ैदियों को पीटो...

अब क़ैदियों से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को जेल से बाहर निकलने की जल्दबाजी है. नागपुर केंद्रीय जेल के एक कैदी ने पत्र लिख कर पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मसार कर दिया है. इस क़ैदी ने बताया कि जेल अधिकारी तबादला पाने के लिए, यानि जेल की नौकरी से छुटकारा पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने से परहेज़ नहीं करते. पुलिस अधिकारी व कर्मचारी क़ैदियों को बेरहमी से पीटते है ताकि क़ैदी उनकी शिकायत करे और उनका तबादला हो जाए.

नागपुर के वर्धा रोड स्थित केंद्रीय कारा में अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे क़ैदियों को यहां के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें बेरहमी से इस क़दर मारते-पीटते हैं कि किसी की उंगली टूट जाती है तो किसी की कमर में मोच आ जाती है. इस केंद्रीय कारा की अव्यवस्था और यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की काली करतूतों का पर्दाफ़ाश एक क़ैदी ने पत्र लिख कर किया है. क़ैदी का कहना है कि जेल के कर्मचारियों ने पिछले दिनों दो क़ैदियों के आपसी झगड़े को गैंगवार का नाम देकर तीन दिनों के अंदर 35 क़ैदियों की बेरहमी से पिटाई की. इस पिटाई से कई क़ैदियों के हाथ और उंगली टूट गई, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर में मोच आ गई. इस पिटाई से कई क़ैदियों की हालत ऐसी हो गई है कि वो चल भी नहीं सकते. इसी हालत में यहां के 3 क़ैदियों को दूसरे जेलों में स्थानांतरित भी किया गया. 6 क़ैदियों को अंडा सेल में बंद कर दिया गया. यहां के कुछ अधिकारी हर दिन बैरकों से क़ैदियों को चुन-चुन कर ले जाते हैं और बेरहमी से उनकी पिटाई करते हैं. फिर उन्हें जेल बदल देने की धमकी दे कर चुप रहने के लिए भी कहते है. चूंकि जेल बदल जाने से क़ैदियों के परिवार वालों को परेशानी होती है, इसलिए क़ैदी डर से चुप रहते हैं.

पत्र भेजने वाले क़ैदी का कहना है कि वास्तव में जिन 35 क़ैदियों की बेरहमी से पिटाई की गई, उनका न किसी से झगड़ा है और न किसी से कुछ लेना-देना. इनका सिर्फ़ इतना ही दोष था कि इन्होनें जेल में व्याप्त समस्याओं के संबंध में जेल अधीक्षक से शिकायत की थी. क़ैदी का कहना है कि जेल प्रशासन यहां की अव्यवस्था और क़ैदी अधिकारों के संबध में एक भी सवाल बर्दाश्त नहीं करता है. इसके अलावा नागपुर जेल में तैनात क़रीब 90 प्रतिशत अधिकारी विदर्भ क्षेत्र से बाहर के हैं. यहां के ज़्यादातर कर्मचारियों का इस जेल में दंडस्वरूप तबादला किया जाता है. यहां आए कुछ अधिकारियों पर जेल में बंदियों की हत्या, हत्या के प्रयास आदि जैसे मामले भी चल रहे हैं. विदर्भ के बाहर के पुलिस विभाग से नागपुर जेल में आए अधिकारी और कर्मचारी कुंठित हो गए हैं. कई कर्मचारी तो जानबूझ कर क़ैदियों को प्रताड़ित करते हैं ताकि क़ैदी उनकी शिकायत करें और उनका यहां से जल्द-से-जल्द तबादला हो जाए. पत्र में उक्त क़ैदी ने योगेश पाटिल नाम के एक जेलकर्मी के नाम का उल्लेख करते हुए कहा है कि पिटाई करने वालों में योगेश पाटिल सबसे बेरहम हैं. जेल अधीक्षक की ओर से योगेश पाटिल को पूरा शह मिलता है. इसलिए क़ैदियों को फुटबॉल की तरह मैदान में मारा जाता है. पत्र में 7 मई की एक घटना का हवाला देते हुए क़ैदी ने लिखा है कि इस दिन सुबह-सुबह जेल में मारपीट हुई. उसी दिन एक क़ैदी जेल में अव्यवस्था के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल पर बैठा था. उसकी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए योगेश पाटिल ने उसकी जमकर पिटाई की. वह तब तक उसकी पिटाई करता रहा जब तक कि उसने खाना खाकर अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी. सच्चाई छिपाने के लिए जेल प्रशासन ने गैंगवार की कहानी रची. इससे जेल अधिकारियों को ही लाभ मिलता है. गैंगवार पर नियंत्रण होने से इन्हें पुरस्कार और पदोन्नति मिलती है. जेल प्रशासन की इस बेरहम करतूत और मनगढ़ंत गैंगवार की कहानी से यहां का हर क़ैदी डरा और सहमा हुआ है. अब तो यहां का हर कर्मचारी क़ैदियों से बदतमीजी और गाली-गलौज की भाषा में ही बातचीत करता है. क़ैदी ने पत्र में लिखा है कि जेल प्रशासन सरकार के जेल सुधार और पुनर्वास नीति को ताक पर रखकर क़ैदियों के अधिकारों का हनन कर रही है.

इस संबंध में जब चौथी दुनिया ने बातचीत करने के लिए जेल में फोन से संपर्क किया तो वहां उपस्थित एक कर्मचारी ने कहा कि प्रभारी अधिकारी अभी नहीं है. इसलिए इस संबध में हम कुछ भी नहीं कह सकते. एक अन्य अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि क़ैदियों के सारे आरोप ग़लत हैं. एक क़ैदी ने तो कुछ माह पूर्व जेल के एक हवलदार पर हमला कर दिया था. क़ैदी आपस में लड़ते रहते हैं. क़ैदियों की गुटबाजी तोड़ने के लिए कुछ क़ैदियों को अलग-अलग जेल में भेजने के आदेश भी आ चुके है. बहरहाल, उक्त अधिकारी की बात अगर सही भी है तो क्या कुछ क़ैदियों की ग़लती की सज़ा सारे क़ैदियों को देना, उन्हें डंडे के ज़ोर पर आतंकित कर के रखना और उनकी पिटाई करना क्या जायज़ है? ज़ाहिर है, इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस विभाग को संवेदनशील हो कर सोचना पड़ेगा. आख़िर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती इस जेल में की ही क्यों जाती है जो महज़ तबादला पाने के लिए ऐसे अमानवीय हरकत करते हैं. और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें दंडस्वरूप क्यों नहीं उनके गृह ज़िला से और दूर तैनात कर दिया जाता है ताकि आगे से वो किसी क़ैदी को पीटने से पहले दस बार सोचे. और कम-से-कम सरकार को इस रिपोर्ट में छपे पत्र के आधार पर तो इस पूरे मामले की जांच करवानी ही चाहिए.

संजय स्वदेश
feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

बेहाल है जननी सुरक्षा योजना

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना का हाल-बेहाल है. प्रसव केंद्र के बाहर सड़क पर महिलाएं बच्चा जनने को मजबूर हैं. यह हाल तब है जबकि यहां की मुख्यमंत्री महिला है. प्रदेश के 3424 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर केवल 32 महिला डॉक्टर तैनात हैं, जबकि पांच हज़ार से अधिक पुरुष डॉक्टर हैं. पीएमएस कैडर में महिला डॉक्टरों के लिए 15 फ़ीसदी का कोटा है, जबकि लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिलाओं को कोटा देने की बात हो रही है. पिछले 10 साल में एक भी एमबीबीएस छात्रा पीएमएस कैडर में डॉक्टर नहीं बनी. आधी आबादी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी दर्दनाक है. गर्भावस्था कोई रोग नहीं है, फिर भी हर वर्ष गर्भावस्था, शिशु-जन्म और असुरक्षित गर्भपात के कारण हज़ारों महिलाएं अकारण ही मौत का शिकार हो जाती हैं. विचलित कर देने वाली बात यह है कि मरने वाली इन महिलाओं की कोई गिनती नहीं होती और कोई यह भी नहीं देखता कि इन्हें हुआ क्या था. बेबुआ नौरगिया (कुशीनगर) स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव पीड़ा से कराह रही मुसहर महिला ने खुले में सड़क पर बच्चा जना, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे भगा दिया था. घटना के बाद ग्रामीण गुस्से में आ गए और कोटवा मार्ग को जाम कर दिया. मौक़े पर पहुंचे प्रभारी चिकित्साधिकारी ने दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया, लेकिन क्या सज़ा मिली इसका आज तक पता नहीं चला. ग्राम मड़ार विन्दवलिया मुसहर टोली निवासी पारस मुसहर की पत्नी माया देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ. इनके परिजनों का आरोप है कि एएनएम प्रसव कराने के एवज में पैसे मांग रही थी. पैसा न देने पर अस्पताल से भगा दिया. महिला ने सड़क पर ही बच्चा जना. आसपास की महिलाओं ने चारों ओर से चादर टांग कर बच्चा पैदा कराया. नाराज़ ग्रामीणों ने फिर चक्का जाम कर दिया. प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. पीके मिश्र मौक़े पर पहुंचे और जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य केंद्र ले गये. दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात भी कही गई, लेकिन नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात. ये घटनायें बताती हैं कि जननी सुरक्षा योजना का प्रदेश में क्या हाल है. श्रावस्ती ज़िले में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 72 दाइयों को प्रशिक्षित किया गया और इन्हें प्रसव किट उपलब्ध कराया गया था, लेकिन प्रदेश में मातृत्व और शिशु मृत्यु दर का ग्राफ अभी भी ऊंचा है.

उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये लंबी दूरी तय करनी है. अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां प्राथमिक और समग्र आपातकालीन प्रसूति देखभाल सेवाएं दिया जाना निश्चित किया गया था, वहां सेवा शुरू ही नहीं हुई. प्रदेश में एक लाख में 517 महिलाएं प्रसव के दौरान दम तोड़ रही हैं और उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले 1000 शिशुओं में 67 जीवित नहीं बचते. शिशु मृत्यु की घटनाओं में लगभग एक चौथाई उत्तर प्रदेश में दर्ज होती हैं. 100 में से मात्र 22 बच्चे ही अस्पताल में जन्म लेते हैं. तीन चौथाई प्रसव अस्वास्थ्यकर वातावरण में घर में ही होते हैं. गर्भवती महिलाओं में 80 प्रतिशत एनेमिक होती हैं.

प्रदेश में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 583 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है. एक तिहाई से कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति या स्त्रीरोग विशेषज्ञ नियुक्त हैं और लगभग 45 प्रतिशत स्वास्थ्य केंद्रों में मौजूद एंबुलेंस चलाने के लिए भी धन उपलब्ध नहीं है. वास्तविकता यही है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित हर 20 में से केवल 1 प्राथमिक रेफरल अस्पताल (समग्र आपातकालिक प्रसूति देखभाल सुविधा केंद्र) में ही ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराया जाता है और केवल 100 में से 1 इकाई में ख़ून भंडार करने की सुविधा उपलब्ध है. ह्यूमन राइट्स वॉच ने उत्तर प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ज़िला अस्पतालों का दौरा किया. हाल यह है कि गर्भवती महिलाओं को कभी-कभी ख़ून चढ़ाने या ऑपरेशन से प्रसव कराने के लिए 100 किलोमीटर (60 मील) से भी अधिक दूर के स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर कर दिया जाता है. जब किसी महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाते हैं, तो उसे अपनी नाल कटवाने, दवाईयों के लिए पैसा देना पड़ता है. सफ़ाई आदि करने के लिए भी कुछ पैसा देना पड़ता है. स्टाफ नर्स भी पैसा मांगती है.

सरकार का दावा

महिला चिकित्सकों की कमी के संदर्भ में सरकार का तर्क है कि अस्पतालों में तमाम नर्सें व आशाकर्मी नियुक्त हैं, इसलिए महिला गाइनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है. महिला चिकित्सक सूदूर गांव की पीएचसी में काम करने नहीं जा सकतीं.

स्वयंसेवी संगठन का कहना है

स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की निशा वारिया कहती हैं कि सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के लिए गर्भावस्था से संबंधित मृत्यु के सभी मामलों की औपचारिक सूचना दिए जाने को अनिवार्य किया जाना चाहिए. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ मृत्यु की घटनाओं की जांच की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए. जांच के दौरान प्रक्रिया संबंधी कमियों पर ध्यान दिया जाए और इससे प्राप्त परिणामों को ज़िला और राज्य स्तर की योजनाएं बनाते समय एकीकृत किया जाए.

आख़िर क्या है जननी सुरक्षा योजना

प्रसव के दौरान निरंतर जच्चा व बच्चा की मौतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जननी सुरक्षा योजना लागू की. इसका मक़सद संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना रहा है. जननी सुरक्षा योजना में संस्थागत प्रसव कराने के लिए हर महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देने का नियम है. गांव की महिला को 1400 रुपये, शहर की महिला को एक हज़ार तो घर में बीपीएल परिवार की महिला को प्रशिक्षित हाथों से प्रसव पर पांच सौ रुपये दिये जाते हैं. यह प्रोत्साहन राशि आशा बहू को भी मिलती है, जो महिला को अस्पताल तक ले जाती है और इसका टीकाकरण आदि करती है.

योजना में सुराख़

जननी सुरक्षा योजना में धन को ठिकाने लगाने के पूरे बंदोबस्त हैं. असल में सरकारी अस्पताल वही तबका आता है, जो ग़रीब है. इन्हें आसानी से ठगा जा रहा है. डिस्चार्ज होते समय उन्हें धन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. पैसों के लिए उन्हें महीनों दौड़ाया जाता है. कहा जाता है कि बजट नहीं है. इस योजना में सब कुछ नि:शुल्क है, लेकिन महिलाओं को भर्ती करने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं, इसे एडमिशन फीस कहा जाता है. इसके अलावा बाकी सुविधाओं की दरें भी तय हैं. फार्म भरने से लेकर अन्य औपचारिकताओं तक.

सोनिया के क्षेत्र का हाल

प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जनपद रायबरेली, जहां से संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा के लिये चुनकर आती हैं, में जननी सुरक्षा योजना के तहत बीते वर्ष 44 हज़ार संस्थागत प्रसव कराए गए. 42 हज़ार महिलाओं को धन मिल चुका है. दो हज़ार महिलायें प्रतीक्षारत हैं. जागरूक जनपदों में शुमार रायबरेली के नसीराबाद में दलित महिला के अस्पताल गेट पर प्रसव के मामले में तो प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक तक को जांच के लिए आना पड़ा था. ज़िले में दो दर्जन से अधिक जच्चा-बच्चा काल के गाल में समा चुके हैं.

feedback@chauthiduniya.com

राज्यों में पार्टी की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वहां इसकी हालत पहले से ही ख़राब बनी हुई है.

राजनीति दिखावा ही तो है...

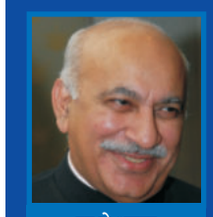

एम जे अकबर

सत्ता राजनीति में गोंद का काम करती है. यही वजह है कि सत्ता में बनी सरकारें अक्सर सुसंगठित होने का आभास देती हैं जबकि विपक्षी दल आमतौर पर बिखरे हुए नज़र आते हैं. स्वार्थ सिद्धि के मौजूदा दौर में एकता बनाए रखने के लिए विचारधारा की कोई अहमियत नहीं होती. असलियत तो यह है कि विचारधारा की ग़ैरमौजूदगी ने एकदलीय शासन और गठबंधन सरकार के बीच के अंतर को ख़त्म कर दिया है. अब इन दोनों ही व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत या सामुदायिक स्वार्थ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं और इनके अस्तित्व का आधार भी यही है. विचारधारा तो बांटने का काम करती है, यह दो पक्षों के बीच सहयोग को असंभव बना देती है. अब यह बात और है कि दोनों संबद्ध पक्ष ख़ुद ऐसा नहीं सोचते, उन्हें लगता है कि वे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा उन्हें ऐसा करने से रोक देती है. राजनीतिक गठबंधन में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती. यह उन सभी देशों के लिए एक समान रूप से सत्य है जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और जहां गठबंधन सरकार ज़रूरत बन चुकी है. राजनीतिज्ञ सत्ता के लिए ही जीते हैं, भावनाओं की कद्र कर वे समय से पहले ही अपने राजनीतिक अवसान को आमंत्रित क्यों करेंगे?

विचारधाराओं एवं व्यक्तिगत या दलीय जवाबदेही की भावनाओं से कोसों दूर जा चुकी भारतीय राजनीति गठबंधनों के लिए सर्वथा उपयुक्त है. यदि जवाबदेही की कोई भावना होती, तो ए.राजा मनमोहन सिंह की सरकार में अब तक मंत्री नहीं बने रहते. लेकिन ऐसा नहीं है और मौजूदा गठबंधन बना रहेगा– बिना किसी आलोचना या कलंक के. थोड़े–बहुत पब्लिक रिलेशंस की ज़रूरत हो सकती है ताकि इस कलंक पर परदा डाला जा सके. गठबंधन के साझीदार दलों के लिए कभी–कभार आपसी मतभेदों को हवा देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. यह ख़ासकर तब होता है जब चुनाव सिर पर हों और राजनीतिक दलों को आम लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपना अलग चेहरा दिखाने की ज़रूरत महसूस

होती है. कोई आश्चर्य नहीं कि बंगाल और बिहार, दो ऐसे राज्य जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, दिखावे की राजनीति का नया नमूना बन गए हैं.

राजनीति के लिहाज़ से देखें तो ममता बनर्जी की दिली ख्वाहिश यही होगी कि कांग्रेस पार्टी को किनारे कर वह इसके सारे वोट हथिया लें. लेकिन बंगाल में कांग्रेस का वोट बैंक अभी भी मौजूद है. यह कम भले हो, लेकिन जब तक ऐसा है तब तक ममता इसके साथ अपने गठबंधन को ख़त्म करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकती. गठबंधन के गणित में थोड़ा–बहुत बदलाव आ सकता है और यह अनुचित भी नहीं है क्योंकि अब तो म्युनिसिपल चुनावों से भी नए समीकरण बन जाते हैं. मई महीने में बंगाल में हुए म्युनिसिपल चुनाव के नतीजों के निहितार्थ भले अब पूरी तरह स्पष्ट हुए हों, लेकिन एक सच्चाई तो पहले ही पानी की तरह साफ हो चुका था. वह ये कि तृणमूल के मुक़ाबले कांग्रेस के ख़िलाफ़ वामपंथी दलों का प्रदर्शन कहीं अच्छा था. ज़ाहिर है, ममता गठबंधन में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेंगी, लेकिन वह राजनीति के गूढ़ रहस्यों से भी अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं. वह कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन की अंदरूनी ताक़त को समझती हैं और इतना दबाव कभी नहीं बनाएंगी कि इसके अस्तित्व पर ही ख़तरा मंडराने लगे. रेलवे मंत्रालय की अपनी ज़िम्मेदारियों की क़ीमत पर बंगाल में कुंडली मार कर बैठी ममता की आलोचनाओं से कांग्रेस भी वाक़िफ़ है, लेकिन वह इसे मुद्दा नहीं बनाएगी. यह विशुद्ध राजनीति का खेल है और बंगाल में अगले साल विधान सभा चुनावों के बाद किसी नए राजनीतिक खेल की शुरुआत भी हो सकती है.

बिहार की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है. नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी भी अपने–अपने कैलकुलेटरों के साथ व्यस्त हैं और उनकी गणितीय गणनाओं का मक़सद दोनों दलों के लिए फ़ायदेमंद ज़मीनी हक़ीक़त की तलाश करना है. नरेंद्र मोदी के साथ ग़लबहियां करते और हाथ मिलाते नीतीश कुमार की तस्वीर बिहार के मतदाताओं ने पहली बार नहीं देखी. यह तस्वीर तो पिछले साल आम चुनावों के दौरान ही अख़बारों के पहले पन्ने पर छप चुकी थी. बिहार के मुसलमान वोटरों ने इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के पक्ष में वोट दिया था क्योंकि प्रदेश में शांति बनाए रखने और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वो नीतीश का शुक्रिया अदा करना चाहते थे. उन्हें पता था कि वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में वोट दे रहे हैं. लेकिन इसके बाद से लेकर अब तक स्थितियां बदल चुकी हैं. नीतीश को मुसलमानों से मिले समर्थन में कमी आ चुकी है. इस तस्वीर पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर नीतीश इसी की भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे. नेता ऐसे राजनीतिक तमाशे करते ही रहते हैं. फिर, चुनाव पास हों तो ऐसे खेल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं. भाजपा भी इस मुद्दे पर तकरार की मुद्रा में ज़रूर थी, लेकिन यह केवल दिखावा ही था. पार्टी का असली मक़सद तो शिथिल पड़े अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना था, अपने वोट बैंक को बनाए रखना था. दोनों ही दलों के नेताओं को यह पता है कि गठबंधन टूटा तो सत्ता दोनों के हाथों से निकल जाएगी. सत्ता का सुख भोग चुकी दोनों पार्टियां कभी ऐसा नहीं होने देना चाहेंगी.

यूपीए के दूसरे कार्यकाल में राजनीतिक पार्टियों के बीच मतभेद कम देखने को मिला है, समस्या तो पार्टियों के अंदर है. पिछले एक साल में भाजपा सुर्ख़ियों में बनी रही है तो इसकी एकमात्र वजह इसके नेताओं के बीच आपसी मतभेद हैं. जसवंत सिंह की जिन्ना पर लिखी किताब हो या पार्टी में उनकी वापसी, ऐसे तमाम मुद्दे मीडिया के लिए गर्मागर्म ख़बर बनते रहे हैं. पार्टी में जसवंत की वापसी से स्थिति थोड़ी सुधरी ज़रूर है, लेकिन अपनी साख बनाए रखने के लिए भाजपा को अभी और भी प्रयास करने होंगे. भाजपा की इस हालत पर कांग्रेस को अंदर ही अंदर ख़ुश होना चाहिए था, लेकिन ख़ुद कांग्रेस की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है. वह असहज महसूस कर रही है. पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमतों को बाज़ार के भरोसे छोड़ने जैसे अलोकप्रिय फ़ैसले इसी का परिचायक हैं तो पार्टी के प्रवक्ताओं की हालत ऐसी है कि वे उल–जुलूल बयान देने के नए कीर्तिमान बना रहे हैं. पिछले कुछ सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब पार्टी के नेताओं को देशी न्यूज़ चैनलों से ज़्यादा अच्छा विदेशी चैनलों के स्टूडियो में बैठना लग रहा है. कांग्रेस अभी लड़ाई की मुद्रा में नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि 2014 के आम चुनावों से पहले अपनी खोई ज़मीन हासिल करने के लिए इसके पास काफी समय है.

राज्यों में पार्टी की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वहां इसकी हालत पहले से ही ख़राब बनी हुई है. आंध्र प्रदेश में कांग्रेस बग़ावत से जूझ रही है तो कर्नाटक में एकाकीपन से, महाराष्ट्र में अनिश्चितता की हालत में है तो मध्य भारत में मतदाताओं की अरुचि का, बंगाल में ममता के खूंटे से बंधने को मजबूर है तो बिहार में इसकी हालत जस की तस बनी हुई है और पंजाब में अकालियों के दबाव में भटकाव का शिकार है. इसकी सारी उम्मीदें बस राहुल गांधी पर टिकी हैं. पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनावों में ख़ुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देंगे और असंभव को संभव बनाकर इसे एक नया जीवन देने में कामयाब होंगे.

क्षेत्रीय दलों को भी अपने हिस्से की सुर्ख़ियों की ज़रूरत है और अपने पुराने मित्र अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से बर्ख़ास्त करने के लिए मुलायम सिंह यादव नए तरीक़े तलाश लेते हैं. उत्तराधिकार के लिए डीएमके में चल रही लड़ाई तो किसी सोप ओपेरा से भी ज़्यादा रोचक है. सामंतवादी संस्कृति में पली–बढ़ी पीढ़ी के लिए ऐसी लड़ाईयां न तो अतार्किक हैं, न ही नई. एक महिला के प्रभुत्व वाली पार्टियों में सबकुछ शांत नज़र आ रहा है क्योंकि इसके नेता ख़ुद को या एक–दूसरे को पार्टी से बर्ख़ास्त ही नहीं कर सकते. सत्ता का गोंद केवल आम जनता के गुस्से से पैदा हुई गर्मी से ही पिघलता है. बढ़ते भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई के साथ भोपाल गैस लीक मामले से जुड़े ताज़ा विवाद ने थोड़ी हलचल ज़रूर पैदा की है, लेकिन गोंद के पिघलने के लिए अभी और गर्मी की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

मनरेगा : काफ़ी गुंजाइश है सुधार की

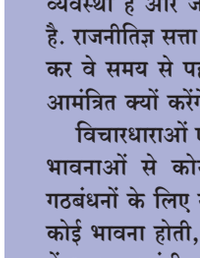

डॉ. सौमित्र मोहन

मनरेगा के तहत काम के दौरान मज़दूरों को मिलने वाली सुविधाएं संदेह के घेरे में हैं. योजना में इन सुविधाओं से संबंधित स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इनका कहां तक पालन किया जाता है, यह संदेहास्पद है. योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यस्थलों पर न तो प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध होती और न ही पीने का साफ पानी. काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है, जबकि इसका स्पष्ट निर्देश योजना की नियमावली में है. बचाव में तर्क यह दिया जाता है कि उक्त कामों को करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, जबकि मज़दूरी एक समान ही देनी पड़ती है और फिर इससे मज़दूरों में असंतोष पैदा होता है. यदि कहीं इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया जाता है तो केवल खानापूर्ति ही की जाती है. आश्चर्य की बात तो यह है कि ज़िम्मेदार अधिकारी इन कामों की अहमियत को नहीं पहचानते. उन्हें यह पता नहीं कि शारीरिक रूप से कमज़ोर या विकलांग लोगों को ऐसे कामों में लगाकर उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता है. यदि ऐसे लोग आसानी से उपलब्ध नहीं हों तो बाक़ी मज़दूरों को ही थोड़े–थोड़े दिन के लिए इस काम में लगाया जा सकता है.

योजना के तहत पूरे किए जा चुके या चल रहे कार्यक्रमों से संबंधित साइनबोर्ड लगाने से संबंधित प्रावधान की भी अक्सर अनदेखी कर दी जाती है. यदि यह साइनबोर्ड लगाया भी जाता है तो इस पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती. ज़ाहिर है, इससे क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार लोगों की असली नीयत का पता चलता है. इस सूचना को छुपाकर वह आम लोगों को काम की मात्रा या गुणवत्ता पर सवाल उठाने का मौक़ा नहीं देना चाहते. लेकिन वह यह नहीं जानते कि सूचना के अधिकार के इस युग में किसी भी जानकारी को हासिल करना कितना आसान है. इसका उपयोग कर कोई भी आम नागरिक उनकी कारगुज़ारियों के बारे में आसानी से जान सकता है. मनरेगा की संरचना में सुधार करने और इसे ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं. कई लोगों का मानना है कि इसके अंतर्गत सामग्री और मज़दूरी के बीच 40 : 60 के अनुपात को बदलकर 50 : 50 कर दिया जाना चाहिए. साथ ही, इसे राज्य स्तर की परियोजनाओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए ताकि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी हो. मशीनों के इस्तेमाल में ज़्यादा स्वतंत्रता की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि काम की गुणवत्ता पर असर पड़े या अधिकतम श्रम दिवसों के सृजन के मनरेगा के प्राथमिक उद्देश्य में कोई बाधा खड़ी हो.

मनरेगा के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों में कमज़ोर तबके और छोटे किसानों के लिए व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं का प्रावधान भी है. बंजर या कृषि के लिए अयोग्य भूमि कृषि योग्य बनाना, जल संवर्द्धन परियोजना, कुओं की खुदाई, मिट्टी संरक्षण, सामाजिक वानिकी योजनाएं, वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम, सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण जैसी योजनाओं में इसकी व्यवस्था है.

व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन कई अन्य राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं. आम राय यही है कि मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के क्रियान्वयन में सावधानी से कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे न केवल ज़्यादा श्रम दिवसों का सृजन किया जा सकता है, बल्कि ग्रामीण इलाक़ों में लाभकारी परिसंपत्तियों का निर्माण भी संभव है. इससे इन क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास की गति को तेज़ किया जा सकता है. लाभार्थियों का सावधानीपूर्वक चयन और योजना के लिए मॉडल बैंक का गठन करने से व्यक्तिगत लाभ योजनाओं का सही इस्तेमाल किया जा सकता है.

व्यवस्था, फिर मनरेगा के साथ अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों को जोड़कर भी इसकी उपयोगिता में इज़फ़ा किया जा सकता है. सूत्र अभिकरणों द्वारा संचालित की जा रही अन्य योजनाओं को मनरेगा के साथ जोड़ने से रोज़गार के ज़्यादा अवसर पैदा किए जा सकते हैं. इतना ही नहीं, इससे काम की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार अभिकरणों के पास ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं. मनरेगा के संचालन के लिए हर स्तर अर्थात ज़िला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों पर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के गठन से भी इसके क्रियान्वयन में सुधार संभव है. हालांकि, योजना की संरचना में ऐसे यूनिट के गठन का प्रावधान पहले से मौजूद है, लेकिन

अधिकतर इलाक़ों में अब तक इसका गठन नहीं किया गया है. फिर, आधारभूत आवश्यकताओं और मानव संसाधन की पूर्ति के लिए योजना के तहत उपलब्ध कराए गए छह प्रतिशत के आकस्मिक कोष का भी बेहतर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, बैंकों, पोस्ट ऑफिस और अन्य संबद्ध पक्षों के बीच बेहतर तालमेल से क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार संस्थाओं तक सरकारी रकम के पहुंचाने की प्रक्रिया को ज़्यादा आसान और बेहतर बनाया जा सकता है.

इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक संचालित सभी रोज़गार योजनाओं में मनरेगा सबसे ज़्यादा सफल रहा है. लेकिन यह भी सच है कि इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है. सबसे पहली ज़रूरत तो योजना के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करना है. लेकिन इससे समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी. ज़रूरत इस बात की भी है कि योजना की संरचना में सुधार किया जाए. देश के ग्रामीण इलाक़ों में ग़रीब मज़दूरों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने और साथ में आधारभूत संरचनाओं के विकास की केंद्र की यह महत्वाकांक्षी योजना तभी पूरी तरह सफल होगी.

(लेखक पश्चिम बंगाल में आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

मुद्दों पर चिंतन ज़रूरी है

केंद्र और राज्यों में गठबंधन सरकारों का अभी तक का अनुभव अच्छा नहीं रहा है. अब समय आ गया है कि देश में मिली जुली सरकारों का गठन हो ताकि स्थाई तौर पर कम से कम पांच सालों तक सरकार काम करती रहे और बार–बार के उपचुनावों का बोझ जनता को न सहना पड़े. पक्ष और प्रतिपक्ष मिल बैठ कर देश की नीति और विकास की तरफ़ ध्यान दे सकेगी. भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों पर भी चिंतन हो, न कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए.

***शैलांचली,** ई–मेल से*

गैस त्रासदी में मिला पैसा कहां गया

पच्चीस साल से भोपाल गैस के शिकार परिवार अकेले लड़ाई लड़ रहे थे. कोई राजनैतिक दल उनके साथ नहीं खड़ा था. भाजपा तो बिल्कुल नहीं. भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वह गैस पीड़ितों के हितों की रक्षा करेंगे, पर भाजपा की सरकार तो पहले भी मध्य प्रदेश में रही है. उसने न मरे लोगों को ज़्यादा मुआवज़ा दिलवाने या देने का फ़ैसला लिया और न प्रभावित परिवार को मदद पहुंचाने की कोशिश की. दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान गैस पीड़ितों के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि कांग्रेस के मुक़ाबले भाजपा को राजनीतिक फ़ायदा कैसे पहुंचे, इसके रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं. गैस कांड के वक़्त 1984 में तत्कालीन प्रदेश और केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने भी पीड़ितों की लाशों और दर्द का सौदा किया था. हज़ारों करोड़ डॉलर की क़ीमत पर एंडरसन को भगाया. मुआवज़े की रकम मुट्ठीभर तय की गई, वह भी काग़ज़ों पर, बाक़ी का लाखों करोड़ डॉलर सरकारी भ्रष्टाचारियों के स्विस बैंक खातों में जमा हो गया, किंतु पाप का घड़ा तो फूटता ही है. देश का क़ानून भले ही अंधा हो लेकिन भगवान सब देखता है. वर्तमान बीजेपी सरकार भी बहती गंगा में नहाने की तैयारी कर रही है, उसे यह नहीं मालूम की सबका मालिक है, उसका क़ानून अंधा नहीं है.

महेश चंद्र वर्मा
चीफ एडिटर
सरकारी व्यापार भ्रष्टाचार
इंदौर से निकलने वाला साप्ताहिक अख़बार

ईमानदार प्रयास के लिए बधाई

संपादक जी, सच्चाई का दामन आप हमेशा अपने साथ रखना, एक दिन आपकी जीत होगी. और एक इंसान सतपाल तंवर जी से भी मैं काफी प्रभावित हुआ. शायद उनके मन में कोई न कोई क्रांति की ज्वाला भड़क रही है. आप भी सतपाल जैसे क्रांतिकारियों का साथ जरूर देना.

***आशीष श्रीवास्तव,** ई–मेल से*

आश्चर्य भी है और ख़ुशी भी

कवर स्टोरी देश के लोगों पर गोली नही चलाएंगे, पढ़कर आश्चर्य भी हुआ और ख़ुशी भी. आश्चर्य इस बात पर कि देश में पुलिस की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए सेना की मदद की ज़रूरत पड़ रही है. ख़ुशी की बात यह है कि सेना ने अपने विवेक से काम लेते हुए इस फ़ैसले को अस्वीकार कर दिया. आख़िर सही भी है, कि जो सेना अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए सीमा पर ज़िंदगी और मौत से लड़ती है, वह अपने ही देश के नागरिकों पर गोली कैसे चला सकती है.

***शेखर कुमार,** धौलपुर, राजस्थान*

कंटेंट बेहतर है

कंटेंट के लिहाज से अख़बार का कोई जवाब नहीं है. राजनीतिक खबरों से लेकर साहित्य, खेल और सिनेमा नियमित रूप से पढ़ता हूं. संपादकीय में विषयों में विभिन्नता रहती है. आशा है कि इसी प्रयास के साथ आगे भी अख़बार पढ़ने को मिलता रहेगा.

***बृजेंद्रनाथ शुक्ला,** आगरा*

दिग्विजय सिंह का जाना...

आमतौर पर आजकल के नेताओं से ज़्यादा सुहानुभूति नहीं रहती लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो भ्रष्ट व्यवस्था के बीच भी अपना काम ईमानदारी से करते रहते हैं. ऐसे ही ईमानदार नेताओं में से एक थे दिग्विजय सिंह. उनके जाने पर वाकई अफसोस हुआ. उनका जाना भारतीय राजनीति में एक अपूरणीय क्षति है. आपके अख़बार ने देश के एक सच्चे नेता को सच्ची श्रद्धांजलि दी है. दिग्विजय सिंह से चौथी दुनिया की अंतिम बातचीत भी अपने आप में भारतीय राजनीति का एक अहम दस्तावेज़ माना जा सकता है.

***राम नरेश,** बांका*

सरकार की लापरवाही

पिछले अंक की ख़बर *सरकार इन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती,* शशि शेखर की रोचक ख़बर है. यह ख़बर मौजूदा केंद्र सरकार की उन साजिशों का पर्दाफाश करती है, जो जघन्य अपराध के दोषियों को बचाने के लिए रची गईं. एंडरसन के अलावा क्वात्रोची, दाऊद इब्राहिम जैसे तमाम अपराधियों की ऐसी लंबी सूची है जिसे पकड़ कर भारत वापस लाने में केंद्र सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है.

***धर्मेंद्र सिंह,** पटना*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें.
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

पाकिस्तान में फौज़ के आने की आहट

पाकिस्तान से आने वाली ख़बरें चिंता पैदा कर रही हैं. किसी आम आदमी से बात हो रही हो या पत्रकार से, सांसद से या नौकरशाह से, बस एक बात कही जा रही है कि यहां के हालात अच्छे नहीं हैं. कितने अच्छे नहीं हैं, उसके जवाब में कहा जाता है कि बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि बहुत ख़राब हैं.

महंगाई आसमान से भी ऊपर जा रही है और बहुत सी जगहों पर रोटी और अनाज के लिए दंगे हो रहे हैं. आम आदमी परेशान है और उसकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं. बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है. इसका सबसे बड़ा असर वहां की क़ानून व्यवस्था पर पड़ा है. छीनाझपटी बढ़ रही है और चोरी व डकैती की ख़बरें आम हो गई हैं. बेरोज़गार नौजवानों को लगता है कि नौकरी या काम न मिलने की हालत में चोरी डकैती, रोज़ी-रोटी का आसान रास्ता है. पुलिस के पास समय नहीं है कि लोगों को पकड़े या फिर उसकी साख इतनी गिर गई है कि कोई उसे भाव ही नहीं दे रहा है.

पाकिस्तान की पुलिस की हालत भारत की पुलिस से भी ख़राब है. आज़ादी के बाद वहां की पुलिस की ट्रेनिंग नए सिरे से हो, इसका फ़ैसला वहां के शासन ने नहीं लिया. छोटा देश और नया देश होने के नाते, उनके पास एक बड़ा मौक़ा था जिसे वहां की सरकार ने गंवा दिया. आज वहां की पुलिस के पास न नई ट्रेनिंग है और न ही मानवीयता, बल्कि वह वहां के सामंती तबके के हितों की पहरेदार बन गई है. वहां ज़्यादती का शिकार थाने में इसीलिए नहीं जाता कि क्योंकि उसे डर है कि उस पर और ज़्यादती होगी.

पाकिस्तान में, वहां की सरकार का, उसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात का, वहां के प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ रहा. सभी को लगता है कि यह सरकार आज है, कल नहीं होगी. प्रधानमंत्री युसूफ रज़ा गिलानी पीर साहब कहलाते हैं, वह अभी भी कुछ ख़ास मिलने वालों को गंडा ताबीज़ देते हैं. उनके खानदान में पीरी मुरीदी का सिलसिला चलता आ रहा है और वह इसे बढ़ा रहे हैं. वह आए थे राष्ट्रपति ज़रदारी के नुमाइन्दे बन कर, लेकिन अब उन्होंने अलग सत्ता केंद्र बना लिया है. पाकिस्तानी प्रशासन में सीधा बंटवारा दिखाई दे रहा है.

पाकिस्तानी राष्ट्रपति ज़रदारी को कभी भी जनसमर्थन हासिल नहीं रहा. बेनज़ीर भुट्टो अपनी लड़ाकू छवि और समझदार महिला की छाप की वजह से पाकिस्तान में हमेशा विकल्प के तौर पर देखी जाती रहीं. नवाज़ शरीफ भी इसी नज़र से देखे जाते रहे पर इसमें उनके पंजाबी होने का बड़ा हाथ रहा. पाकिस्तान की पूरी राजनीति पर पंजाब का हमेशा से दबदबा रहा है और सारे प्रमुख विभाग पंजाब से रिश्ता रखने वाले लोगों के पास ही रहे हैं. बेनज़ीर भुट्टो की हत्या के बाद भी लोग नहीं चाहते थे कि ज़रदारी प्रधानमंत्री बनें, इसीलिए गिलानी प्रधानमंत्री बने और एक चालाक समझौते के तहत ज़रदारी राष्ट्रपति बने. ज़रदारी पाकिस्तान के प्रशासन को चुस्त बनाने और वहां के लोगों में उत्साह भरने में बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं. इसीलिए आज पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है.

अमेरिका से मिलने वाली सहायता का इस्तेमाल पाकिस्तान में विकास के किसी प्रोग्राम में नहीं हो रहा है. न वहां अस्पताल हैं, न स्कूल-कॉलेज. बड़े शहरों को, जैसे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को छोड़ दें, तो देहाती क्षेत्र भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा बुरी हालत में हैं. यहां तो फिर भी कुछ आवाज़ इस स्थिति के ख़िलाफ़ राजनैतिक दलों और अख़बारों में उठ जाती है पर पाकिस्तान में तो इसकी झलक भी नहीं मिलती. पाकिस्तान में विपक्ष नाम की कोई ताक़त है ही नहीं.

शायद पाकिस्तान में शासन करने वालों को भी लगने लगा है कि अगले दो महीने उनके और फौज़ के बीच की दूरी को कम कर उन्हें वहां से हटा सकते हैं. पाकिस्तान की फौज़ लोकतांत्रिक नहीं है, वह केवल फौज़ है और उसे नागरिक शासन करने का स्वाद पता है. भारत के लिए पाकिस्तान में फौज़ का आना काफी ख़राब होगा. इसके बाद आतंकवाद तो बढ़ेगा ही कुछ दूसरी समस्याएं भी बढ़ जाएंगी. अमेरिका क्या चाहेगा यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तानी सेना से उसके सीधे संबंध हैं.

दहशतगर्दी या आतंकवाद का शिकार पाकिस्तान भारत से ज़्यादा है. वहां के आतंकवादी संगठनों को लगने लगा है कि पाकिस्तान की सरकार को अपने असर में लेना ज़्यादा आसान है. भारत में तो वे अपनी कार्यवाही शायद प्रैक्टिस की योजना के तहत कर रहे हैं. उनके नए नए आदेशों की वजह से पाकिस्तान का नागरिक अपने बच्चों और बच्चियों के न केवल भविष्य, बल्कि उनकी जान को लेकर भी चिंतित रहता है. बहुतों को डर लगा रहता है कि सुबह उनके घर से निकला लड़का या लड़की शाम को वापस आएगा भी या नहीं. पाकिस्तान की सरकार इस निराशा से नहीं लड़ पा रही है.

लोग मांग करने लगे हैं कि इससे अच्छी तो सेना थी. यह मांग वहां बढ़ रही है और लोकतंत्र के लिए ख़तरा पैदा कर रही है. लोकतंत्र के नाम पर शासन करने वाले लोग लूट तंत्र और दमन तंत्र की रक्षा करने वाले बन गए हैं. आज पाकिस्तान में फौज़ के आने की आहट सुनाई देने लगी है. सितम्बर तक इसका ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज़ अगर कुछ करना चाहेगी तो उसके पास जुलाई और अगस्त अच्छे मौक़े हैं. भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की पाकिस्तान की कोशिश को मैं इसी रोशनी में देखता हूं, क्योंकि विदेश सचिव, गृहमंत्री के साथ पाकिस्तान सरकार की न केवल बातचीत बल्कि उसकी बाद की प्रतिक्रिया भी स्वागत योग्य मानी जानी चाहिए.

शायद पाकिस्तान में शासन करने वालों को भी लगने लगा है कि अगले दो महीने उनके और फौज़ के बीच की दूरी को कम कर उन्हें वहां से हटा सकते हैं. पाकिस्तान की फौज़ लोकतांत्रिक नहीं है, वह केवल फौज़ है और उसे नागरिक शासन करने का स्वाद पता है. भारत के लिए पाकिस्तान में फौज़ का आना काफी ख़राब होगा. इसके बाद आतंकवाद तो बढ़ेगा ही, कुछ दूसरी समस्याएं भी बढ़ जाएंगी. अमेरिका क्या चाहेगा यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना से उसके सीधे संबंध हैं. सेना भी अमेरिका को वो सारी जानकारियां देती है जो वह अपनी सरकार को भी नहीं देती. लेकिन सेना की महत्वाकांक्षा भी अमेरिकी दबाव को अस्वीकार कर सकती है क्योंकि यदि नागरिकों का गुस्सा अपनी अक्षम सरकार के ख़िलाफ़ बढ़ता है और उसे दहशतगर्दी महंगाई, बेकारी, क़ानून व्यवस्था जैसी स्थितियों से और दो चार होना पड़ता है तो फिर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सितम्बर से पहले हमें पाकिस्तान में मार्शल लॉ देखने के लिए दिमाग़ बना लेना चाहिए, हालांकि हमारी मालिक से प्रार्थना है कि वह पाकिस्तान में ऐसा न होने दे.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

टूट कर बिखर जाएगा पाकिस्तान

कुछ दिन पहले की बात है. ओकारा शहर के एक पुलिस थाने के सामने लोगों का हुजूम जमा हुआ. हुजूम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं. थोड़ी देर बाद यह हुजूम थाने के अंदर पहुंचा और दो पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. थाने में मौजूद अन्य पुलिस वालों ने उन्हें मरने से तो बचा लिया, लेकिन पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ऐसी घटनाएं कराची में भी हुई हैं जहां लोगों ने संदिग्ध अपराधियों को ज़िंदा आग के हवाले कर दिया. अराजकता के और भी संकेत देश के अलग-अलग हिस्सों से मिल रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में पंजाब से कम से कम दो ऐसी ख़बरें आई हैं जिसमें माता-पिता ने पहले अपने बच्चों की हत्या कर दी फिर अपनी भी जान दे दी. लाहौर से एक रिक्शावाले के बारे में हैरतअंगेज़ ख़बर मिली, जिसने अपनी पत्नी और तीन बेटियों के साथ मौत का क़रार किया था. उसकी सबसे बड़ी बेटी तेरह साल की थी, लेकिन परिवार की माली हालत इतनी ख़राब थी कि मौत के सिवा दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं था.

इन ख़बरों को लेकर सरकार का रवैया बिल्कुल संवेदनहीन रहा है. सूचना मंत्री ने कहा कि आत्महत्याएं विकसित देशों में भी होती हैं. उन्हें यह मानने में थोड़ी भी हिचक नहीं हुई कि ग़रीबी से लड़ने में सरकार बेबस है. उन्होंने लोगों को यह सलाह भी दी कि यदि वे अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते तो उन्हें पाकिस्तान बैतूल माल के हवाले कर दें. उनके साथ खड़े बैतूल माल के डायरेक्टर जेनरल ने हंसते हुए बताया कि स्वीट होम्स के नाम से ऐसे बच्चों के लिए पूरे देश में पंद्रह केंद्र खोले गए हैं. ऐसे बयान सुनने में कतई अच्छे नहीं लगते, बल्कि दिल में तीखे दर्द का एहसास होता है. यदि यह सरकार ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर सकती, तो इसके बने रहने का औचित्य क्या है, अपने बच्चों को अनाथालय जैसी संस्थाओं में भेजने की सलाह देने का क्या मतलब है? सरकारी पक्ष ने जनसंख्या नियंत्रण के विकल्प की चर्चा तक नहीं की. सूचना मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हम मंत्रियों के राजसी ठाट-बाट के बारे में सुन रहे हैं. सरकारी कामकाज में भाई-भतीजावाद और घोर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (पाकिस्तान) ने बताया है कि सेना और प्रशासन यदि सरकारी ख़रीद में नियम-कायदों का पालन करे तो करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं जिसका विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है. देश लगातार अराजकता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, इसके कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं. यह कोई नई बात नहीं, बल्कि यह प्रक्रिया सालों से चली आ रही है.

कुव्यवस्था का पहला परिणाम यही होता है कि क़ानून का शासन ख़तरे में पड़ जाता है. आज पाकिस्तान की हालत यह है कि साधन संपन्न लोग अपनी मर्जी की हांकने के लिए स्वतंत्र हैं. एक ताज़ा ख़बर के मुताबिक़ रिनाला खुर्द के एक जमींदार ने 40 ईसाइयों को अपने गांव में केवल इसलिए बंधक बना कर रख लिया क्योंकि उसकी बेटी एक इसाई लड़के के साथ भाग गई थी. जमींदार के गुर्गों ने इन सभी ईसाइयों को घर के अंदर जला देने की धमकियां भी दीं.

देश के उत्तर में हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें कई लोगों की राय में जीत हासिल करना नामुमकिन है. इस लड़ाई में हमारी सेना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मुक़ाबला कर रही है, जो गुरिल्ला पद्धति में पारंगत हैं. तालिबान के प्रभाव वाले इलाक़ों से क्रूरता की ऐसी ख़बरें आ रही हैं जिन पर सहज विश्वास भी नहीं किया जा सकता. तालिबान की क्रूरता का शिकार हुए ओरक्जाई के तीन युवक हाल तक कोहट अस्पताल में पड़े हुए थे. आतंकियों ने भरे बाज़ार में इनके हाथ काट दिए थे. ग़रीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले इन युवकों की सूनी आंखों में केवल एक सवाल है, किस क़ानून के तहत उनके हाथ काटे गए हैं और इसकी भरपाई कौन करेगा. तालिबान ने केवल उनका हाथ ही नहीं काटा, बल्कि उन्हें इस लायक़ नहीं छोड़ा कि वे कोई काम कर सकें और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें. उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. ख़बरों पर भरोसा करें तो सरकार की ओर से उनसे मुलाक़ात करने तक कोई नहीं गया.

देश के दूसरे हिस्सों में आतंकी तत्व छोटे बच्चों को अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं जिन्हें भविष्य में आत्मघाती हमलावरों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. ख़बरें बताती हैं कि आतंकी छह साल की छोटी उम्र के बच्चों को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं. ग़रीबी के मारे लोग अपने बच्चों को आतंकी संगठनों के हाथों या मज़दूरी के लिए बेचने को मजबूर हैं. जवान लड़कियों को वेश्यालय और कोठों पर भेजा जा रहा है. देश से बाहर जाने के लिए आतुर युवा दलालों को मुंहमांगी रकम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिलता है. आम नागरिकों को लगता है देश में उनके लिए सोचने वाला, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और न्यायिक तंत्र तक उनकी पहुंच नहीं है. भीड़ के हिंसक हो जाने की वारदातों के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है.

संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा पाकिस्तान में खाद्य सुरक्षा पर जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक़ देश की 48 प्रतिशत अर्थात क़रीब आधी जनसंख्या खाद्य सुरक्षा से महरूम हैं. 170 मिलियन की आबादी वाले देश के लिए यह बहुत बड़ी संख्या है. मजारों पर मुफ्त बंटते चावल के लिए मची मारामारी और कबाड़ में भोजन की तलाश करते ग़रीब बच्चों की तस्वीरों के सामने धनी लोगों की वैभवशाली जीवनशैली की तस्वीरें वीभत्स लगती हैं. हालात में बदलाव की हमारी कोशिशें अब तक ग़रीबों तक नहीं पहुंच पाई हैं और कोई आश्चर्य नहीं कि हम बर्बादी की कगार पर खड़े हैं. फॉरेन पॉलिसी मैग्जीन द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम एक बार फिर विश्व के दस सबसे कम सफलतम राष्ट्रों में शामिल है. आतंकवाद के चलते चारों ओर फैली कुव्यवस्था इसकी सबसे बड़ी वजह है. आतंकवाद को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा कारण ग़रीबी है, जबकि ग़रीबी के मूल में प्रशासनिक अक्षमता और आम जनों की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्धता का नितांत अभाव है.

कुव्यवस्था का पहला परिणाम यही होता है कि क़ानून का शासन ख़तरे में पड़ जाता है. आज पाकिस्तान की हालत यह है कि साधन संपन्न लोग अपनी मर्जी की हांकने के लिए स्वतंत्र हैं. एक ताज़ा ख़बर के मुताबिक़ रिनाला खुर्द के एक जमींदार ने 40 ईसाइयों को अपने गांव में केवल इसलिए बंधक बना कर रख लिया क्योंकि उसकी बेटी एक इसाई लड़के के साथ भाग गई थी. जमींदार के गुर्गों ने इन सभी ईसाइयों को घर के अंदर जला देने की धमकियां भी दीं. हिंसा की ऐसी ख़बरें दूसरे इलाक़ों से भी आ रही हैं. धनी लोग यह जानते हैं कि वह हत्या जैसा अपराध करने के बाद भी आसानी से बच निकलने में कामयाब हो सकते हैं. पैसे की ताक़त की कोई सीमा नहीं होती. ग़रीबों को अक्सर बेवजह ही दंडित होना पड़ता है, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता है.

इस कुव्यवस्था के दुष्चक्र से हम कैसे निजात पा सकते हैं, यह कहना मुश्किल है. एक तूफ़ान सरकार और समाज के लिए आवश्यक कई संस्थाओं को पहले ही उड़ा चुका है और अब बाकी बचे ढांचे को भी पूरी तरह ख़त्म करने के लिए तैयार हो रहा है. हर जगह अपराधियों ने आतंकियों के साथ हाथ मिला लिए हैं. देश के कई हिस्सों में उनका राज चलता है और आम जनता इन इलाक़ों में पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकती. हालात में सुधार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है. लेकिन मौजूदा माहौल को देखते हुए यह कल्पना करना भी असंभव है कि सरकार बिना किसी सहयोग के अपने दम पर कुछ ख़ास कर सकती है. सरकार के अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति भी नज़र नहीं आती. यह सहयोग आम जनता की ओर से होना चाहिए था, लेकिन निराशा की बात यह है कि समाज का कोई संगठन ऐसा करने की हालत में नहीं है, न ही किसी राजनीतिक दल के पास यह क्षमता है. ज़रूरत इस बात की है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसके लिए संगठित होकर पहल करें. छात्रों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऐसे संगठन दूसरे देशों में भी बनते रहे हैं. अभिजात्य वर्ग को बदलाव के लिए तैयार करने में इस वर्ग को एक अहम भूमिका निभानी ही होगी. यदि हालात को अपने हाल पर छोड़ दिया गया तो इस देश में रहने वाले हरेक इंसान का अस्तित्व ख़तरे में होगा.

हयात के.
feedback@chauthiduniya.com

गायिका चेरिल कोल के डिंपलों से प्रेरित होकर कई महिलाएं डिंपलीप्लास्टी (कृत्रिम डिंपल बनाने केलिए होने वाली प्लास्टिक सर्जरी) को अपना रही हैं.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

कब करें आयोग में शिकायत

पिछले अंक में हमने आपको द्वितीय अपील के बारे में बताया था. इस बार हम आपको बताते हैं कि आरटीआई क़ानून के तहत शिक़ायत का क्या अर्थ होता है. शिक़ायत कब, कहां और कैसे दाख़िल की जाती है. दरअसल, अपील और शिक़ायत में एक बुनियादी फ़र्क़ है. कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको ग़लत दे दिया जाता है और आपको पूर्ण विश्वास है कि जो जवाब दिया गया है वह ग़लत, अपूर्ण या भ्रामक है. इसके अलावा, आप किसी सरकारी महकमे में आरटीआई आवेदन जमा करने जाते हैं और पता चलता है कि वहां तो लोक सूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं किया गया है. या फिर आपसे ग़लत फीस वसूली जाती है. तो, ऐसे मामलों में हम सीधे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में शिक़ायत कर सकते है. ऐसे मामलों में अपील की जगह सीधे शिक़ायत करना ही समाधान है. आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को एक लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको कोई जानकारी देने से मना किया गया है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग, जैसा मामला हो, में अपनी शिक़ायत दर्ज करा सकते हैं.

सूचना क़ानून की धारा 18 (1) के तहत यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, कि वे एक व्यक्ति से शिक़ायत स्वीकार करें और पूछताछ करें. कई बार लोग केंद्रीय सूचना लोक अधिकारी या राज्य सूचना लोक अधिकारी के पास अपना अनुरोध जमा करने में सफल नहीं होते, जैसा भी मामला हो. इसका कारण कुछ भी हो सकता है, उक्त अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के तहत नियुक्त न किया गया हो, जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के तहत अग्रेषित करने के लिए कोई सूचना या अपील के लिए उनके आवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया हो, जिसे वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास न भेजें या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग में अग्रेषित न करें, जैसा भी मामला हो.

- जिसे इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी तक पहुंच देने से मना कर दिया गया हो. ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना के लिए अनुरोध या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो.
- जिसे शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसे वह अनुपयुक्त मानता/मानती है.
- जिसे विश्वास है कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है.
- इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने या अनुरोध करने से संबंधित किसी मामले के विषय में.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

सूचना आयोग के पते/फोन नं.

केंद्रीय सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
वलब बिल्डिंग
ओल्ड जेएनयू कैंपस
बेर सराय, नई दिल्ली-67
011-26717354
www.cic.gov.in

बिहार राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
चौथा तल, सूचना भवन
(नए सचिवालय के सामने)
पटना-1
0612-2235466

झारखंड राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
इजीनियर हॉस्टल
धुर्वा, रांची
09431364947
फैक्स-0651-2401418

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
बी-22, छर इमली
भोपाल
0755-2761366/2761367

छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
निर्मल छाया भवन
मीरा दातर रोड
नियर बॉटली हाउस ,
शंकर नगर, रायपुर
0771-4014406
फैक्स-0771-2442132

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
छठा तल, इंदिरा भवन
लखनऊ
0522-2288598/2288600

उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
सैक्टर 1, सी-10
डिफेंस कॉलोनी
देहरादून
0135-2666778

ज़रा हट के

समलैंगिक पुरुष बोले तो तेज़ दिमाग़

आमतौर पर समलैंगिक पुरुषों का नाम सुनते ही लोगों के मन में न जाने क्या-क्या विचार उत्पन्न होने लगते हैं. सभी लोग उन्हें हेय दृष्टि या फिर उपेक्षा की नज़रों से देखते हैं. लोग भले ही उन्हें उपेक्षा की नज़रों से देखें, लेकिन उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जिसकी तारीफ़ करते लोग नहीं थकते जैसे उनका दिमाग अमूमन आम लोगों की तुलना में ज़्यादा तेज़ होता है. यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसका खुलासा एक शोध में किया गया है.

समलैंगिक पुरुष परिचितों के चेहरे तेज़ी से और अधिक सटीकता से याद रख सकते हैं. एक नए अध्ययन के मुताबिक महिलाओं की तरह ही समलैंगिक पुरुष मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं. यॉर्क विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सहायक प्रोफेसर व अध्ययनकर्ता जेनीफर स्टीव्स ने अध्ययन में चेहरे पहचानने की क्षमता पर लिंग के प्रभाव और यौन अभिविन्यास का अध्ययन किया था. उन्होंने बताया कि चेहरों को पहचानने में समलैंगिक पुरुष विषमलिंगी महिलाओं की तरह ही अपने मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं. विषमलिंगी पुरुष इसके लिए मस्तिष्क के दाएं हिस्से का ही इस्तेमाल करते हैं.

स्टीव्स ने कहा, हमारे परिणाम बताते हैं कि समलैंगिक पुरुष और विषमलिंगी महिलाएं चेहरे पहचानने में मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं. इससे संग्रहित जानकारी तेज़ी से मिलने लगती है. अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों को 10 चेहरों की तस्वीरें दिखाकर उन्हें याद रखने और उन्हें 50 अन्य चेहरों में से पहचानने के लिए कहा गया था. प्रतिभागियों को केवल कुछ मिली सेकेंड के लिए ही ये तस्वीरें दिखाई गई थीं. गौरतलब है कि ये सभी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट थी.

आर्टिफिशियल डिंपल... न बाबा न

डिंपल गर्ल के नाम से मशहूर बॉलीवुड तारिका प्रिती जिंटा की अदाओं के तो क्या कहने, जब वह हंसती हैं तो ख़ूबसूरती उनके चेहरे से झलकती है और उनके चेहरे का डिंपल तो मानों इसमें चार चांद लगा देता है. इसे देख कर हुस्न के कद्रदान आह भरते नज़र आते हैं. वैसे तो ख़ूबसूरत दिखने की चाह में लोग जाने क्या-क्या नहीं करते हैं. ख़ासकर महिलाएं तो इस रेस में सबसे आगे रहती हैं. लिहाज़ा महिलाओं का रुझान आर्टिफिशिल डिंपल की तरफ़ बढ़ रहा है, लेकिन ख़ूबसूरती के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा बनवाए जाने वाले कृत्रिम डिंपल आगे चलकर आपकी सुंदरता के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं. ब्रिटेन के कॉस्मेटिक शल्य चिकित्सकों ने महिलाओं को कृत्रिम रूप से डिंपल बनवाने के प्रति आगाह करते हुए इसे न अपनाने का अनुरोध किया है.

गायिका चेरिल कोल के डिंपल से प्रेरित होकर कई महिलाएं डिंपलीप्लास्टी (कृत्रिम डिंपल बनाने केलिए होने वाली प्लास्टिक सर्जरी) को अपना रही हैं. पिछले कुछ महीनों में इसे अपनाने वाली महिलाओं की संख्या में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

हालांकि चिकित्सकों की सलाह है कि लोगों को इस प्रक्रिया से बचना चाहिए. वेबसाइट हेराल्ड सन डॉट कॉम डॉट एयू के मुताबिक़ उम्र बढ़ने के साथ त्वचा का लचीलापन कम होने लगता है. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ यह डिंपल कैसे दिखेंगे. उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि कुछ सालों में ये भयानक भी दिख सकते हैं.

इस प्रक्रिया की एक और ख़ामी यह है कि इस तरह के डिंपल चेहरे पर हमेशा बने रहते हैं जबकि जो प्राकृतिक डिंपल होते हैं, वे हंसने के दौरान ही दिखते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 12 जुलाई –18 जुलाई 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
स्वास्थ्य के लिहाज़ से लंबे समय से चल रही बीमारियों से मुक्ति मिलेगी. नौकरीपेशा वर्ग के लिए इस सप्ताह कुछ मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. प्रेम/विवाह/निजी संबंध में विश्वास की कमी तनाव का कारण बन सकता है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
करियर की दृष्टि से यह सप्ताह बेहतर रहेगा. दमा, अस्थमा के मरीजों के लिए परेशानियां हो सकती हैं. पुराने मित्र क़ानूनी अड़चनों को दूर करने में ख़ासे मददगार साबित होंगे. अपने आस-पास चाटुकार प्रवृत्ति के लोगों से बचकर रहें अन्यथा अपव्यय के शिकार हो सकते हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
धन की समस्या बनी रहेगी. पारिवारिक सुख के लिहाज़ से समय अच्छा है. शौक को करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. लंबी दूरी की यात्राओं से परहेज रखें तो बेहतर है. वाहन चलाने में भी सावधानी अपेक्षित है अन्यथा दुर्घटना हो सकती है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता हैं. अपने और परिजनों के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें. अध्यापन, लेखन, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. किसी ख़ास परिजन से अरसे बाद मिलने की संभावना है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
व्यापारियों के लिए यह समय आगे की योजना बनाने के लिए उचित है. नौकरीपेशा वर्ग के लिए कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार अपेक्षित है. छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. नए रिश्ते बनेंगे और फायदेमंद भी होंगे.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
मानसिक एवं शारीरिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं. छात्रों को भी परीक्षाओं में आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने से निराशा हो सकती है. व्यापारियों को भी कारोबार में कुछ सुधार के लक्षण दिखाई देंगे. पुराने क़र्ज़ वापस पाने में सफल हो सकते हैं.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
दिल की बीमारियों के शिकार लोगों के लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद समय अनुकूल रहेगा. लंबी दूरी की यात्राओं से परहेज करें, दुर्घटना हो सकती है. खाने-पीने और वाहन चलाते समय भी सावधानी अपेक्षित है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस हफ्ते पेट और दिल की बीमारियां थोड़ा परेशान कर सकती हैं. एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करें, सफलता ज़रूर मिलेगी. इस हफ्ते ख़ुशनुमा एहसास लेकर कोई ज़िंदगी में आएगा और आप अंजाने में ही इसकी गिरफ़्त में आ सकते हैं.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है. मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं. लंबी यात्राओं से दूर रहना ही बेहतर होगा. शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हों तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
यह सप्ताह परेशानियों से राहत दिलाने वाला हो सकता है. लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात मिलेगी. अपने खाने-पीने का उचित खयाल रखें. भाग्य के सहयोग से नए मौक़े आपके हाथ आएंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
विद्यार्थियों को अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने के लिए ज़्यादा प्रयास करने होंगे. इस दौरान होने वाली परीक्षाओं में भी सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है. परिवार में भाई-बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकता है, अपने व्यवहार पर अंकुश रखें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
खान पान का स्तर ऊंचा रहेगा, सामाजिक समारोह में खान-पान का ख़ूब लुत्फ लेने का मौक़ा मिलेगा. सप्ताह के आखिर में बुखार, जुकाम और पेट संबंधी बीमारियां सिर उठा सकती हैं. कार्य स्थान में छोटी-छोटी उलझनें आ सकती हैं.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

एक अच्छी बात यह देखने को मिली कि एएलपी द्वारा नए प्रधानमंत्री के लिए गिलार्ड के नाम को मंजूरी देने के कुछ घंटों के अंदर ही स्टॉक बाज़ार में 16 अंकों का उछाल आया और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी मज़बूत हुआ.

बदले परिवेश में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

डॉ. आशुतोष मिश्रा

गुरुवार की उस सुबह को ऑस्ट्रेलिया अपनी फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने के सदमे से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था, राजधानी कैनबरा में एक अलग ही खेल चल रहा था. एक आश्चर्यजनक और पल-पल बदलते घटनाक्रम के साथ प्रधानमंत्री केविन रूड की सत्ता से विदाई के बाद ही यह खेल ख़त्म हुआ. सत्ता के गलियारे में खेले गए इस खेल में ऐसी कई चीजें थीं, जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हुई थीं. मंदारिन भाषी केविन रूड देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिसे अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो चार साल तक उनके साथ उप प्रधानमंत्री रही जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं. इतना ही नहीं, गिलार्ड को शपथ दिलाने वाली गवर्नर जेनरल क्वेंटिन ब्राइस भी देश की पहली महिला गवर्नर जनरल हैं. वित्त मंत्री वायने स्वेन को नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया.

केविन रूड ने गुरुवार सुबह को अपनी ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी (एएलपी) के सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया. पिछले कुछ सप्ताहों में उनकी लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही थी और 30 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी. पार्टी सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श का मक़सद भी यही था, इससे निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए. लेकिन इस बैठक में रूड को यह भान हो गया कि पार्टी के अंदर भी उन्हें ज़्यादा समर्थन हासिल नहीं है. अपनी हार निश्चित देख उन्होंने मतदान के बजाय पद छोड़ने का प्रस्ताव रखा. प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मीडियाकर्मियों से पहली बार बात करते हुए गिलार्ड ने यही कहा कि एक अच्छी सरकार अपने रास्ते से भटकती जा रही थी और उन्हें स्थिति पर नियंत्रण के लिए आगे आना पड़ा. साथ ही यह भी कि रूड की सरकार कई बार ज़रूरी फ़ैसले लेने से चूक गई और अपने रास्ते से भटक गई. गिलार्ड के इस कड़े बयान से विपक्षी पार्टियों द्वारा रूड सरकार की नीतियों का तीखा विरोध समझ में आता है, हालांकि ख़ुद गिलार्ड भी इस सरकार के शीर्ष नेताओं में शामिल थीं.

हालांकि, नए घटनाक्रम के बाद विपक्षी पार्टियों के रुख़ में कोई बदलाव आएगा, ऐसा नहीं दिखता. विपक्ष के नेता टोनी एबॉट ने कहा, लेबर पार्टी ने अपने नेता को भले त्याग दिया हो, नीतियों को नहीं त्यागा है. उसने केवल अपना सेल्समैन बदला है, उत्पाद पुराने ही हैं. यदि आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं, तो इस सरकार को बदलना होगा. उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि गिलार्ड रूड से अलग होंगी, इसकी उम्मीद कोई न करे. न्यू साउथ वेल्स की लेबर माफिया ने एक चुने हुए प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदख़ल करने का यह घिनौना खेल खेला है, यह एक वीभत्स हत्या है. एएलपी की वेबसाइट पर भी लगातार नए मैसेज मिल रहे थे, मसलन हम अपना वोट वापस लेना चाहते हैं. यह घिनौना है. रूड को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है, यह विश्वसनीय नहीं लगता. अपने मार्मिक विदाई भाषण में रूड ने पिछले चार साल की उपलब्धियां गिनाई. अपनी पत्नी और बच्चों से घिरे रूड भाषण के दौरान कई बार रो पड़े. प्रधानमंत्री जैसे बड़े ओहदे को छोड़ते समय नेता अक्सर एक भावपूर्ण और मार्मिक भाषण देते हैं, लेकिन रूड की तरह सार्वजनिक रूप से रोते हुए शायद ही कोई और नज़र आया हो. प्रधानमंत्री के रूप में रूड की दो बड़ी उपलब्धियों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, पहला तो वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को सहेज कर रखना, जिसके लिए रूड ने वित्तीय संस्थाओं के साथ सख्ती का रवैया अपनाया और पैकेजों की घोषणा कर क़रीब पांच लाख लोगों को बेराज़गार होने से बचा लिया. यदि ऐसा हो जाता तो ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था मंदी के प्रकोप से बच नहीं पाती. दूसरा, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक बाद रूड ने ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों के पूर्वजों से माफ़ी मांगी थी. उनका यह अनोखा क़दम वास्तव में ऐतिहासिक है.

टोनी एबॉट की अगुआई में विपक्ष जूलिया गिलार्ड के नए नेतृत्व से मुक़ाबला करने के लिए रणनीति तो बना रहा है, लेकिन दोनों पक्षों को यह पता है कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होनेवाले हैं और उन्हें चुनाव के मैदान में उतरना होगा. नई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड के लिए सबसे बड़ी चिंता सरकार और पार्टी की लगातार घटती लोकप्रियता पर लगाम कसना है तो उन्हें उन ग़लतियों को भी ठीक करना होगा, जिसके चलते रूड की सरकार का पतन हो गया. दो ऐसे मुद्दे हैं जिनपर उन्हें तत्काल और नए नज़रिए से फ़ैसला लेना होगा. पहला, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम और कार्बन प्राइसिंग को संसद की मंजूरी दिलाना और दूसरा, 40 प्रतिशत सुपर माइनिंग टैक्स का मामला जिसके चलते पूरा माइनिंग उद्योग रूड की सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था. मीडियाकर्मियों से बातचीत में गिलार्ड ने ख़ुलासा किया कि वह माइनिंग उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत को तैयार हैं. उन्होंने टैक्स के समर्थन में दिखाए जा रहे विज्ञापनों को भी वापस लेने की घोषणा की और उम्मीद जताई की माइनिंग उद्योग भी ऐसा ही करेगा और खुले नज़रिए के साथ आगे आएगा. हालांकि, यह अच्छे संकेत हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों के इस दावे से सच्चाई झलकती है कि गिलार्ड रूड की नीतियों में ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगी.

एक अच्छी बात यह देखने को मिली कि एएलपी द्वारा नए प्रधानमंत्री के लिए गिलार्ड के नाम को मंजूरी देने के कुछ घंटों के अंदर ही स्टॉक बाज़ार में 16 अंकों का उछाल आया और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी मज़बूत हुआ. मीडिया के साथ बातचीत में गिलार्ड एक दमदार और निर्णय लेने में सक्षम नेता के रूप में सामने आई. नीतिगत फ़ैसलों के मामले में रूड अक्सर अपने पार्टीजनों, यहां तक कि मंत्रियों के विचारों की भी अनदेखी कर देते थे, गिलार्ड का रवैया इससे अलग नज़र आया. रूड के विपरीत वह सबको विश्वास लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध नज़र आईं. 1998 से लेकर अब तक का उनका संसदीय अनुभव भी सबको साथ लेकर चलने के रवैये की तस्दीक करता है, लेकिन यह देखना रोचक होगा कि अपनी इस छवि को वह कहां तक सहेज कर रख पाती हैं. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आनेवाले कुछ दिनों में गिलार्ड को क्लाइमेट चेंज, सुपर माइनिंग टैक्स, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा और ख़ुद एएलपी में अंदरूनी सुधार जैसे मुद्दों पर कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है.

संभावना जताई जा रही है कि पार्टी के सहयोगियों और गवर्नर जनरल से विचार-विमर्श के बाद गिलार्ड अगले 2-3 महीनों में चुनावों की घोषणा कर सकती हैं और अक्टूबर-नवंबर तक नए प्रधानमंत्री एवं नई सरकार का स्वरूप तय हो जाएगा. गिलार्ड के लिए राहत की बात यह है कि पद छोड़ते समय केविन रूड की लोकप्रियता काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन टोनी एबॉट से वह फिर भी आगे थे. गिलार्ड को रूड से ज़्यादा समर्थन ज़रूर मिलेगा. लेकिन वह शिक्षा क्षेत्र में क्रांति के नाम पर 16 बिलियन से ज़्यादा के घोटाले के ठीक बाद प्रधानमंत्री बनी हैं. फिर वह रूड की उसी सरकार का एक अहम हिस्सा थीं, जो ख़ुद की उन्हीं के मुताबिक़ कई बार अपने रास्ते से भटक गई. वह चाहकर भी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की असफलताओं से ख़ुद को पूरी तरह अलग नहीं कर सकती.

अहम सवाल यह है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के लिहाज़ से जूलिया गिलार्ड का प्रधानमंत्री बनना कितना महत्वपूर्ण है. रूड के शासनकाल के दौरान दोनों देशों के बीच व्यवसायिक संबंध मज़बूत हुए और निवेश में वृद्धि हुई, तो दूसरी ओर कई घटनाओं के चलते संबंधों में खटास भी आई. पहले हरभजन सिंह विवाद, फिर यूरेनियम की सप्लाई से इंकार करने और हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हुए बार-बार हमलों के चलते रिश्तों में तनाव पैदा होता रहा. गिलार्ड रूड की तरह मंडारिन भाषी नहीं हैं और भारत अच्छे संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत की उम्मीद कर सकता है. वह यह उम्मीद कर सकता है कि नई सरकार में उसकी चिंताओं पर पहले से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा.

चीन के साथ संबंधों को ज़्यादा तवज्जो देने के रूड की नीति के चलते उनके शासनकाल में दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ा और एक सौ मिलियन डॉलर के निवेश के साथ ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में नए चाइना सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी मिली. जूलिया गेलार्ड ने मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया-इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए 8 मिलियन देने की ही घोषणा की, लेकिन धन की मात्रा से ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहां गिलार्ड का उत्साहवर्द्धक रवैया है और नई दिल्ली के लिए यह राहत की बात है. इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई तो पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार, निवेश, कूटनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में नए शोध को बढ़ावा देने के इंस्टीट्यूट के घोषित उद्देश्य को भी रेखांकित किया.

भारतीय छात्रों के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते नस्लीय हमलों के कारण जब दोनों देशों के संबंध बहुत ख़राब हो गए थे तो गिलार्ड ने सितंबर 2009 में पांच दिनों का भारत दौरा किया था और विश्वास बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई शीर्ष नेताओं से मुलाक़ात की थी. भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर कॉमनवेल्थ और विक्टोरिया सरकार द्वारा उठाए गए क़दमों के बारे में मीडिया को बताते वह ज़्यादा विश्वसनीय भले न लगी हों, लेकिन उनके इस पांच दिवसीय दौरे ने यह ज़रूर बता दिया कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को वह कितना महत्व देती हैं. यदि वह अगामी चुनावों के बाद फिर से प्रधानमंत्री चुन ली जाती हैं तो भारत के लिए सबसे अहम बात यही होगी कि वह यूरेनियम के सप्लाई से मना करने के केविन रूड के फ़ैसले को बदलती हैं या नहीं. एएलपी की अब तक की विचारधारा पर नज़र डालें तो यह तब तक संभव नहीं दिखता जब तक कि भारत एनपीटी पर दस्तखत न करे. हालांकि, कूटनीतिक गलियारों और व्यवसायिक हलकों में ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगली सरकार फिर से लेबर पार्टी की ही बनेगी और संभव है कि नई सरकार आदर्शवादिता के बजाय प्रगतिवादिता को अपना सकती है. यदि ऐसा हुआ तो यूरेनियम के निर्यात को मंजूरी मिल सकती है. भारत के प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा लंबे समय से अपेक्षित है. यदि यह यात्रा मौजूदा माहौल में संपन्न हो जाती है तो कैनबरा के कूटनीतिक हलकों में भारत की मज़बूत उपस्थिति दर्ज हो सकती है, जो केविन रूड के शासनकाल में चीन की ओर मुड़ी हुई थी.

(लेखक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पॉलिसिंग एंड सिक्युरिटी, ऑस्ट्रेलिया में एसोसिएट इन्वेस्टीगेटर हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

साई 1860 में पहली बार शिरडी आए थे. तक़रीबन सोलह साल की उम्र में. लिहाज़ा वहां के लोग उन्हें कोई ख़ास तरजीह नहीं देते थे.

संकल्प कब सिद्ध होगा?

कनुप्रिया

आजकल दुनिया भर में चर्चा है थॉट पावर यानि संकल्प शक्ति की. बी पॉजिटिव यानि सकारात्मक सोच रखें. हम सब कोशिश कर चुके हैं. सकारात्मक सोच रखें कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो रहा है, वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं. भगवान की कृपा हम पर बनी रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये बुरे दिन कभी तो मिटेंगे. लेकिन चाहे कितनी भी सकारात्मक सोच रखूं, जो चाहूं वो नहीं होता. उल्टा ही होता है. और फिर नाराज़ हो मैं दुनिया से और भगवान से बेजार हो कर कहती हूं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है. मुझे तो खुशी मिल ही नहीं सकती. जो मैं चाहती हूं वो कभी नहीं होता. सब मुझसे जलते हैं. मेरी खुशी तो कोई देख ही नहीं सकता. भगवान भी मुझसे नाराज़ हैं.

और हम यूं ही हालात से समझौता कर बेचारगी भरी ज़िंदगी जीते हैं. आइए देखें हमारे विचार, हमारे संकल्प क्यों पूरे नहीं होते. हमें कोई नौकरी चाहिए तो हम चाहते हैं कि हमें यह नौकरी मिल जाए. हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन साथ-साथ हमारे मन में क्या-क्या विचार चलते हैं, ज़रा इन पर ध्यान दीजिए. क्या यह नौकरी मुझे मिल जाएगी? क्या इस बार भाग्य मेरा साथ देगा? क्या वे लोग मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. कहीं एप्रोच वाले लोग तो नहीं आएंगे. मेरी तो कोई जान पहचान भी नहीं है. भगवान कृपा करो. मुझे यह नौकरी दिला दो. अगर हमारे विचारों में, संकल्पों में शक्ति है तो ज़रा सोचें कि हमने कौन सी शक्ति बाहर भेजी है. डर की या संशय की! आगे बढ़ें. जीवन के ड्रामे में नौकरी के कई और मौक़े आएंगे. खुशी हुई लेकिन साथ ही नकारात्मक शक्ति से भरपूर विचारों का तांता भी तेज़ी से पनपा. क्या मैं इंटरव्यू में पास कर जाऊंगा. बहुत से लोगों को बुलाया होगा. मुझसे कुछ ऐसा पूछ लिया जो मुझे नहीं आता तो क्या होगा. और यह सारे नकारात्मक विचार एक बार नहीं आते बल्कि दिन-रात आते हैं. जब तक इंटरव्यू का समय नहीं पंहुच जाता, ये विचार मन में चलते रहते हैं. अब सोचें एक सकारात्मक शक्ति वाला विचार कि मुझे यह नौकरी चाहिए ही चाहिए. और इसके लिए ढेर सारी सकारात्मक शक्तियां भी नौकरी दिलाने के लिए सृष्टि में पहुंच गई. जब हमने कहा कि हमारे विचारों की शक्ति से काम होता है तो स्वयं ही देखें कि कौन सी विचार शक्ति ज़्यादा मज़बूत है. सकारात्मक या नकारात्मक. तब भी अगर हमें इंटरव्यू के बाद नौकरी मिल जाती है तो आप देखेंगे कि नौकरी के अवसर कई जगह से एक साथ आते हैं. अब विचारों का सिलसिला कुछ इस तरह चलेगा. क्या मेरे लिए यह नौकरी ठीक है? इसकी टाइमिंग मुश्किल है. सारा दिन निकल जाएगा. वहुत ज़िम्मेदारी का काम है. माहौल पता नहीं कैसा होगा? क्या यहां तरक्की के अवसर हैं. अब इस नकारात्मक शक्ति से भरपूर विचारधारा के साथ एक छोटा सा सकारात्मक विचार. चलो नौकरी तो मिल गई है. जब यह सोचते हैं कि यहां टिक पाएंगे कि नहीं, क्या इसलिए हम इस नौकरी में हैं और तभी नौकरियां छूटती हैं. अब आप कहेंगे, हम क्या करें? ये सारे विचार आना तो स्वाभाविक है. इस पर हमारा कोई वश नहीं है. यहां आप बिल्कुल सही हैं. आपने अपने विचारों को रोकने या बदलने की ज़रूरत ही नहीं समझी क्योंकि आपको इनके महत्व का पता ही नहीं था. जानते ही नहीं थे कि जीवन में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ आपके अपने ही विचारों का है. ये वो शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को ही नहीं पूरी सृष्टि को चला रही हैं. आज यह शक्ति नकारात्मक है, तो न सिर्फ़ मेरे जीवन में बल्कि मेरे आसपास पूरे महौल में सब कुछ नकारात्मक है. लेकिन जिस दिन यह जान लूंगा कि मेरे ही विचार मेरी नियति रचते हैं. अगले दिन जागते हैं इस सोच के साथ कि जैसी नियति चाहता हूं वैसे ही लिखूंगा. पर पहले यह तय करना है कि मैं विचार रचता कैसे हूं. इस नकारात्मक विचार शक्ति को पहचानूंगा कैसे, यह जान लूं. आज के लिए इतना ही. अगली बार जानेंगे अपने विचारों के साथ दोस्ती कैसे करें

ओम् साईं राम

feedback@chauthiduniya.com

ज्ञानोदय

- मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता. प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और प्रजाओं के हित में ही राजा को अपना हित समझना चाहिए. आत्मप्रियता में राजा का हित नहीं है, प्रजाओं की प्रियता में ही राजा का हित है.

-चाणक्य

- केवल वही व्यक्ति बेकार नहीं , जो बैठा रहता है. बल्कि वह भी बेकार है, जिसकी योग्यता का पूर्ण लाभ नहीं लिया जाता.

-सुकरात

- चाहे गुरु पर हो या ईश्वर पर, श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिए. क्योंकि बिना श्रद्धा के सब बातें व्यर्थ होती हैं.

-समर्थ रामदास

- मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है, इतिहास की धारा को बदल सकते हैं.

-महात्मा गांधी

- ईश्वर बड़े-बड़े साम्राज्यों से ऊब उठता है लेकिन छोटे-छोटे पुष्पों से कभी खिन्न नहीं होता.

-रवींद्रनाथ ठाकुर

- नाव जल में रहे लेकिन जल नाव में नहीं रहना चाहिए, इसी प्रकार साधक जग में रहे लेकिन जग साधक के मन में नहीं रहना चाहिए.

-रामकृष्ण परमहंस

- फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं. परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा है.

-तुलसीदास

- ज्ञानी जन विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी पुरुष आवश्यकता से और पशु स्वभाव से.

-कौटिल्य

भक्तों पर उदार साई

जब आप परेशान हों तो साई बाबा को याद करें. उनके पास जाकर ध्यान लगाएं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप एक साई भक्त की कहानी सुनिए जिसकी ज़िंदगी तबाह होने के कगार पर थी. पर साई की कृपा से सब ठीक हो गया. बाबा की भक्ति में लीन बाबा की भक्त रागिनी के जीवन में लंबे समय से परेशानियां चल रही थीं. उसके घर में रोज कोहराम मचता था. रागिनी का कहना है कि ऐसा लगता था कि मानो अपने ही परिवार में लोग एक दूसरे के ख़ून के प्यासे हो गए हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे. तभी किसी ने रागिनी को साई बाबा की शरण में जाने को कहा. रागिनी को एक मिनट के लिए लगा कि ऐसी हालत में कोई क्या कर सकता है. पहले तो उन्होंने सलाह मानने से इंकार कर दिया. बाद में रागिनी को लगा एक बार साई का दर्शन करने में क्या दिक़्क़त है. रागिनी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंच गई. फिर क्या था. बाबा ने रागिनी को अपनी शरण में ले लिया. शिरडी में बाबा ने रागिनी को साक्षात दर्शन दिया. बाबा ने उन्हें घर लाने की सलाह दी. रागिनी जब वापस पटना लौटी तो उसने साई बाबा की फोटो लगाकर पूजा करनी शुरू कर दी. लगभग एक साल बाद रागिनी ने साई बाबा की एक मूर्ति स्थापित की. धीरे-धीरे आसपास के लोगों को साई बाबा के चमत्कार का पता चला. लोगों ने साई बाबा की पूजा करनी शुरू कर दी. देखते-ही-देखते बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी. रागिनी को लगा कि उनकी मेहनत सफल रही. बाबा की भक्ति रास आई. जब लोग इस मंदिर में अपना दुख दर्द लेकर पहुंचने लगे तो उनके साथ भी चमत्कार होना शुरू हो गया. इसलिए कहते हैं बाबा को मन से साधो, उनकी कृपा ज़रूर होगी. रागिनी की भक्ति से ख़ुश होकर साई बाबा ने मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा दिखानी शुरू कर दी. इन्हीं भक्तों में नेहा भी है. नेहा की नौकरी होने वाली थी. सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी. पर जब नेहा घर से निकलने वाली थी कि उसका लेटर घर में कहीं गुम हो गया. नेहा ने अपना लेटर ढूंढना शुरू किया. लगातार ढूंढने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर का पता नहीं चला तब नेहा रोते-रोते पहुंच गई बाबा के मंदिर में. नेहा ने बाबा के सामने अपना सारा दुख कह डाला. उदास नेहा घर लौटी. लेकिन जैसे ही घर में घुसी कि ज्वाइनिंग लेटर उन्हें दिख गया. लेटर मेज पर रखा हुआ था. जबकि नेहा ने मेज पर कई बार ढूंढा था. नौकरी ज्वाइन करने के बाद अब नेहा जब भी अपनी तनख्वाह उठाती है, एक दिन बाबा के चरण में रखती इसके बाद ख़र्च करती है. पटना के इस साई मंदिर पर शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होता था. लोग देखकर मज़ाक उड़ाया करते थे. पर आज इस साई मंदिर में हज़ारों की तादाद में भीड़ लगी रहती है. और जो भी साई भक्त साई के दरबार में अपने दुख को लेकर जाते हैं उनके दुखों का निवारण भी साई करते हैं. कहा जाता है की भक्त जहां भगवान को पुकराता है वहीं भगवान पधारतें हैं. कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है पटना के कंकड़बाग साई मंदिर में, जहां अब सुबह-शाम तीन समय बाबा की आरती होती है और बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बहिष्कार वापस लिए जाने के बाद बौद्धों और मुसलमानों के रिश्ते अब लगभग सामान्य हो चुके हैं, लेकिन अंतर्धार्मिक शादियां अभी भी जारी हैं और खटास अभी भी बरक़रार है.

समकालीन साहित्य में सार्थक हस्तक्षेप

अनंत विजय

हिंदी में साहित्यिक पत्रिकाओं का लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है. दरअसल हिंदी में लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत छठे दशक में व्यावसायिक पत्रिका के जवाब के रूप में की गई. इस आंदोलन का श्रेय हम हिंदी के वरिष्ठ कवि विष्णुचंद्र शर्मा को दे सकते हैं. उन्होंने 1957 में बनारस से कवि का संपादन-प्रकाशन शुरू किया था. कालांतर में और भी कई लघु पत्रिकाएं व्यक्तिगत प्रयासों और प्रकाशन संस्थानों से निकली, जिसने हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं को न केवल समृद्ध किया, बल्कि उसका विकास भी किया. 1967 में नामवर सिंह के संपादन में आलोचना, सत्तर के दशक में विश्वनाथ तिवारी के संपादन में दस्तावेज, ज्ञानरंजन के संपादन में पहल. बाद में देश निर्मोही के संपादन में पल प्रतिपल के शुरुआती अंकों ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन बाद के उसके अंक कमज़ोर निकले. अब भी रुक-रुक कर उसका संपादन हो रहा है. लेकिन 1986 में राजेंद्र यादव के संपादन में निकली पत्रिका हंस ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया. इसी महीने हंस के प्रकाशन के पच्चीस साल पूरे हो रहे हैं. व्यक्तिगत प्रयासों से इतने लंबे समय तक नियमित रूप से मेरे जानते हिंदी साहित्य की कोई पत्रिका नहीं निकली. अखिलेश के संपादन में तद्भव के अंक ने भी पाठकों और आलोचकों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

लेकिन मुझे लगता है कि साठ के दशक में शुरू हुआ लघु पत्रिका आंदोलन अपनी राह से भटक गया है. इसने न केवल अपना चरित्र, बल्कि स्वरुप भी खो दिया है. लघु पत्रिका आंदोलन और उसकी विरासत से अंजान, अबोध लोग संपादक बने जा रहे हैं. लेकिन उन्हें न तो लघु पत्रिकाओं के दायित्व की परवाह है और न ही इसके चरित्र की. दरअसल संपादन एक बेहद कठिन कर्म है. इसमें व्यक्तिगत संबंधों को तरजीह दिए बगैर काम करना पड़ता है, लेकिन आज तो साहित्यिक पत्रिकाओं में तुम मेरी मैं तेरी वाली स्थिति व्याप्त है. पत्रिकाएं सौदेबज़ी का अखाड़ा बनती जा रही हैं. आज किसी भी लघु पत्रिका के संपादक में इतना साहस है कि वह किसी स्थापित साहित्यकार की रचना को लौटा सके. बड़े नामों को छापने के चक्कर में हो यह रहा है कि किसी का रिसर्च पेपर, किसी का भाषण, किसी का वक्तव्य छप रहा है. इससे संपादकों को दृष्टि की दयनीयता और और दरिद्रता का पता चलता है. आज हम कुछेक लघु पत्रिका संपादकों को छोड़ दें, तो अधिकांश में रचनाओं के चयन की दृष्टि का घोर अभाव दिखाई देता है. तक़रीबन हर संपादक संयोजन कर रहा है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने का साहस कितने लोगों के पास है. अगर संपादक की दृष्टि सुलझी हुई हो तो पत्रिका का एक स्वरूप बनता है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ संयोजन कर रहे हों तो उसकी एक स्पष्ट रूपरेखा आपके दिमाग़ में हो, वरना पूरी पत्रिका बिखर जाती है.

लघु पत्रिकाओं का एक अहम दायित्व स्थानीय प्रतिभाओं को मौक़ा देकर उसे साहित्य के परिदृश्य पर उभारने का भी होता है, पर आज के तमाम साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक नए लेखकों की रचनाओं को तरजीह नहीं देते हैं. उन्हें तो बड़े नाम चाहिए ताकि पाठक उसके प्रभाव में आकर पत्रिका ख़रीद सके. अच्छा होता अगर लघु पत्रिका के संपादक बड़े नामों

को छापने का मोह छोड़कर स्थानीय और नई प्रतिभाओं को उभारते. लेकिन साहस की कमी और बाज़ार की नासमझी उन्हें ऐसा करने से रोक देती है. हिंदी के वामपंथी लेखक हमेशा से बाज़ार और उसके प्रभाव का शोर मचाते रहते हैं. लेकिन उन्हें न तो बाज़ार की समझ है और न ही बाज़ार की ताक़त का एहसास. उन्हें तो हिंदी की ताक़त का भी एहसास नहीं है. अगर हिंदी का बाज़ार बन रहा है तो तकलीफ किस बात की.

क्या लेखकों को यह अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी कृतियां हज़ारों में बिके. आज हिंदी में कोई भी किताब पांच सौ से ज़्यादा नहीं छपती है और उसको भी बिकने में सालभर लग जाते हैं. पांच सौ किताबों के बिकने की बात प्रकाशक मानकर अगर दूसरा संसकरण छाप देता है तो लेखकों के पांव ज़मीन पर पड़ते ही नहीं हैं. हिंदी में बाज़ारवाद का शोर मचाने वालों से मेरा अनुरोध है कि पहले वो बाज़ार को समझें, उस पर विचार करें और इसके बाद अपने विचार व्यक्त करें. ऐसा नहीं है कि साहित्यिक पत्रिकाएं ख़ूब बिक रही हैं. इनका भी वही हाल है. अगर हंस, ज्ञानोदय, कथादेश और तद्भव को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई लघु पत्रिका होगी जो हज़ार प्रति छपती होगी. खैर, यह एक अवांतर प्रसंग है जिसपर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी.

अभी-अभी हिंदी में एक नई पत्रिका लेखक पत्रकार अशोक मिश्र के संपादन में आई है- रचना क्रम. पहले अंक में इस बात के संकेत हैं कि पत्रिका छमाही निकला करेगी. यह अंक ओम भारती के अतिथि संपादन में निकली है. तक़रीबन डेढ़ सौ पन्नों की इस पत्रिका में तमाम तरह की रचनाएं हैं. नामवर के भाषण से लेकर चंद्रकांत देवताले की कविताएं, अरुंधति राय का लंबा साक्षात्कार, रवींद्र कालिया और तेजिंदर के उपन्यासों के अंश के अलावा कई वैचारिक लेख भी हैं. लगता है कि इस अंक की योजना काफी पहले बन गई थी. इसी वजह से रवींद्र कालिया के उपन्यास अंश के इंट्रो में शीघ्र प्रकाश्य छप गया है, जब कि कालिया जी का उपन्यास 17 रानाडे रोड काफी पहले प्रकाशित होकर धूम मचा रहा है. महेश कटारे की कहानी इस अंक की बेहतरीन कहानियों में से एक है, जबकि मुशर्रफ़ आलम जौकी की कहानी इस अंक की सबसे कमज़ोर कहानी है. मुशर्रफ़ के साथ जो एक बड़ी दिक्कत है, वह ये है कि कहानियों के विषय का चुनाव तो ठीक-ठाक करते हैं लेकिन जब कहानी लिखते हैं तो वह उनसे संभलता नहीं है और पूरा का पूरा बिखर जाता है. यही वजह है कि दर्जनों कहानियां लिखने के बाद मुशर्रफ़ आलम जौकी की पहचान एक कहानीकार के रूप में बन नहीं पा रही है. रचना क्रम में पत्रकार उमेश चतुर्वेदी की कहानी श्रद्धांजलि छपी है और पत्रिका की ओर से यह दावा किया गया है कि उमेश की यह पहली कहानी है. लेकिन उमेश चतुर्वेदी की यह पहली कहानी नहीं है. इसके पहले भी उनकी तीन-चार कहानियां प्रकाशित होकर पुरस्कृत हो चुकी हैं. संपादक को इनमें सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो आनेवाली पीढ़ी और शोधार्थियों के बीच भ्रम फैलेगा. कुल मिलाकर अशोक मिश्र की इस पत्रिका से एक उम्मीद जगती है और इसने समकालीन हिंदी परिदृश्य में एक सार्थक हस्तक्षेप तो किया ही है. लेकिन संपादक से मेरा एक आग्रह है कि वह नए लोगों को तरजीह दें और स्थापित और बड़े साहित्यकारों की कूड़ा रचनाएं छापने से परहेज करें. विश्वास मानिए, पत्रिका को एक बड़ा बाज़ार मिलेगा और साहित्य को कई प्रतिभाएं.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

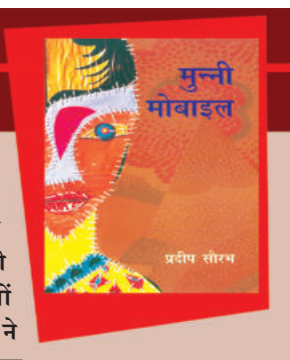

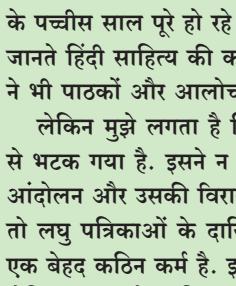

प्रदीप सौरभ

आज सोच रहे हैं, आनंद भारती-कैसी थी उनकी मानसी. मैं कई बार उसे बिना बात के झिड़क देता था. गुस्से में अपशब्द भी कह देता था पर वह कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी. उसे अपने आनंद भारती पर बेइंतहा विश्वास था...एक ऐसा विश्वास, जिसे रूमानी कहा जा सकता है. तब आनंद भारती भी यही सोचते थे कि मानसी शायद उनकी बाहर की ग्लैमरस दुनिया से प्रभावित है, उसे हीरो समझती है.

पर यही बात आनंद भारती तब नहीं समझ पाए कि सामान्य सी दिखने वाली मानसी हृदय से उनके उतार-चढाव को गहराई से समझती है. वह जानती थी कि आनंद भारती का रास्ता पथरीला है और इतना नुकीला, जहां चलने पर घाव भी मिल सकते हैं. सुख-सुविधाएं हों तो भी आनंद भारती का मन इतना गहरा समंदर है कि उसकी थाह कोई नहीं पा सकता. समंदर में उठने वाले ज्वार-भाटे की तरह आनंद का मन भी अनेक परतों से घिरा है. पर मानसी उसमें डूबकर संतुष्ट थी. बड़ा फ़ख्र था उसे अपने आप पर कि उससे ज़्यादा आनंद कोई दूसरा नहीं समझ सकता. आनंद उसकी इस बात को सुनकर रहस्य भरी मुस्कान से भर उठते थे...उनके भावनाओं के सैलाब का कोई ओर-छोर नहीं था. रिसर्च गाइड से मतभेद हो जाने के कारण आनंद भारती ने रिसर्च बीच में ही छोड़ दी थी. छिटपुट लेखन का काम बढ़ गया था.

अब वह पुस्तकालय जाते तो पुस्तकों के बजाय काग़ज़ कलम से जूझते. लेख लिखते तो काग़ज़ मानसी की ओर बढ़ा देते. मानसी उनके पन्ने को साफ-सुथरे ढंग से उतारती. कभी-कभी उस पर अपना चुना हुआ शीर्षक भी चस्पा कर देती. आनंद भारती की हर रचना की पहली पाठिका अक्सर

वही होती. आनंद भारती कुछ भी रचते...आड़ी-तिरछी रेखाएं भी, तो वह सब कुछ मानसी के बैग में हिफ़ाज़त से रख लिया जाता. न जाने कब तक आनंद भारती की इन सभी कविताओं, चित्रों और लेखों के रफ स्केच मानसी ने संभालकर रखे होंगे-इसका लेखा-जोखा आज आनंद भारती के पास नहीं है. होता तो शायद वह मानसी को आज अपना सर्वस्व समर्पित कर देते. अपने व्यक्तिगत भावों को हमेशा छुपा लेने वाले और बड़े-बड़े लेखों पर पैनी नज़र रखने वाले आनंद भारती मानसी की आंखों में वह सब नहीं पढ़ पाए, जो युवाकाल का चिरंतन सत्य है. पहाड़ों पर बहते निर्झर की तह मानसी उनके साथ बनी रही. वह रिश्ता सहज, सरल और नैसर्गिक सा रहा. पूरे तीन बरस तक.

अगले अंक में जारी ...

राख में मिल जाएगी संस्कृति लद्दाख की

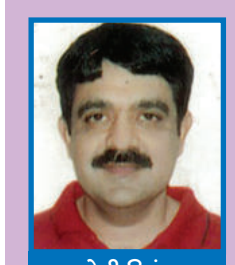

योगी सिकंद

उसका नाम मुझे याद नहीं. चलिए उसका एक नाम दे देते हैं सोनम. सोनम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (एलबीए) के लिए काम करता है. एलबीए बौद्ध समुदाय की वही संस्था है, जिसने मुसलमानों के बहिष्कार अभियान का नेतृत्व किया था. मैं सोनम से जोखांग मठ में मिला. लेह के मुख्य बाज़ार के बीचों-बीच सुन्नियों के मस्जिद के नज़दीक स्थित इसी मठ में एलबीए का कार्यालय है. बहिष्कार की चर्चा करते हुए सोनम कहता है कि इसकी शुरुआत आरगन समुदाय के युवकों द्वारा कुछ बौद्ध लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के बाद हुई थी. सोनम का यह बयान नामग्यालों की सोच से अलग है. वह आगे बताता है, छेड़छाड़ की इस घटना का बौद्ध युवकों ने विरोध किया और पूरे शहर में कई जगहों पर दोनों पक्षों के बीच हिंसक टकराव हुए. आसपास के गांवों में कुछ मुसलमानों के घर जला दिये गये और उन्हें लेह में शरण लेनी पड़ी. लेह और उसके नज़दीक स्थित शेय गांव में पुलिस की गोलीबारी में तीन लोगों की जान चली गई. लेह में व्यवसाय कर रहे कई कश्मीरी व्यापारियों को कश्मीर वापस लौटना पड़ा. बहिष्कार करीब तीन साल तक चला और सोनम गर्व के साथ कहता है कि लामाओं से मिले सहयोग के साथ एलबीए ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई. हमने बौद्धों को मुसलमानों की दुकान से सामान ख़रीदने या मुसलमानों की गाड़ियों में बैठने से मना कर दिया. बहिष्कार तभी जाकर ख़त्म हुआ, जब दोनों समुदाय अंतर्धार्मिक शादियों पर रोक लगाने को राजी हुए. लेकिन सोनम बताता है कि ये शादियां अभी भी हो रही हैं और सच्चाई यह है कि अधिकतर मामलों में मुसलमान युवक ही बौद्ध लड़कियों से शादी कर रहे हैं. वह चेतावनी के लहज़े में कहता है कि इस पर काबू नहीं किया गया तो स्थिति के दुबारा तनावपूर्ण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. वह यह भी बताता है कि मुसलमान बौद्ध लड़कियों को पैसे का लालच देकर धर्म बदलने और शादी के लिए तैयार कर लेते हैं. हालांकि, अधिकतर मुसलमान इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर देते हैं.

मैं सोनम से पूछता हूं कि क्या बहिष्कार और हिंसा की ये बातें बुद्ध के उपदेशों से मेल खाती हैं? सवाल सुनकर वह पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर स्वीकार करता है कि बुद्ध ने सभी

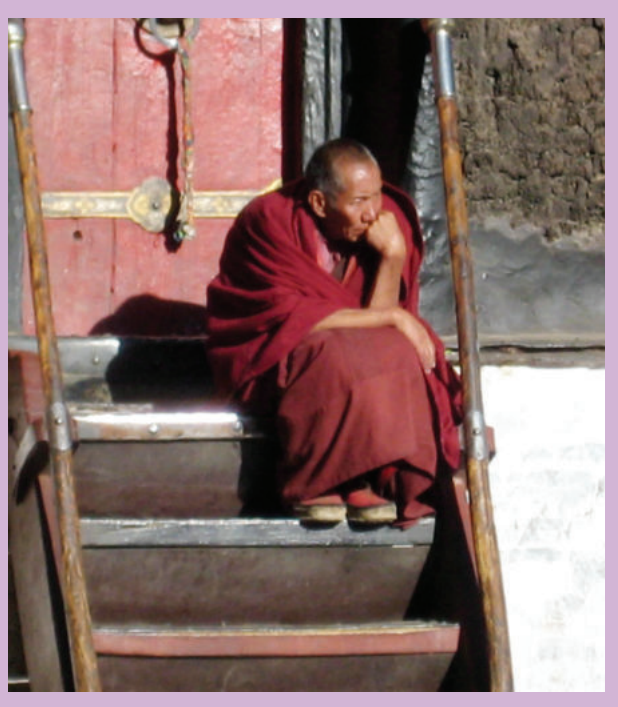

जीवों के प्रति अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया था. लेकिन वह यह कहने से भी नहीं चूकता कि बुद्ध ने हमें धर्म की रक्षा करने का उपदेश भी दिया था और बहिष्कार का भी यही मक़सद था. वह मुझे एक बौद्ध महंत की कहानी बताता है जिसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. हत्या की वजह यह थी कि उस इंसान ने 999 बौद्धों की हत्या का वचन लिया था. मुझे इस कहानी की सच्चाई का पता नहीं, लेकिन सोनम इसी के आधार पर बहिष्कार की प्रासंगिकता को सही साबित करने की कोशिश करता है. वह कहता है कि बौद्ध यदि दया का पाठ ही पढ़ाते रहे तो लद्दाख इलाक़े में हाशिए पर चले जाएंगे और मुसलमानों का प्रभुत्व कायम हो जाएगा. वह अफ़ग़ानिस्तान और कश्मीर घाटी का उदाहरण देता है, जो कभी बौद्ध प्रधान इलाक़े हुआ करते थे. सोनम बताता है कि बौद्धों की शांतिप्रियता की वजह से ही इस्लाम उनके बीच फूट पैदा करने और फिर इन इलाक़ों से भगाने में कामयाब रहा. लद्दाख की चर्चा करते हुए वह कहता है कि यदि बौद्ध समुदाय अपने धर्म की रक्षा के लिए संगठित नहीं हुआ तो यहां भी इस्लामिक आतंकी तत्वों का बोलबाला हो जाएगा. मैं उसकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन किसी समुदाय के सामाजिक बहिष्कार को सही नहीं मान सकता. मैं उसे दलाई लामा की याद दिलाता हूं. बहिष्कार को ग़लत बताते हुए दलाई लामा ने बौद्धों और मुसलमानों को मिल बैठ कर समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने की सलाह दी थी. अब सोनम के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा था. न चाहते हुए भी वह मान लेता है कि बहिष्कार का फ़ैसला ग़लत था, शायद बौद्ध धर्म के ख़िलाफ़ भी. लेकिन यह कहकर इसे जायज़ ठहराने की कोशिश करता है कि कश्मीरी और आरगन समुदायों की हरक़तों के ख़िलाफ़ यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी.

बहिष्कार वापस लिए जाने के बाद बौद्धों और मुसलमानों के रिश्ते अब लगभग सामान्य हो चुके हैं, लेकिन अंतर्धार्मिक शादियां अभी भी जारी हैं और खटास अभी भी बरकरार है. सोनम यह भी बताता है कि बहिष्कार का असर अभी भी नज़र आता है. पहले दोनों समुदायों के लोग एक-दूसरे के घरों में ख़ूब आते-जाते थे, लेकिन अब इसमें कमी आ गई है. बहिष्कार के असर से स्थानीय अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं है. लेह की अधिकतर दुकानों और सवारी गाड़ियों के मालिक पहले आरगन और कश्मीरी हुआ करते थे, लेकिन बहिष्कार के दौरान बौद्धों ने अपनी दुकानें लगा लीं, अपनी गाड़ियां ख़रीद लीं. सोनम कहता है कि लेह की अर्थव्यवस्था पर अब बौद्धों का क़ब्ज़ा है, हालांकि, आरगन समुदाय के लोगों को यह अच्छा नहीं लगता. इसमें कोई संदेह नहीं कि एक्स मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखता है. वह न हमारी इज़्ज़त करते हैं, न हमारे धर्म की, वह शिक़ायत के लहज़े में कहता है. उन्हें बचपन से ही क का मतलब काफ़िर सिखाया गया है, फिर हम उनसे प्रेम और सौहार्द की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं. वह मुझे मुसलमानों के बदले नज़रिए के बारे में भी बताता है जो बौद्धों से दूर रहने की हरसंभव कोशिश करते हैं. वह स्थानीय रीति-रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं और जानबूझ कर इस्लामिक परंपराओं को अपनाने लगे हैं. वह दावा करता है कि मुसलमान स्वभाव से ही झगड़ालू होते हैं और ख़ुद अपने धर्मावलंबियों के साथ लड़ने से भी बाज नहीं आते. वह खाड़ी युद्ध के दौरान करगिल की याद दिलाता है, जहां स्थानीय सुन्नियों ने सद्दाम हुसैन के समर्थन में प्रदर्शन किया था, लेकिन शियाओं ने उन्हें मारपीट कर घरों के अंदर जाने को मजबूर कर दिया था. शिया और सुन्नी आपस में एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, लेकिन बौद्धों के ख़िलाफ़ एकजुट हो जाते हैं. वह बौद्ध लोगों के उस डर के बारे में भी बताता है, जो लद्दाख में इस्लामिक आतंकवाद के बढ़ते ख़तरे से चिंतित हैं. हालांकि, वह मानता है कि आतंकी तत्वों को स्थानीय मुसलमानों का समर्थन हासिल नहीं है. वह कुछ दिन पहले जांस्कर में रांगडुम मठ के तीन लामाओं की हत्या की याद दिलाता है, जिन्हें आतंकियों ने मार दिया था. वह कहता है कि आतंकी तत्वों पर नकेल नहीं कसी गई तो वे हमारे सभी मठों को ध्वस्त कर देंगे और लद्दाख की संस्कृति राख में मिल जाएगी.

सोनम बताता है कि एलबीए पूरी तरह भारत का समर्थक है. वह यह भी कहता है कि पाकिस्तान के साथ मिलने का विकल्प बौद्धों के पास उपलब्ध नहीं है. यदि ऐसा हुआ तो हम पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, वह कहता है. सोनम के मुताबिक बौद्धों के लिए आदर्श स्थिति यही होगी कि लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए. हम कश्मीरियों से एकदम अलग हैं, फिर उनके साथ बने रहने का कोई कारण नहीं है, यह कहकर वह अपनी बात ख़त्म कर देता है.

feedback@chauthiduniya.com

बेल्किन के सभी मॉडलों में बिल्ट-इन सेल्फ हीलिंग ख़ूबियों को भी रखा गया है जो ख़ुद नेटवर्क की समस्या का पता लगाकर उसका निवारण भी करता है.

गर्मियों में दिखें हॉट और आकर्षक

विल्स लाइफस्टाइल मेंस रेंज में वाइब्रेंट स्ट्राइप्स, क्राफ्टेड जैकेट और स्मार्ट ट्राउजर्स हैं. कंपनी के वूमेंस रेंज में स्मार्ट शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट और जैकेट्स हैं.

स्टाइल और पर्सनालिटी को निखारने में कपड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. मौसम बदलते ही कपड़ों का स्टाइल बदल जाता है. महिलाओं और पुरुषों के लिए परिधान बनाने वाली विल्स लाइफस्टाइल ने गर्मी के इस मौसम को पूरे उत्साह से जीने के लिए नए कलेक्शन लांच किए हैं. यह कलेक्शन बिल्कुल नए, ठंडक देने वाले और ताज़गी भरने वाले फैब्रिक से तैयार किए गए हैं. इसके लिए कंपनी ने लाइनेन के साथ अलग-अलग फैब्रिक को मिलाकर नया प्रयोग किया है. इन कपड़ों से बने ड्रेसेज को मौसम के अनुकूल शेड और डिज़ाइन दिए गए हैं. साथ ही, ग्राहकों के कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है. बेहद आरामदायक और आकर्षक डिज़ाइन वाले इस कलेक्शन में रंगों का चुनाव बिल्कुल अलग हटकर किया गया है. इनमें समुद्री नीला, बसंती हरा, गहरा नीला, हल्का गुलाबी, आर्किड और नियॉन लाल के अतिरिक्त तमाम अन्य रंग मौजूद हैं जो आपको गर्मियों में सुकून पहुंचाएंगे. विल्स लाइफस्टाइल मेंस रेंज में वाइब्रेंट स्ट्राइप्स, क्राफ्टेड जैकेट और स्मार्ट ट्राउजर्स हैं. कंपनी के वूमेंस रेंज में स्मार्ट शर्ट्स, ट्राउजर्स स्कर्ट और जैकेट्स हैं.

विल्स ने यह संग्रह उन महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रस्तुत किया है, जो अपने व्यवहार के अनुसार अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाकर चार-चांद लगाना चाहते हैं. आधुनिक फैशन और ट्रेंड को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए इस संग्रह में हर तबक़े के लोगों को ध्यान में रखा गया है. इस कलेक्शन के ज़रिए ब्रांड ने महिलाओं और पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ परिधानों के तमाम विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि वे इस उमस भरे मौसम में भी आरामदायक और तरोताज़ा महसूस कर सकें. विल्स आधुनिक महिलाओं और पुरुषों के लिए ख़ास ब्रांड है. कंपनी अपने उत्पाद को लेकर काफ़ी सतर्क रहती है ताकि वह अपने ग्राहकों की गुणवत्ता और फैशन संबंधी मांगों को पूरा कर सके.

यह कलेक्शन 1095 रुपये के रेंज से शुरू होती है और देश के सभी प्रमुख स्टोरों में उपलब्ध है.

बेल्किन का अत्याधुनिक राउटर

भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक मोहित आनंद के अनुसार पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी डिजिटल कंटेंट शेयरिंग के क्षेत्र में ज़बरदस्त तेज़ी आई है. बेल्किन की नई ज़ोरदार रेंज की बदौलत कंपनी ग्राहकों के लिए विश्वस्तरीय, लगाने में आसान, तेज़ रफ्तार, भरोसेमंद और सुरक्षित वायरलेस तकनीक का अनुभव उपलब्ध कराना चाहती है. मोहित ने कहा कि वायरलेस नेटवर्किंग रेंज के उत्पादों को इस तरह से तैयार किया गया है कि उनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सके.

बेल्किन की अत्याधुनिक राउटर रेंज की प्रमुख एप्लीकेशन में पहला सेफ मेमोरी है. यह फोटोग्राफ और अन्य महत्वपूर्ण फाइलों का बाहरी हार्ड ड्राइव पर स्वत: ही बैकअप लेता है. दूसरा एप्लीकेशन प्रिंट जिनी है, जिसमें कहीं से भी, नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से वायरलेस तरीक़े से प्रिंट करने, उसे शेयर करने और प्ले मैक्स की सुविधा उपलब्ध है. तीसरा एप्लीकेशन म्यूज़िक मूवर है. इसकी मदद से अपनी म्यूज़िक लाइब्रेरी से होम स्टीरियो पर वायरलेस आधार पर एमपी3 प्ले किया जा सकता है. जिस हार्ड ड्राइव पर म्यूज़िक स्टोर करना हो, उसे राउटर से कनेक्ट करके इसका लुत्फ उठा सकते हैं. इसकी अगली खूबी म्यूज़िक लेबलर है. यह ख़ुद-ब-ख़ुद ट्रैक्स की पहचान कर उसे एनटाइटल, आर्टिस्ट और जॉनर के हिसाब से उनकी लेबलिंग करता है. इसका डेली डीजे फंक्शन भी बेहतरीन है. आप अपने मूड के हिसाब से म्यूज़िक लाइब्रेरी से दैनिक पर्सनलाइज़्ड प्लेलिस्ट ले सकते हैं. इसका टॉरेन्ट जिनी बड़ी मीडिया फाइलों जैसे मूवी, म्यूज़िक और गेम्स डाउनलोड करने की सुविधा देता है. कमाल की बात तो यह है कि कंप्यूटर न होने पर भी आप ऐसा कर सकते हैं. इनके अलावा इसमें निम्न प्रमुख विशेषताओं में शामिल ईज़ी स्टार्ट वायरलेस सेट अप और प्री-वायर्ड वायरलेस सेट अप है. प्री-सेट सिक्युरिटी तत्काल नेटवर्क सुरक्षा का भरोसा देता है और वीडियो मैक्स स्ट्रीमिंग वीडियो प्रदर्शन के लिए नेटवर्क सेटिंग्स को आदर्श बनाता है.

बेल्किन ने नेटवर्किंग बाज़ार की ज़रूरतों को देखते हुए अत्याधुनिक वाई-फाई उपकरण लांच किया है. कंपनी का यह नया उपकरण यूजर्स के लिए होम नेटवर्किंग को आसान और दिलचस्प बनाएगा. बेल्किन के अत्याधुनिक वाई-फाई उत्पादों में बेसिक, सर्फ, शेयर और प्ले मैक्स राउटर्स, मॉडम राउटर्स तथा वायरलेस यूएसबी क्लाइंट एडॉप्टर्स शामिल हैं. इसमें म्यूज़िक, गेम्स, एचडी वीडियो आदि की सुविधा दी गई है. साथ ही, इसमें कहीं भी और कभी भी फोटो शेयर एवं प्रिंट करने की सुविधा भी दी गई है. बेल्किन की नई वाई-फाई रेंज सभी तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इसकी प्लग एंड प्ले डिवाइस की वायरलेस सेटिंग करना न सिर्फ़ आसान है, बल्कि यह स्टाइलिश डिज़ाइन और कलात्मकता का नमूना भी है. नए ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक़ बेल्किन की अगली पीढ़ी की इस रेंज में पहले से कंफीगर्ड वायरलेस सिक्युरिटी का इंतज़ाम है. बेल्किन के हरेक डिवाइस में प्री-सेट सिक्युरिटी की व्यवस्था है. आसान तथा सुविधाजनक बनाने के लिए सभी उपकरणों में प्री-वायर्ड नेटवर्क केबल और पावर एडॉप्टर दिया गया है. बेल्किन के सभी मॉडलों में बिल्ट-इन सेल्फ हीलिंग ख़ूबियों को भी रखा गया है जो ख़ुद नेटवर्क की समस्या का पता लगाकर उसका निवारण भी करता है.

बेल्किन की नई वाई-फाई रेंज सभी तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इसकी प्लग एंड प्ले डिवाइस की वायरलेस सेटिंग करना न सिर्फ़ आसान है, बल्कि यह स्टाइलिश डिज़ाइन और कलात्मकता का नमूना भी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सेहत के साथ तकनीक का मेल

एचसीएल इंफोसिस्टम्स ने हेल्थकेयर समाधानों को उपलब्ध कराने के लिए वैलनॉजिक के साथ गठबंधन किया है. एचसीएल इंफोसिस्टमस भारत की प्रमुख हार्डवेयर, सर्विस और आईसीटी सिस्टम्स इंटीग्रेशन एवं वितरण कंपनी है, जबकि वैलनॉजिक जाना-माना हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर प्रदाता है. देशव्यापी एकीकृत हेल्थकेयर डिलीवरी मॉडल तैयार करने के लिए शुरू की गई यह भागीदारी सुरक्षित, किफ़ायती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के इरादे से की गई है. इस नई पहल से जिस तरह का मॉडल तैयार करने की योजना है, उससे मरीज़ों, क्लीनीशियनों, क्लीनिकल प्रयोगशालाओं, इमेर्जिंग केंद्रों, भुगतानकर्ताओं तथा अन्य संबद्ध पक्षों के लिए उम्दा और कस्टमाइज़्ड हेल्थकेयर सुविधा मुहैया कराने में मदद मिलेगी.

गठबंधन के बारे में जॉर्ज पॉल, कार्यकारी उपाध्यक्ष, एचसीएल इंफोसिस्टम्स ने कहा कि सूचना और संचार टेक्नोलॉजी ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र में सूचनाओं के रखरखाव, रिकॉर्ड संरक्षण और आवश्यकता होने पर उन्हें प्राप्त करने के तौर-तरीक़ों में व्यापक बदलाव किए हैं. यह नया हेल्थकेयर समाधान देशभर में हेल्थकेयर के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने और इसके एकीकरण में तेज़ी लाएगा, जिससे तकनीकी कुशलता, क्लीनिकल स्तर पर प्रभावशीलता और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

वैलनॉजिक इंफॉरमेशन टैक्नोलॉजीज के चेयरमैन डॉ. अजीत के. नागपाल ने कहा कि हमारा साझा लक्ष्य और वचनबद्धता स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को अधिक सुरक्षित और किफ़ायती बनाना है. हमें इस महत्वपूर्ण ई-हैल्थ पहल के लिए एचसीएलफ इंफोसिस्टम्स द्वारा अपना महत्वपूर्ण भागीदार चुने जाने पर गर्व है और इससे चिकित्सा पद्धति के तौर-तरीक़ों में व्यापक बदलाव आएगा.

भारत के आईसीटी मार्केट में एचसीएल इंफोसिस्टमस की नेतृत्वशाली भूमिका और हैल्थकेयर डाटा मैनेजमेंट में वैलनॉजिक की विशेषज्ञता के मेल से अत्याधुनिक हैल्थकेयर समाधान मुहैया कराया जाएगा. हैल्थकेयर क्षेत्र में वैलनॉजिक की सक्रियता की बदौलत मेडिकल क्षेत्र और भागीदार संगठनों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को तेज़ी से अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

सायना को सानिया की कहानी से सबक लेना होगा. उन्हें यह समझना होगा कि शीर्ष पर पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल वहां टिके रहना होता है.

सानिया मत बनना सायना

आदित्य पूजन

तीन सप्ताह में तीन विश्वस्तरीय टूर्नामेंट जीतकर भारत लौटी बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल को वैसे तो पूरे देश से बधाई संदेश मिले, लेकिन लंदन से सानिया मिर्ज़ा का भेजा संदेश पाकर वह ख़ुशी से झूम उठीं. विम्बलडन खेलने लंदन गई सानिया ने अपने संदेश में सायना को युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत और आदर्श बताया था. पिछले कुछ समय से टेनिस के कोर्ट पर अपने प्रदर्शन के बजाय इतर कारणों से चर्चा में रही सानिया की टीस को इस संदेश की मदद से समझा जा सकता है. ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा जब ख़ुद सानिया के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था. 2003 में जूनियर गर्ल्स विंबलडन डबल्स का ख़िताब जीतकर पहली बार सुर्ख़ियों में आईं सानिया का करियर ग्राफ शुरुआत में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि लोग उन्हें युवाओं के लिए आइकॉन घोषित करने लगे. सानिया दूसरों के लिए आदर्श तो बन गईं, लेकिन समस्या यह हो गई कि शुरुआती सफलता से मिली शोहरत ने ख़ुद उनके आदर्श बदल दिए. सानिया टेनिस से ज़्यादा ग्लैमर और पैसे के पीछे भागने लगीं. उनके क़दम भटक गए और आज हालत यह है कि युवाओं की एक पीढ़ी ही नहीं, बल्कि पूरा भारत उनसे ठगा महसूस कर रहा है. सानिया के संदेश में यही दर्द छुपा है, ख़ुद उम्मीदों पर खरा न उतर पाने की निराशा झलकती है. सायना के लिए बेहतर यही होगा कि वह इस निराशा को समझें और उन ग़लतियों से बचें जिनके चलते केवल 24 साल की उम्र में सानिया आज संन्यास के बारे में योजनाएं बनाने को मजबूर हैं.

इसमें कोई संदेह नहीं कि सायना नेहवाल भारतीय खेल जगत की नई उम्मीद बन कर उभरी हैं. जून के महीने में उन्होंने लगातार तीन सप्ताह में इंडियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स, सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज और इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज का ख़िताब अपने नाम किया और महिलाओं की वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गईं. लेकिन वह इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं. उनका अगला लक्ष्य नंबर एक का ताज हासिल करना है. केवल सायना ही नहीं, पूरे देश को यह भरोसा है कि वह अपने मक़सद में कामयाब होंगी, लेकिन यह डर भी है कि सफलता का सुरूर कहीं उनके सिर चढ़कर न बोलने लगे, शोहरत और पैसे की बारिश में उनके पैर भी सानिया मिर्ज़ा की तरह डगमगा न जाएं. बैडमिंटन की जगह कहीं बाज़ार उनके ऊपर भी न हावी हो जाए.

भारतीय खेलों की त्रासदी यही रही है कि जैसे ही कोई खिलाड़ी अपने करियर की शुरुआत में सफलता हासिल करता है, पूर्व खिलाड़ियों से लेकर मीडिया और प्रशंसक से लेकर बाज़ार तक उसके पीछे पड़ जाता है. मीडिया उसे नया सुपरस्टार घोषित करने लगता है तो प्रशंसक उससे उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं. पूर्व खिलाड़ी उसमें महानता की छवि देखने लगते हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत तो बाज़ार की हो जाती है. उसे तो मानो बेचने के लिए एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है. उसके सामने विज्ञापनों की होड़ लग जाती है. युवा खिलाड़ियों का अचेतन मस्तिष्क इस चकाचौंध में अक्सर भटक जाता है. सानिया मिर्ज़ा के साथ भी यही हुआ. महिला टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पचास खिलाड़ियों में शामिल होने से पहले ही उन्हें भारत की टेनिस क्वीन घोषित कर दिया गया. विज्ञापन कंपनियां उनके पीछे पड़ गईं और हर चौक–चौराहे पर लगे होर्डिंग्स में उनकी तस्वीर नज़र आने लगी. टेनिस कोर्ट पर प्रदर्शन से ज़्यादा चर्चा उनके फैशनेबल कपड़ों और अफेयरों को लेकर होने लगी. समस्या यह है कि विज्ञापन कंपनियां संघर्ष के दिनों में इन खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आतीं. सानिया मिर्ज़ा हों या सायना नेहवाल, करियर की शुरुआत में ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इन्हें प्रायोजक नहीं मिलते थे. सरकारी मदद नहीं मिली तो इनके अभिभावकों को अपने स्तर से पैसों की व्यवस्था करनी पड़ी थी, लेकिन एक दो प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते ही कंपनियां उन पर टूट पड़ीं.

सानिया और सायना में कई बातें एक जैसी हैं. सानिया की तरह सायना भी मध्यवर्गीय परिवार से हैं और हैदराबाद में पली–बढ़ी हैं. दोनों ने बचपन में अपने खेलों के गुर सीखे और जूनियर स्पर्द्धाओं में अच्छे प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की. कड़ी लगन एवं मेहनत और परिवारवालों के सहयोग से राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का सफ़र तय करने में इन्हें ज़्यादा वक़्त नहीं लगा. तेज़ी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते दोनों ही अंतरराष्ट्रीय सर्किट में भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही. लेकिन यहीं से दोनों की किस्मत अलग–अलग रास्ते पर आगे बढ़ती नज़र आ रही है. सानिया के करियर में साल 2007 सबसे अच्छा रहा जब वह बैंक ऑफ द वेस्ट क्लासिक टूर्नामेंट की सिंगल्स स्पर्द्धा में उपविजेता रहीं और डबल्स में शहार पीर के साथ मिलकर चैंपियन बनीं. इसके अलावा वह एक्यूरा क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र तय करने में कामयाब रहीं. लेकिन इसके बाद से उनका करियर लगातार ढलान पर है. वर्ल्ड रैंकिंग में कभी 27वें स्थान पर रही सानिया आज पहली सौ खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं हैं. सिंगल्स के अलावा डबल्स में भी उनका प्रदर्शन लगातार नीचे की ओर जा रहा है. 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स्ड डबल्स ख़िताब जीतने के बाद से अब तक वह कोई भी ख़िताब नहीं जीत पाई हैं. इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी करने के बाद अब वह टेनिस से संन्यास लेने की योजना भी बना रही हैं.

2007 में सानिया की उम्र क़रीब–क़रीब उतनी ही थी, जितनी आज सायना नेहवाल की है. सायना के छोटे से करियर में साल 2010 अब तक सबसे बेहतरीन रहा है. वह एक के बाद एक टूर्नामेंटों में ख़िताब जीतती जा रही हैं और सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर चुकी हैं. ज़ाहिर है, उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं और इसका दबाव भी उनके ऊपर होगा. लेकिन सायना को सानिया की कहानी से सबक लेना होगा. उन्हें यह समझना होगा कि शीर्ष पर पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल वहां टिके रहना होता है. इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन के अलावा त्याग की ज़रूरत होती है. उन्हें ख़ुद को पैसे और प्रसिद्धि के मायाजाल से बचाकर रखना होगा.

सायना चाहें तो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के उदाहरण से भी सीख ले सकती हैं. स्कूल के दिनों से ही अभिन्न मित्र रहे सचिन और कांबली क़रीब–क़रीब एक साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आए थे. दोनों की प्रतिभा पर किसी तरह के शक़ की कोई गुंजाइश नहीं. कई लोगों का तो यहां तक मानना है कि बल्लेबाजी की शैली के मामले में कांबली सचिन से कहीं ज़्यादा बेहतर थे. लेकिन सचिन जहां अभी भी क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजी के नए मापदंड खड़े कर रहे हैं, कांबली गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं. उनका किस्सा भी सानिया मिर्ज़ा से काफ़ी मिलता–जुलता है. शुरुआती कामयाबियों ने उन्हें इतना चकाचौंध कर दिया कि कांबली बल्लेबाजी के अलावा हर वो काम करने लगे, जिससे सुर्ख़ियों में बने रहें, लेकिन आज उन्हें कोई याद भी नहीं करता. सायना को सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा लेनी चाहिए. अपनी प्राथमिकताएं तय कर उसे पाने के लिए जी–जान से कोशिश करनी चाहिए. लक्ष्य निगाहों में हो, तो उसे पाना आसान हो जाता है. अच्छी बात यह है कि सायना अब तक प्रलोभनों से दूर रहने में कामयाब रही हैं. लेकिन उनका असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है. यदि वह आगे भी ऐसा करने में कामयाब रहती हैं, तो बैडमिंटन के कोर्ट पर भारतीय तिरंगा लंबे समय तक फहराता रहेगा.

aditya@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम–भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार–राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

ऑन लाइन पाइरेसी के माध्यम से देशी विदेशी फ़िल्मों के अनसेंसर्ड प्रिंट डाउनलोड किए जाते हैं. इंटरनेट पर हज़ारों अश्लील वेबसाइट मौजूद हैं.

सेंसर, फिल्में और राजनीति-4

सेंसर शब्द ही बेमानी है

राजेश एस कुमार

इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हमारे यहां सेंसर बोर्ड सिर्फ़ सतही तौर पर फिल्मों और सर्टिफिकेट की भूलभुलैया में उलझा रहता है, जबकि समस्या की जड़ कुछ और है. सेंसर सामाजिक दुष्प्रभाव की बात करता है. इसी के आधार पर वह उन सभी मसालों को आम लोगों तक पहुंचने से रोकने का ढिंढोरा पीटता है, जो संस्कृति के ख़िलाफ़ हो. लेकिन इन्हें रोकने में वह कितना सफल होता है, यह सर्वविदित है. पिछले तीन अंको में हमने उन मसलों और कंटेंट पर बात की थी जो सेंसर के अपारदर्शी काले चश्मे से गुज़रते हैं. इस आख़िरी कड़ी में सेंसर के लापरवाह रवैये और उन अनसेंसर्ड जरियों की बात करेंगे जिन्हें न तो बोर्ड सेंसर करता है और न ही ऐसा करना उसके लिए संभव है. असंभव इसलिए नहीं है कि वह कुछ कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि वह कुछ करना ही नहीं चाहता. असलियत यह है कि इनकी धार सेंसर की कैंची से ज़्यादा तेज़ है.

देश में फिल्मों के अलावा पोर्न और पायरेटेड फिल्मों का बाज़ार, इंटरनेट का वृहत संसार, हॉलीवुड फिल्मों का गैरसंपादित ऑनलाइन वितरण, अश्लील साहित्य, येलो जर्नलिज्म, सैटेलाइट चैनलों का सीधा अनकट प्रसारण जैसे कई ऐसे माध्यम हैं जो लोगों की आम दिनचर्या में शुमार हो गए हैं. इन माध्यमों से प्रचारित और प्रसारित होने वाला कंटेंट हर बच्चे की पुहंच में है और फिल्मों से कहीं ज़्यादा वल्गर और दुष्प्रभावी होता है. इतने सारे माध्यमों के आगे सेंसर बौना सा प्रतीत होता है. ऑन लाइन पाइरेसी के माध्यम से देशी-विदेशी फिल्मों के अनसेंसर्ड प्रिंट डाउनलोड किए जाते है. इंटरनेट पर हज़ारों अश्लील वेबसाइट मौजूद हैं. भारत में इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग करने वाले जानते होंगे की हिंदी की पहली सॉफ़्ट-पॉर्न कॉमिक कैरेक्टर पर बेस्ड रीींळीींरलहरलहळ.ले साइट को रणवीर कपूर विवाद के बाद भारत सरकार ने बैन कर दिया है. लेकिन वो यह भी जानते होंगे कि सविता भाभी जैसी कई और देशी-विदेशी साइट्स इंटरनेट के 80 फीसदी हिस्से में मौजूद हैं. सेंसर बोर्ड भी यह अच्छी तरह जानता है, लेकिन कुछ नहीं करता. रही बात क़ानून की तो सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि भारत में साइबर लॉ में प्रावधान इतने कड़े नहीं है कि इसको रोका जा सके. इसी तरह मस्तराम के देसी संस्करण और डेबोनियर से लेकर प्लेब्वॉय जैसी मैग्ज़ीन कोई भी बच्चा किसी भी दुकान से ख़रीद सकता है. घर में बच्चे का बोलना शुरू होता कि उसके हाथ में मोबाइल और कंम्प्यूटर थमा दिया जाता है. मोबाइल पाते ही एमएमएस स्कैंडल्स और सेक्स क्लिप का कारोबार शुरू हो जाता है. पहले से ही सिनेम से रिया-अस्मित, शाहिद-करीना और लक्ष्मी राय समेत कई अभिनेत्रियों के अश्लील एमएमएस चर्चा में रहे हैं. वेबसाइट तो औपचारिक तौर पर ही सही लेकिन 18+ की शर्त रख देती है, पर मोबाइल कंटेंट के मामले में तो यह अवरोध भी नहीं है. सिंगल स्क्रीन में चलने वाली एडल्ट फिल्मों में वयस्क और अवयस्क कोई भी घुस सकता है. हाथ में टॉर्च लिए खड़ा गेटमैन लगभग सेंसर की तरह ही बर्ताव करता है. उसे मालूम है कि नियम-क़ानून क्या हैं, फिर भी वह आंख मूंदे केवल खड़ा रहता है. इस तरह सैकड़ों ऐसे विषय और सेक्टर्स हैं जहां सेंसर की भूमिका हो सकती है पर नहीं है.

ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बोर्ड सिर्फ अश्लील और हिंसात्मक दृश्यों को सेंसर करने के लिए बना है. जानकारी के लिए बता दें कि सेंसरसिप के कुछ मापदंड हैं. फिल्में 4 श्रेणियों- यू, यू/ए, ए और एस में वर्गीकृत की जाती हैं. संक्षिप्त में समझें तो यू श्रेणी के सर्टिफिकेट की फिल्म सभी दर्शकों के लिए होती है. यू/ए श्रेणी की फिल्म वयस्क के अलावा अभिभावक की मौजूदगी में बच्चे भी देख सकते हैं. ए यानी एडल्ट फिल्में सिर्फ़ वयस्कों के लिए होती हैं और आख़िरी श्रेणी एस के अंतर्गत सेंसर्ड फिल्में डॉक्टरों समेत एक विशेष दर्शक वर्ग के लिए होती हैं. बाकी फिल्में ग़ैर क़ानूनी रूप से प्रदर्शित होती हैं. इन चारों के अलावा सॉफ्ट और हार्डकोर पॉर्न फिल्मों की भी श्रेणी है. यह विदेशों में मान्य है, भारत में नहीं. इन श्रेणियों के अंतर्गत सिर्फ़ अश्लील दृश्य ही नहीं बल्कि किसी जाति, समुदाय, राष्ट्र और धर्म विरोधी संवाद और दृश्य, अतिरेक हिंसा, महिलाओं और विकलांगों पर नकारात्मक टिप्पणी और द्विअर्थी संवादों पर भी कैंची चलती है. इसलिए अतिरेक हिंसा वाली फिल्म भी एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ पास होती है. लेकिन सच्चाई यह है कि उपरोक्त श्रेणियां और क़ायदे-क़ानून सिर्फ़ काग़ज़ी हैं. जिसका जितना रसूख, उतना लचीला बोर्ड.इन हाइटेक ऑप्शंस से लड़ने कि लिए भले ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सेंट्रल बोर्ड की मुख्य बैठकों में अध्यक्ष शर्मिला टैगोर बोर्ड को हाईटैक बनाने का बात कहती हों या मॉर्डनाइजेशन के युग में ऑनलाइन तरीके से सर्टिफिकेट देने की प्रकिया अपनाने की बात करती हों पर हक़ीक़त में यह सिर्फ़ बैठकों में होने वाली खानापूर्ति मात्र है.

जहां देश की ऐंबेंसी का पोर्टल पोर्न वेबसाइट में तब्दील हो जाता है, वहां सेंसर के क्या मायने रह जाते हैं. जब तक उपरोक्त माध्यमों को बारीकी से समझकर सेंसर करने का रास्ता नहीं निकाला जाएगा, तब तक देश में सेंसर शब्द ही बेमानी है.

rajeshy@chauthiduniya.com

मेहनत पर विश्वास

ख़ूबसूरत और डीसेंट श्रिया शरन अब अपने सोबर अंदाज़ के विपरीत स्क्रीन पर ठुमके लगाते हुए नज़र आने वाली हैं. वह पवन कुमार की तमिल फ़िल्म कोमा राम पुली में आइटम डांस करने वाली हैं. यह आइटम डांस तीन मिनट का है जिसकी शूटिंग पूरी होने में सिर्फ़ तीन दिन का वक़्त लगा. लेकिन सिर्फ़ तीन मिनट के इस गाने से श्रिया के बैंक बैलेंस में ख़ासा इज़ाफ़ा हुआ है. अपने इस छोटे से आइटम डांस के लिए उन्होंने 22 लाख रूपए वसूले हैं. श्रिया बचपन से ही कत्थक नृत्यांगना बनना चाहती थी इसलिए अपने शौक को पूरा करने के लिए वह कभी कभार फ़िल्मों में आइटम डांस करना चाहती हैं.

सफल मॉडल और अभिनेत्री श्रिया सरन ने भले ही बहुत कम फ़िल्मों में काम किया है. लेकिन अच्छी भूमिका और अभिनय के वजह से वो दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने में सफल रही हैं. अलग-अलग भाषाओं में निपुण श्रिया बॉलीवुड ही नही हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहीं है. कड़ी मेहनत के बावजूद श्रिया बॉलीवुड में अपनी जगह एक सफल अभिनेत्री के रूप में नहीं बना पाई. कई हिंदी फ़िल्में जैसे थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम, आवारापन, मिशन इस्तांबुल, एक- द पावर ऑफ वन आदि फ़िल्मों में काम किया पर सभी एक के बाद एक फ्लॉप होती गई, हलांकि उनके ख़ूबसूरत चेहरे को दर्शकों ने ख़ूब नोटिस किया. दक्षिण की फ़िल्मों के शहंशाह रजनीकांत के अपोजिट वह शिवाजी द बॉस में काम कर चुकी है. अपनी सफलता का राज़ बताते हुए वह कहती है कि वो पक्के तौर पर यह विश्वास करती है कि कड़ी मेहनत से वह जो भी चाहें, वो हासिल कर लेती हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रिव्यू

खट्टा मीठा

बॉलीवुड में हॉलीवुड या दूसरी विदेशी फिल्मों के अलावा टॉलीवुड की फिल्मों का रीमेक बनाने की परपंरा पुरानी है. अच्छी बात यह है कि इन फिल्मों को बॉक्स आफिस पर पसंद भी ख़ूब किया जाता रहा है. ऐसे ही अक्षय कुमार स्टारर फिल्म खट्टा-मीठा भी वर्ष 1989 में आई हिट मलयालम फिल्म वेल्लानाकालुड़ी नाडु का हिंदी रीमेक है. प्रियदर्शन निर्देशित इस फिल्म में अक्षय के अलावा तृषा कृष्नन, अरूणा ईरानी, जॉनी लीवर, असरानी, मकरंद देशपांडे, राजपाल यादव हैं. फिल्म की स्टार कास्ट से ही इस फिल्म के फ्लेवर का पता चलता है, उस पर प्रियदर्शन का निर्देशन इस बात को पुख्ता करता है कि खट्टा मीठा कॉमेडी जॉनर की फिल्म है. बी-टाउन के बड़े हास्य कलाकारों को एक साथ इस फिल्म में देखना अच्छा अनुभव होगा, अगर उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया होगा. कहानी कुछ यूं है कि संघर्षरत रोड कॉन्ट्रेक्टर सचिन तिचकुले बड़े-बड़े सपने देखता है लेकिन उस सपने पूरे नहीं हो पाते क्योंकि वह रिश्वत में विश्वास नहीं रखता. हद तो तब होती है जब सचिन शहर आता है, उसी शहर में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तृषा मेनन नई म्यूनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट पर आती है. अक्षय से ब्रेक-अप के बाद तृषा अक्षय से नफ़रत करती है. सचिन अपने रास्ते पर चलते हुए अजीबो-ग़रीब हालातों से गुज़रता है, इसमें काफी हास्यासपद घटनाएं पैदा होती हैं. जैसा कि प्रियदर्शन की अधिकतर फिल्म में किसी भी एक सिचुएशन पर हंसी और व्यंग का तड़का होता है. फिल्म में कॉमेडी ट्रीटमेंट के साथ सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को भी दिखाया गया है. साथ ही यह दर्शाया गया है कि सिस्टम में टिकने के लिए चतुर होने की जरूरत है. फिल्म का संगीत प्रीतम ने दिया है. वैसे इस फिल्म के गाने पर विवाद पहले ही खड़ा हो चुका है. बॉलीवुड की फिल्मों में बढ़ते अपशब्द के इस्तेमाल के ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस फिल्म के एक गीत में जमकर गाली का इस्तेमाल किया गया है. गणेश आचार्य द्धारा कोरियोग्राफ किए गए इस गीत में अंग्रेजी गाली बुल शिट का इस्तेमाल हुआ है, इस गाने में सिस्टम के ख़िलाफ़ भावनाओं को प्रदर्शित किया गया है. इससे देश के कुछ नेताओं को लगता है कि उनकी छवि खराब हुई है, इसलिए गीत के बोल में से उस शब्द को हटाने का आदेश सेंसर बोर्ड द्धारा दिया जा चुका है. हालांकि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार मानते हैं कि बुलशिट जैसी गाली आम है और मर्यादा की सीमा में है. हर फिल्म के साथ इनदिनों कंट्रोवर्सी आम है, देखते हैं इस कंट्रोवर्सी के बाद 23 जुलाई को रिलीज हो रही यह फिल्म क्या कमाल दिखाती है.

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड

दिल्ली, 12 जुलाई-18 जुलाई 2010 www.chauthiduniya.com

बारिश से बेहाल नेता

चुनावी गर्मी से नेता बेहाल हैं, तो मौसमी गर्मी से जनता. मौसमी गर्मी से आम लोगों को निजात देने के लिए बारिश ने तो दस्तक दे दी है, लेकिन इस दस्तक ने नेताओं के मस्तक से पसीना कम नहीं किया. इसकी वजह है बारिश में ग्रामीण क्षेत्रों का चुनावी दौरा नहीं कर पाना, लेकिन नीतीश ने दूरदृष्टि से काम लेकर बारिश के पहले दौरे का काम निबटा लिया, लोगों का मन टटोल लिया और पार्टी का अंदरूनी भूगोल माप लिया. लालू यादव, रामविलास पासवान और सुशील मोदी सरीखे नेता यह करने में पीछे रह गए. उनके दौरे में बरसात खलल डाल रही है.

सरोज सिंह

चुनावी मानसून पता नहीं किस नेता के लिए कामयाबी की फुहारें लाए और किस नेता को वृष्टि छाया क्षेत्र में सूखा छोड़ दे, यह तो समय बताएगा, लेकिन प्राकृतिक बारिश की ठंडी फुहारों के बावजूद कुछ नेताओं के माथे से पसीने का गिरना थम ही नहीं रहा. बारिश से प्रदेश की जनता तो राहत महसूस कर रही है पर नेता आहत. नेताओं की निगाह गांवों के वोटरों पर लगी है, लेकिन बरसात उन्हें वहां जाने से रोक रही है. पर इसी में कुछ नेता ऐसे भी हैं, जिन्होंने दूरदृष्टि से काम लिया और बारिश गिरने के पहले ही गांवों का दौरा कर ग्रामीण मतदाताओं से संपर्क का काम निबटा लिया.

वोट-रेस के पहले कैंपेन-रेस में कुछ नेताओं ने तो बढ़त हासिल कर ली. इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम अव्वल है. चार महीने बाद की चुनावी फसल काटने के लिए सारी पार्टियां तैयारियां तो कर रही हैं, संसाधन तो झोंक रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं से समय रहते संपर्क करने में पिछड़ गईं. बारिश और बाढ़ के माहौल में गांवों के मतदाता नेताओं की याचना लेने से वंचित रह जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने बरसात के पहले पूरे बिहार का दौरा कर विश्वास यात्रा के जरिए मतदाताओं से संपर्क का आत्मविश्वास पुख्ता कर लिया. विश्वास यात्रा के सियासी प्रभाव को आंकने में अन्य नेताओं ने थोड़ी देर कर दी, और जब तक संभलते और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क अभियान का कार्यक्रम बनाते तब तक बारिश ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

नीतीश कुमार ने दूरंदेशी से विश्वास यात्रा का ऐसा कार्यक्रम बनाया कि बरसात शुरू होने से पहले ही संपूर्ण बिहार का दौरा सम्पन्न हो जाए. और ऐसा ही हुआ, नीतीश कुमार समय रहते बारिश के पहले ही लगभग पूरे बिहार की जनता से विकास यात्रा जारी रखने का वादा कर आए. नीतीश मतदाताओं से संपर्क के साथ-साथ अपनी यात्रा के दौरान रात में स्थानीय नेताओं के यहां भोजन कर राजनीतिक पारा भी समझ आए. ज़िलों में पार्टी के अंदर चल रही गुटबंदी को समझने में भी उन्हें इस यात्रा से काफी मदद मिली. इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर किस नेता की जनता में कितनी पैठ है, इसका भी आकलन हो गया. आगामी चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में उससे मदद मिलने की उम्मीद है. पार्टी नेता बताते हैं कि नीतीश कुमार जिस ज़िले में विश्वास यात्रा पर निकलते थे. उस ज़िले का पूरा चुनावी इतिहास और आंकड़ा उनके साथ होता था. वहां के स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेताओं की हैसियत का पूरा विवरण भी उनके पास होता था. चुनावी मामले में उनकी मदद करने वाले एक नेता ने बताया कि इन आंकड़ों को नीतीश कुमार ज़मीनी तौर पर ख़ुद अपनी आंखों से देख लेना चाहते थे, ताकि टिकट बंटवारे से लेकर अन्य कोई राजनीतिक फ़ैसला करने में कोई चूक न हो जाए. बताया जाता है कि कुछ ज़िलों के राजनीतिक आंकड़ों को उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर दुरुस्त भी कराया. नीतीश कुमार चाहते थे कि चुनाव की घोषणा से पहले वह पहले दौर का होमवर्क पूरा कर लें और इसमें वह सफल रहे. भाजपा भी ज़िलास्तर पर अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाने में जुट गई है. 103 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सार्वजनिक कर भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की कि पांच साल पहले पार्टी की जो हैसियत थी, वह बरक़रार है और इस चुनाव में भी जदयू के साथ सम्मानजनक समझौता होगा. इसके अलावा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यह भी साफ़ कर दिया कि नरेंद्र मोदी व वरुण गांधी के बिहार दौरे पर फ़ैसला केवल भाजपा और भाजपा ही करेगी. पार्टी ज़िलों में जाकर यह साफ़ कर रही कि नीतीश कुमार या फिर जदयू का कोई दबाव भाजपा पर नहीं है और टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय करने के लिए पार्टी पूरी तरह स्वतंत्र है. भाजपा ने ज़िलास्तर पर अपने स्थानीय नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है. भाजपा हर ज़िले में रैली आयोजित करने का भी मन बना रही है और जल्द ही इस पर फ़ैसला ले लिया जाएगा. चकाई, सोनबरसा व मुजफ्फरपुर सीट पर पार्टी अपना दावा मजबूती से रखेगी. कुल मिलाकर राजग ने पहले राउंड का अपना होमवर्क पूरा कर लिया.

नीतीश मतदाताओं से संपर्क के साथ-साथ अपनी यात्रा के दौरान रात में स्थानीय नेताओं के यहां भोजन कर राजनीतिक पारा भी समझ आए. ज़िलों में पार्टी के अंदर चल रही गुटबंदी को समझने में भी उन्हें इस यात्रा से काफी मदद मिली. इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर किस नेता की जनता में कितनी पैठ है, इसका भी आकलन हो गया. इसका भी आकलन हो गया. आगामी चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में उससे मदद मिलने की उम्मीद है.

इस बार लालू प्रसाद यादव व रामविलास पासवान का चुनावी अभियान लय में नहीं दिख रहा. ऐसा कुछ राज्यसभा चुनाव के कारण तो कुछ आपसी तालमेल व स्पष्ट रणनीति की कमी के कारण हुआ. हालांकि ये नेता संभलने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इन्हीं कोशिशों के तहत लालू प्रसाद यादव चंपारण से भंडाफोड़ यात्रा शुरू कर रहे हैं. इसके अलावा पासवान ने भी ज़िला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों का दौर शुरू कर दिया है. बताया जाता है कि लालू यादव व रामविलास पासवान के बीच राज्य में तालमेल के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है. इन दोनों नेताओं का पूरा ज़ोर नीतीश के चुनावी समीकरणों को ध्वस्त करने पर है. ये दोनों नेता दलित, महादलित और अतिपिछड़ा वोटों में हो रही सेंधमारी रोकने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. इसके अलावा मुसलमानों की तरफ ललचायी नज़रों से देख रहे नीतीश कुमार को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी का कार्ड जोरशोर से चलने की रणनीति तय की गई है. सवर्ण वोटरों की नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी को भी ये दोनों नेता भुनाना चाहते हैं. बांका के सांसद दिग्विजय सिंह की अंत्येष्टि में नीतीश कुमार के नहीं जाने को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है. अंत्येष्टि के दिन जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा उसे देखकर लालू व पासवान को लगता है कि सवर्ण वोटरों को यह बात बताई जाए कि नीतीश कुमार जिसकी मदद से सत्ता तक पहुंचे उसकी अंत्येष्टि में जाना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा. जदयू के नेता दलील दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को विश्वास यात्रा में गोपालगंज जाना था. इस कारण वह नहीं जा सके, लेकिन राजद सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि नीतीश मानवता भूल चुके हैं. लालू प्रसाद को भी इस दिन जनसभा के लिए जाना था, लेकिन समय निकालकर वह अंत्येष्टि में शामिल हुए. नीतीश चाहते तो वह भी लालू प्रसाद की तरह समय निकाल सकते थे. पर उन्होंने इसे ज़रूरी नहीं समझा. देखा जाए तो राजद व लोजपा की रणनीति नीतीश से नाराज तबके के नजदीक जाना और उन्हें अपना बनाना है. किसान महापंचायत के भी कई नेताओं पर इन दोनों की नज़र है. सूत्रों पर भरोसा करें तो प्रभुनाथ सिंह इस खेमे में आ सकते हैं. उनके अलावा भी कुछ सवर्ण विधायकों व नेताओं को भी साथ लाने की तैयारी चल रही है. जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो अंदरूनी खींचतान के कारण अपने पक्ष में उभरे समर्थन का लाभ नहीं उठा पा रही है. ज़िलों में कार्यक्रम हो तो रहे हैं पर इनमें मारपीट व उपद्रव के कारण सारे किए धराए पर पानी फिर रहा है. मधुबनी व बेतिया में जो सीन सामने आया उससे तो यह लगने लगा है कि अगर यही चलता रहा तो कांग्रेस की तरफ मुखातिब वोटर नीतीश कुमार की तरफ चले जाएंगे. अब यह जरूरत महसूस की जाने लगी है कि सोनिया गांधी बिहार के मामले में सीधा हस्तक्षेप करे और प्रदेश के लोगों से सरकार बनाने के लिए सहयोग मांगे. सोनिया गांधी के इस क़दम से कांग्रेस के अंदर गुटबंदी तो बंद होगी ही साथ ही लोगों में यह भरोसा भी जगेगा कि सही मायनों में कांग्रेस बिहार के चुनावी अखाड़े में उतरने वाली है. उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त महीने में सोनिया गांधी बिहार में एक बड़ी रैली कर पार्टी की तरफ से चुनावी शंखनाद करेगी. वाम दलों ने भी अपनी खोई ज़मीन वापस पाने के लिए गांवों का रुख कर लिया है. इस तरह से सभी दल गांवों में घूम-घूमकर वार्मअप हो रहे हैं. पहला राउंड ख़त्म होने को है और सभी नेताओं की पूरी कोशिश है कि दूसरे राउंड में कोई चूक न रह जाए.

feedback@chauthiduniya.com

बदले समीकरण से पुराने चेहरों के साथ-साथ नए दावेदारों की बेचैनी भी बढ़ गई है. वर्तमान विधायक राज किशोर केसरी ने पिछले चुनाव में डॉ. राम चरित्र यादव को हराया था.

बिहार का रेल मंत्री जो भी बने, अपने-अपने इलाक़ों में रेलगाड़ी एवं रेल पटरी बिछाने तथा ट्रेन आदि का ठहराव प्रदान कर अपनी वाह-वाही और वोट की राजनीति बुनने में मशगूल रहे.

चुनावी समर को लेकर क़वायद तेज़

विजय खेमका, राम चरित्र यादव, रंजन सिंह, मोती लाल साह, सतीश साह, पप्पू सिंह, अनंत भारती, राज किशोर केसरी

नीरज कुमार सिंह

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी समर में कूदने के लिए पुराने चेहरे के अलावा कई नए उत्साही चेहरों के आ जाने से सियासी क़वायद तेज़ हो गई है. [illegible]

विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया सदर

[illegible] पूर्णिया के युवा वर्ग के कर्मठ नेता अनंत भारती. स्वच्छ छवि एवं समाज के हर वर्ग से जुड़े रहने के कारण समाज में विजय खेमका की अलग पहचान है. साथ ही प्रमंडल के सभी ज़िलों में भाजपा संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं में भी लोकप्रिय हैं. उनमें पार्टी लेवल के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की अदभूत क्षमता है, जिसे पार्टी के आम कार्यकर्ता सहजता से स्वीकारते हैं. विजय खेमका बताते हैं कि प्रदेश नेतृत्व का जो विचार होगा, उसपर अमल करूंगा, साथ ही पार्टी के पूरे प्रमंडल के उम्मीदवार का समर्थन करूंगा और तहेदिल से पूर्णिया प्रमंडल में कमल खिलाने के लिए काम करूंगा. तेज तर्रार युवा नेता अनंत भारती के बारे में पूर्णिया बुज़ुर्ग विकास मंच के अध्यक्ष का कहना है कि अनंत भारती एक सुलझे और विचारवान युवक हैं. अगर भाजपा से उन्हें टिकट मिलता है तो उनकी जीत सुनिश्चित है. पूर्णिया ज़िला महादलित विकास मंच के अध्यक्ष अशोक का कहना है कि अनंत भारती जैसे ईमानदार एवं स्वच्छ छवि के कर्मठ युवा को विधायक बनने का मौक़ा मिलना चाहिए. खुद भाजपा ज़िला मंत्री अनंत भारती का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर मुझे भरोसा है, जिसका पालन मैं सहर्ष करूंगा. समर्थन में युवाओं के साथ मैं जनसंपर्क करूंगा और पार्टी को मजबूत जनाधार के लिए कमल खिलाने का कार्य करूंगा, जिससे एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भाजपा में आमजनों का विश्वास निरंतर बढ़ सके. वैसे वर्त्तमान पूर्णिया सांसद उदय सिंह उर्फ़ पप्पू सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में काफी विकास किया है. अत: स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्णिया विधानसभा से वैसे प्रत्याशियों को जीत मिलेगी, जिनके साथ पप्पू सिंह का आशीर्वाद रहेगा.

> कांग्रेस से ही टिकट की दावेदारी मोतीलाल साह भी पेश कर रहे हैं. उनका कहना है कि मैं महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में आया. देश के प्रति कुछ करने का जज्बा के चलते चीन-भारत की लड़ाई के समय कुछ युवकों के साथ नाटक खेलकर 35 हज़ार रुपये जमा करके भारत सरकार के सुरक्षा कोष में दिया. उनके समर्थन में मनोज, विजय जैसे समर्थकों एवं स्थानीय जनता का कहना है कि मोतीलाल साह जैसे पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का टिकट एक बार अवश्य मिलना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

कुलपति की पहल रंग लाएगी

डॉ. अरविंद कुमार

> कुलपति डॉ. अरविंद कुमार इस विश्वविद्यालय को देश के शैक्षणिक मानचित्र पर सबसे ऊपर करने के संकल्प के साथ प्रभार ग्रहण किया था, लेकिन राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के नित्य नए-नए आदेश ने मगध विश्वविद्यालय के सारे कार्यों को प्रभावित कर दिया.

राज भवन और राज्य सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के बीच [illegible]

[illegible] आना होगा. अब देखने वाली बात यह होगी कि नए कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय विकास की ऊंचाइयों को छू पाता है या नहीं.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

बिना इंजन के दानापुर रेलमंडल

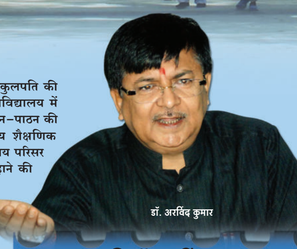

दानापुर रेलमंडल हीरक जयंती मनाने की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन आज भी इस मंडल के पास एक भी अपना इंजन नहीं है. नतीजा यह है कि मंडल के अधीन चलने वाली मेल एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों के साथ-साथ मालगाड़ियों का परिचालन दूसरे मंडल के इंजन की सहायता से किया जा रहा है. यह स्थिति कब तक बनी रहेगी, कहा नहीं जा सकता. बता दें कि रेल प्रशासन ने रेलवे के बढ़ते कामकाज संबंधी परेशानियों से निजात के लिए हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे जोनल कार्यालय का शुभारंभ 2000 में किया. इस जोन के अंतर्गत दानापुर मंडल, सोनपुर मंडल, मुगलसराय मंडल, समस्तीपुर मंडल, धनबाद मंडल शामिल हैं. हाजीपुर जोन में आय के क्षेत्र में धनबाद प्रथम तथा दानापुर दूसरे स्थान पर है. त्रासदी यह है कि इस जोन के धनबाद एवं मुगलसराय मंडल से आवागमन होने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन अपने इंजन के सहारे होता है, वहीं दानापुर मंडल से आवागमन होने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन दूसरे मंडल के इंजनों से किया जा रहा है. जबकि दानापुर रेल मंडल से राजस्व के तौर पर करोड़ों रुपये प्राप्त हो रहे हैं. इतना ही नहीं हाजीपुर जोनल कार्यालय बनने तथा जीएम, एजीएम आदि अधिकार का कार्यालय तथा चैंबर आदि तो बन गए हैं, लेकिन इस मंडल में रेलगाड़ियों के पार्ट्स सहित अन्य सामग्री का सप्लाई अभी भी प्राय: हावड़ा से ही हो रहा है. ग़ौरतलब है कि दानापुर रेलमंडल की स्थापना साल 1925 में किया गया. उस समय मुगलसराय मंडल भी दानापुर मंडल के अंतर्गत पड़ता था. साल 1978 में रेल प्रशासन ने रेलवे के बढ़ते लोड एवं विकास को देखते हुए मुगलसराय मंडल को अलग मंडल बनाया. आज दानापुर रेल मंडल से करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है. बावजूद इसके एक इंजन के लिए इसे दूसरे मंडल पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि आधा दर्जन से अधिक रेलमंत्री बिहार तथा दानापुर रेल मंडल के इर्द-गिर्द के बने. ज्ञात हो कि दानापुर रेलमंडल के अधीन चलने वाली क़रीब 180 मेल-एक्सप्रेस एवं 60 सवारी गाड़ी तथा सैकड़ों मालगाड़ियां हैं. इन ट्रेनों के परिचालन में लगी इंजन मुगलसराय एवं आसनसोल सहित अन्य मंडल के होते हैं. इतना ही नहीं पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर एवं दानापुर स्टेशनों से आवागमन होने वाली सभी ट्रेनों को चलाने के लिए भी इंजन दूसरे मंडल के होते हैं. इस मंडल से नए-नए रेल का परिचालन शुरू तो किया जा रहा है, लेकिन इनको चलाने के लिए इंजन की व्यवस्था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है. हां, रेलमंत्रियों ने अपने-अपने समय काल में शिलालेख पर नाम लिखवाने की होड़ ज़रूर लगाई. अपने इलाक़ों में सभी मंत्रियों ने वोट बैंक की राजनीति की है, जिसका शिलालेख आज भी गवाह के रूप में है. यह अलग बात है कि कुछ किए गए काम या लगाए गए मशीन आज कुव्यवस्था के शिकार हो गए हैं. सभी रेलमंत्रियों ने अपने-अपने इलाक़े स्थित स्टेशनों पर आरक्षण काउंटर, फुट ओवर ब्रीज, यात्री विश्रामालय, डिसप्ले बोर्ड सहित कई कार्य किए और कई की घोषणा भी रेलमंत्रियों ने कर रखी है. वहीं प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य किए जा रहे हैं. ये अलग है कि इस मंडल के अंतर्गत सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट का आलम व्याप्त है. कार्य की घोषणा तो की गई, लेकिन वह आज तक धरती पर नहीं पहुंची है. रेल प्रशासन ने पटना जंक्शन साहित इस मंडल के दर्ज़नों स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाने का फरमान जारी किया है. इस दिशा में कुछ स्टेशनों पर काम शुरू भी कर दिया गया. इतना ही नहीं आरएनसीसी पटना के हर्डिंग पार्क, दानापुर स्टेशन स्थित यार्ड में गाड़ियों के रखरखाव एवं जांच परख करने के लिए करोड़ों रुपये की लागत पर उपकरण लगाए गए हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

VAT No- 10493583094 ॐ 9939072343
श्री गणपति स्टोर्स
एन.एच. 31, राम मोहनी चौक, गुलाबबाग (पूर्णिया)
हमारे यहां साल पत्तल, थाली कप-प्लेट, कटोरी डिस्पोजल ग्लास, पेपर प्लेट, थर्मोकॉल थाली, मिठाई-डब्बा, नेपकिन इत्यादि बाजार से उचित मुल्य पर उपलब्ध है।

नेपाल से चल रहा अपराध का धंधा

बिहार सरकार अपराधियों को पकड़ने और ख़त्म करने का दावा अपने सुशासन में चाहे जितना कर ले, लेकिन हक़ीक़त कुछ और ही बयां करती है. वास्तविकता यह है कि शातिर अपराधी आज भी अपने ठिकानों को सुरक्षित रखते हुए मौक़ा पाते ही घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आते. इसका उदाहरण चंपारण की धरती बनी हुई है. बिहार पुलिस ने चंपारण में एक-दो बड़े दस्यु सरगनाओं को आत्मसमर्पण क्या कराया, मानो उनकी ड्यूटी पूरी हो गई. मगर, हालात यह है कि अब भी नामी गिरामी बड़े दस्यु सरगना अपने ठिकाने नेपाल के नवलपरासी ज़िला के हथुअनवा, सखुअनवा गांव में सुरक्षित करते हुए अपने चेलों और वंशजों से मौक़ा पाकर भारतीय सीमा में अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं. इसलिए अब भी चंपारण की धरती पर अपहरण की घटना जारी है. इन दस्यु सरगनाओं का नाता यहां होने वाले अपहरण, ख़ून-खराबा, गंडक दियारा में खेती करना, वाल्मीकि व्याध्र परियोजना से लकड़ी की तस्करी आदि से जुड़ा हुआ है. नेपाल की नागरिकता प्राप्त करके मुखिया या पहलवान कहवाकर मौज मस्ती की ज़िंदगी जीना इनका शौक बन गया है. इनसे अपराध करने का कारण पूछो, तो कहते हैं अपराधी हम नहीं अपराधी वह है, जिन्होंने उन्हें हथियार उठाने के लिए बाध्य किया है.

वैसे चंपारण में अपराध का इतिहास बहुत पुराना है. इतिहास के पन्ने में यह दर्ज़ है कि एक अंग्रेज़ पदाधिकारी ने चंपारण स्थित योगापटी को 13 अप्रैल 1911 को क्राइम ऑफ यूनिवर्सिटी की संज्ञा दी थी. 18 सितंबर 1917 को एसपी एस फलेजर की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार ने चंपारण को आगे चलकर ज़िला बनाया. 1970 में फिर से चंपारण अपराध की कहानी दोहराने लगा. योगापटी के अपराधी गामा के डर से चंपारण सिहरने लगा. वह 1974 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. उसी का शागिर्द मुस्लिम हुआ, जिसकी तूती चंपारण, गोपालगंज नेपाल के नवलपरासी, यूपी के पड़रौना, गोरखपुर तक बोलती रही. इसी बीच बासुदेव यादव, लक्ष्मण यादव, रूदल यादव अपराध की दुनिया में क़दम रखा. इन सभी के आतंक के कारण बिहार की कांग्रेस सरकार ने साल 1981 से लेकर 1984 तक ब्लैक पैंथर अभियान लागू किया. इस अभियान में एक डीआईजी, पांच एसपी, पंद्रह डीएसपी, एक सौ पचास दरोगा और चौदह कंपनी की फौज को शामिल किया गया. इस अभियान में छोटे-छोटे अपराधी पकड़े गए या मारे गए, लेकिन सभी बड़े अपराधी बच निकले. इसके बाद लोग यह समझ रहे थे कि अपराधी अब सिर नहीं उठाएंगे. क्योंकि सभी क्षेत्र छोड़कर भाग निकले. मगर, 1983 में मालूम हुआ कि ठकराहा में एक जाति विशेष की पंचायत के दौरान एक मुस्लिम मारा गया है. घटना ने लोगों को हतप्रभ करते हुए यह संदेश दिया कि अपराधी अभी भी इस क्षेत्र में सक्रिय है. ब्लैक पैंथर अभियान असफल साबित हो गया. अपराधियों का अपराध सिर चढ़कर फिर से बोलने लगा. अपराध इतना फैला कि चंपारण की बेटी, रोटी, खेती, सभी असुरक्षित हो गए. घर से बाहर जाने की गारंटी थी, लेकिन फिर घर लौटने की कोई गारंटी नहीं थी.

बासुदेव यादव, लक्षण यादव, सत्तन यादव का अपराध का तांड़व चंपारण में बोलने लगा. लक्षण यादव के घात में मारे जाने के बाद उसका भाई भागड़ यादव ने कमान संभाला. बासुदेव यादव और भागड़ यादव बिहार सरकार के समानांतर सरकार चलाने लगे और ये बिहार सरकार बोले जाने लगे. ये दुर्नामी अपराधी एक-एक भयंकर अपराध का अंजाम देने लगे और अपराध का कारनामा बढ़ता गया. राधा यादव भूअरवा नरसंहार 14 दिसंबर 1994 को हुआ. राजद सरकार के मुखिया लालू यादव को बगहा को पुलिस ज़िला घोषित करना पड़ा. फिर भी ये मुखिया से लेकर एमएलए और एमपी तक के चुनाव में हराने और जीताने का ठीका लेने लगे. इनके ही शागिर्द रूदल यादव, लालू यादव, रामभजु यादव, राधा यादव, रामचंद्र, रामचंद्र मल्लाह, ध्रुव मल्लाह, योगेंद्र कुशवाहा, अलाउदीन मियां, नेमा अहीर, व्यास दुबे, रामजतन नुनीया, ललन अहीर, टहलु यादव, ध्रुव यादव, आदि इनके छत्रछाया के नीचे रहकर पूरे चंपारण में अपहरण, ख़ून खराबा करते रहे और ये बैठकर संचालन करते रहे और फिरौती का पैसा वसूलते रहे. प्रारंभ में अपने सहमति पर लोगों को मुखिया और प्रमुख बनाए. भागड़ यादव ने अपने भाई सत्तन यादव को नौतन विधानसभा से विधायक और बेटा को ज़िला परिषद का अध्यक्ष तक बनवा डाला. बासुदेव यादव ने अपने बेटा को मुखिया और दामाद कन्हैया यादव को मधुबनी प्रखंड का प्रमुख बनाया. रामाधार को धनहा विधानसभा से चुनाव लड़ाया जिसमें राजेश सिंह मात्र तेरह सौ वोट से विधायक का चुनाव हार गया. सुशासन सरकार बनने के बाद लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आया. सरकार ने अपराधियों के लिए पुनर्वास योजना लागू किया. पारिवारिक दबाव बनने पर भागड़ यादव 8 मई 2008 को बेतिया पुलिस के सामने और बासुदेव यादव ने 24 मई 2008 को बगहा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, लेकिन हथियारों का समर्पण नहीं किया. कारण था कि अपने शागिर्द और इन हथियारों के बल पर अपने कुशासन को जारी रखना. इनके शागिर्दों में जहां रामभजू, लालू को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, वहीं इनके बहुत सारे शागिर्द नेपाल में रहकर अपने-अपने पुत्रों के बल पर दियारा से लेकर अजड़ी तक चंपारण के क्षेत्रों में कुशासन चला रहे हैं, जिससे अब भी अपहरण का सिलसिला जारी है. दो लाख के ईनामी अपराधी भागड़ यादव और बासुदेव यादव के चेला राधा यादव पर दो लाख, रामचंद्र मल्लाह पर 50 हज़ार, उमाशंकर कुशवाहा पर एक लाख, रूदल यादव पर पचास हज़ार का ईनाम बिहार सरकार ने घोषित कर रखा है. राधा पर 26 कांड, उमाशंकर पर 36, रामचंद्र मल्लाह पर 32, रूदल पर 25, मुरारी पर 12 बगहा पुलिस ज़िला के थानों में पुलिस ने कांड दर्ज़ कर रखा है. राधा यादव का भतीजा चुम्मन यादव, रूदल यादव, लालबाबू कुशवाहा के राजेंद्र चौधरी, किशोर राम का गिरोह गुरुओं, चाचाओं की संपत्ति की रखवाली के साथ-साथ अपराध की खेती करने में जुटे हुए हैं. एक दिसंबर 2006 के दिन पीपरासी दियारा में चार किसानों की हत्या अपने हुक्मरानों के आदेश पर जातिगत लड़ाई में कर डाला. पिछले दिसंबर से अगर इनके गतिविधि पर नज़र डाली जाए तो हर एक दो महीना के अंतराल पर वह एक वारदात कर डालते हैं. सात दिसंबर को भैरोगंज थाना के विसमरापुर गांव से एक रात में दो युवकों का अपहरण उस समय किया जब उनके घर के दरवाजे पर बारात आई थी. भैरोगंज थाना के मंझरिया गांव से एक शिक्षक के पुत्र और दामाद का अपहरण उस समय हुआ जब वे देर शाम अपने घर लौट रहे थे. पिछले 24 मार्च के दिन नवरात्र का मेला देखकर लौटनेवाले तीन व्यवसायिकों का एक साथ अपहरण हुआ, कुछ देर आगे जाकर एक को फिरौती का राशि लाने के लिए छोड़ दिया. सभी अपहरण में पुलिस छुड़ाने का दावा ठोकती रही, पर वास्तविकता यह रहा कि अपहरणकर्ता ने पैसा लेने के बाद ही उन्हें छोड़ा. 4 जून की रात को चौतरवा थाना के चंदरपुर बकवा गांव से किसान प्रभु यादव का हथियारबंद अपराधियों ने अपहरण कर लिया है. इस तरह अब भी ये पुलिस को चुनौती देते हुए घटना का अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं. चेलों और भतीजों को पकड़ने के लिए बगहा पुलिस अधीक्षक डॉ. सिद्धार्थ मोहन जैन के नेतृत्व में पुलिस तैयार बैठी है, लेकिन गुरुओं को पकड़ने के लिए पुलिस बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि नेपाल का मामला ठहरता है. पुलिस अधीक्षक बताते हैं कि शीर्षस्थ पदाधिकारियों को जानकारी दी गई है. दिशा-निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी.

रामचंद्र मल्लाह, भागड़ यादव, राधा यादव

प्रो. अरविंद नाथ तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

हूल दिवस के अवसर पर संदेश

सन् 1855 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसे संथाल परगना में हूल दिवस के नाम से जाना जाता है के पावन अवसर पर महान अमर शहीद सिद्दु-कान्हु एवं चाँद भैरव मुर्मू के पुण्य दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए सभी देश वासियों के प्रति साहेबगंज वन प्रमण्डल हार्दिक उदार व्यक्त करता है तथा इस प्रमण्डल द्वारा विगत वर्षों में जिले को हरा-भरा करने, वन एवं पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने तथा वृक्षारोपण के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का सफलता पूर्ण कार्य करता रहा है। कतिपय झलकियाँ सुस्पष्ट की जा रही है:-

- नरेगा के ही अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में कंटीला तार एवं बाँस घेरान कर 80 किलोमीटर पथ वृक्षारोपण का कर रू. 4,34,75,300/- की राशि खर्च कर 10,07,447 मानव दिवस का सृजन किया गया।
- नरेगा योजना के अन्तर्गत 100 हे. गैर मजरूआ नंगे पहाड़ों को पौधों से अच्छादित कर हरा-भरा किया गया और रू. 35,16,010/- तथा 500 हे. वन भूमि पर मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कर ग्राम वन प्रबन्धन एवं संरक्षण समिति की सहायता से न केवल वनों को सघन किया बल्कि उनको उन्नत किया गया साथ ही साथ 70,20,000/- खर्च कर 82,800 मानव दिवस का सृजन किया गया।
- कल्याण विभाग की योजना से भोगनाडीह में अमर शहीद के वंशजों के लिए घर बनाने का कार्य तथा पुस्तैनी घर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही एक संग्रहालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिसमें हूल आन्दोलन तथा संथाल कला एवं संस्कृति से संबन्धित अवशेषों एवं प्रतिदर्शों का संकलन तथा प्रदर्शन किया जायेगा।
- डी.पी.ए.पी. योजना अन्तर्गत जिले के दो प्रखण्ड-तालझारी एवं पतना में 500 एकड़ रैयती भूमि के पटवन हेतु दो तालाब का निर्माण 8,85,000/- रूपये खर्च कर 3852 मानव दिवस सृजित किया गया
- वन विकास अभिकरण के तहत 300 हे. वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य जिले के विभिन्न प्रखण्डों में 18,32,200/- कुल 1122 मानव दिवस सृजित किया गया है।

वन प्रमण्ड पदाधिकारी
साहिबगंज वन प्रमंडल, साहिबगंज

भोजपुरिया माटी की खुशबू भाने लगी है. तभी तो वह भोजपुरी फिल्मों में ही काम करना चाहती हैं. अपनी इस ख्वाहिश को प्रीति ने एक भोजपुरी फिल्म की लांचिंग पार्टी में जाहिर किया.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

झारखंड पर मंडराता रेडिएशन का ख़तरा

झारखंड में रेडिएशन का ख़तरा मंडरा रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार लापरवाह बनी हुई है. यह ख़तरा जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्सर्जित कचरे से नहीं, बल्कि रामगढ़ ज़िले में स्थित रजरप्पा कोल वाशरी से वर्ष 2007 में गायब हुए ऐश एनलाइजर से बना हुआ है. वैज्ञानिकों के मुताबिक़ रेडिएशन के प्रमुख कारक माने जाने वाले एक तत्व कोबाल्ट-60 से भी अधिक ख़तरनाक ऐश एनलाइजर है. इसे कोयला की छाई की मात्रा को मापने के लिए मंगाया गया था, जिसमें एक्टिव यूरेनियम है, कोबाल्ट-60 की तरह ही ऐश एनलाइजर से ख़तरनाक गामा किरणें निकलती हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक़ ऐश एनलाइजर का एक्टिव रेडियोयुक्त पदार्थ अगर वातावरण के संपर्क में आया तो भीषण तबाही मच सकती है और यह मानव जीवन के लिए ख़तरा बन सकता है. ऐश एनलाइजर से निकलने वाली गामा किरणों की ऊर्जा तीन मिलियन इलेक्ट्रोन बोल्ट के बराबर है.

मालूम हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से गायब हुए कोबाल्ट-60 मायापुरी इलाक़े के कबाड़ी बाज़ार में पहुंच जाने के बाद रेडिएशन से मायापुरी इलाक़े में जानमाल की क्षति हुई. केंद्र सरकार द्वारा इस मामले की एक उच्चस्तरीय जांच जारी है. वहीं दूसरी ओर सीसीएल के रामगढ़ ज़िला स्थित रजरप्पा कोल वाशरी से वर्ष 2007 में गायब ऐश एनलाइजर कोबाल्ट-60 से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन व झारखंड सरकार रेडियो एक्टिव पदार्थयुक्त ऐश एनलाइजर को पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिससे मायापुरी दिल्ली की तरह झारखंड पर भी रेडिएशन का गंभीर ख़तरा मंडरा रहा है. ग़ौरतलब है कि कोल इंडिया ने कोयले में छाई की मात्रा मापने के लिए भाभा परमाणु केंद्र, मुंबई से क़रीब दो करोड़ रुपए की लागत से ऐश एनलाइजर उपकरण मंगवाया था, जिसे रामगढ़ ज़िले के रजरप्पा स्थित कोयला वाशरी के स्टोर में बिना किसी सुरक्षा-व्यवस्था के रखा गया था. बाद में स्टोर से रेडियो एक्टिव पदार्थयुक्त ऐश एनलाइजर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया. इसके काफी दिनों बाद एक सुरक्षा गार्ड ने स्टोर का ताला टूटने की सूचना अधिकारियों को दी. जांच करने पर स्टोर से रेडियो एक्टिव ऐश एनलाइजर गायब था. बाद में एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी देव नारायण प्रजापति से प्रबंधन ने स्थानीय रजरप्पा थाने में इस बाबत प्राथमिकी दर्ज कराई. रेडियो एक्टिव ऐश एनलाइजर के चोरी की ख़बर जब मीडिया में आई तो प्रदेश में खलबली मच गई. तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विधानसभा में घोषणा की कि झारखंड के लोगों को रेडिएशन के संभावित ख़तरे से बचाने के लिए सरकार ठोस क़दम उठाएगी और सीसीएल पर लापरवाही बरतने के लिए मामला दर्ज करेगी, लेकिन यह मामला अब ठंडे बस्ते में जा चुका है.

दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से गायब हुए कोबाल्ट-60 मायापुरी इलाक़े के कबाड़ी बाज़ार में पहुंच जाने के बाद रेडिएशन से मायापुरी इलाक़े में जानमाल की क्षति हुई. केंद्र सरकार द्वारा इस मामले की एक उच्चस्तरीय जांच जारी है. वहीं दूसरी ओर सीसीएल के रामगढ़ ज़िला स्थित रजरप्पा कोल वाशरी से वर्ष 2007 में गायब ऐश एनलाइजर कोबाल्ट-60 से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन व झारखंड सरकार रेडियो एक्टिव पदार्थयुक्त ऐश एनलाइजर को पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिससे मायापुरी दिल्ली की तरह झारखंड पर भी रेडिएशन का गंभीर ख़तरा मंडरा रहा है.

हालांकि सीसीएल प्रबंधन द्वारा इस दिशा में पहल करने के बाद भाभा परमाणु केंद्र, मुंबई से विशेषज्ञों का एक दल रजरप्पा पहुंचा तथा एक खास उपकरण के जरिए ऐश एनलाइजर का पता लगाने की कई दिनों तक कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिली. इधर, स्थानीय पुलिस आसपास के कबाड़ी की दुकानों तथा स्क्रैप डीलरों के यहां छापामारी करती रही, लेकिन रेडियो एक्टिव ऐश एनलाइजर का पता नहीं चल सका. जानकारों का मानना है कि कोल फील्ड एरिया के डेटोनेटर और विस्फोटक पदार्थों पर उग्रवादी संगठनों की पैनी नज़र रहती है. कोयला खदान क्षेत्रों में स्थित बारूद घरों से अक्सर डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्रियां गायब होती रहती हैं. कई बार इस बात का खुलासा हुआ है कि नक्सली संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक पदार्थ सीसीएल की खदानों से गायब किए गए हैं. दरअसल सुरक्षा व्यवस्था में घोर लापरवाही बरते जाने के कारण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. ऐश एनलाइजर का गायब होना भी इसकी कड़ी से जोड़ कर देखा जा सकता है. सुरक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामी के बारे में राज्य और केंद्र सरकार भी अनजान नही हैं. दिल्ली में गायब हुए कोबाल्ट-60 जब एक स्क्रैप डीलर के पास पहुंचा. जब स्क्रैप डीलर ने कंटेनर खोला तो इसके साथ ही कोबाल्ट-60 से रेडिएशन शुरू हो गया. नतीजा जगजाहिर है. झारखंड के लोगों को भी आशंका है कि कहीं दिल्ली की तरह ही किसी ने अज्ञानतावश अब तक गायब ऐश एनलाइजर के कंटेनर को खोलने की गलती की तो झारखंड में भी रेडिएशन से तबाही मच सकती है.

रजरप्पा थाने में इससे संबंधित एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस ने इतने संवेदनशील व ख़तरनाक रेडियो एक्टिव यंत्र के गायब होने की फाइल को बंद कर दिया, जिससे झारखंड और उसके सीमावर्ती राज्यों में ऐश एनलाइजर के रेडिएशन का ख़तरा बरक़रार है. मायापुरी दिल्ली की तबाही से भी झारखंड सरकार ने कोई सीख नहीं ली. सरकार व प्रशासन की नींद शायद तब खुलेगी जब मायापुरी दिल्ली की तरह ही झारखंड में भी रेडिएशन से तबाही शुरू हो जाएगी और तब बचाव का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा.

नन्द किशोर अग्रवाल
feedback@chauthiduniya.com

सिंधी के बाद भोजपुरी की बारी

भोजपुरी इंडस्ट्री की सफलता से क्षेत्रीय और असफल कलाकारों को रोज़गार तो मिला ही. साथ ही साथ इसका सबसे ज़्यादा फायदा रीजनल सिनेमा को हुआ है. भोजुपरी फ़िल्मों के साथ-साथ कई और डूबते रीजनल सिनेमा मसलन मैथिली, सिंधी, हिमाचली और मणिपुरी सिनेमा को नई जान मिल गई. इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि अब यहां की फ़िल्मों में भी बड़े-बड़े सितारे काम करने को राजी हो रहे हैं. एक तरफ जहां कई हीरोइनें हॉलीवुड का रुख़ कर रही हैं, वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झिंगयानी, जो तमिल, तेलगू, पंजाबी फ़िल्मों में काम करने के बाद सिंधी फिल्मों में काम कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सिंधी फ़िल्म प्यार करे दिस में काम किया है. लगभग पांच साल बाद सिधी फ़िल्म का निर्माण हुआ है. राजश्री के एलबम से ग्लैमर जगत में आने वाली प्रीति ने यश चोपड़ा की फ़िल्म मोहब्बतें से अपनी फ़िल्मी पारी शुरू की थी. हिंदी फ़िल्मों के बाद उन्होंने कई रीजनल फ़िल्मों में काम किया. सिंधी के बाद अब उन्हें भोजपुरिया माटी की खुशबू भाने लगी है. तभी तो वह भोजपुरी फ़िल्मों में ही काम करना चाहती हैं. अपनी इस ख्वाहिश को प्रीति ने एक भोजपुरी फ़िल्म की लांचिंग पार्टी में जाहिर किया. उनके मुताबिक़ मुझे भोजपुरी नहीं आती पर अब मैं भोजपुरी भाषा सीखने के लिए स्पेशल क्लास ले रही हूं. साथ ही भोजपुरी में डायलाग्स बोलने का लहज़ा भी सीख रही हूं. वीडियो एलबम से अपनी पारी शुरू करने वाली प्रीति के हौसले बुलंद हैं. उनका कहना है कि सिंधी और भोजपुरी दोनों ही भाषाओं में मिठास है. सिंधी फ़िल्मों की मिठास तो वह चख चुकी हैं अब भोजपुरी की बारी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रीति ने यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें से अपनी फ़िल्मी पारी शुरू की थी. हिंदी फ़िल्मों के बाद उन्होंने कई रीजनल फ़िल्मों में काम किया. सिंधी के बाद अब उन्हें भोजपुरिया माटी की खुशबू भाने लगी है.